राष्ट्रीय संस्करण

ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकार किए गए कम
>> 11

वर्ष 9 अंक 342

दैनिक जागरण

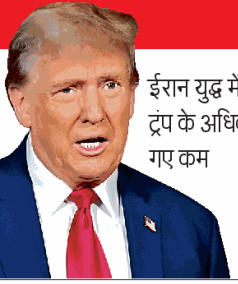

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 21 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदले भारत-इटली संबंध

इटली की प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, वैश्विक व द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा | यूएई और चार यूरोपीय देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं पीएम मोदी | इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने मोदी के लिए किया रात्रिभोज का आयोजन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत और इटली ने आपसी संबंधों को और मजबूत करते हुए इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। अभी तक इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा ही हासिल था। रोम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी की बैठक में यह फैसला किया गया। दोनों नेताओं ने भारत-इटली साझेदारी के संपूर्ण आयामों पर विस्तृत चर्चा की और आपसी संबंधों को दिशा देने के लिए वर्ष 2025-29 की कार्ययोजना की समीक्षा की। बुधवार की बैठक में इस कार्ययोजना की बेहतर निगरानी के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अगुआई में एक स्थायी व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद आपसी कारोबार बढ़ाने के लिए सतत कोशिश करते हुए द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 20 अरब यूरो करने पर भी सहमति बनी है।

प्रधानमंत्री मोदी यूएई और चार यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मेलोनी ने इंटरनेट मीडिया पर 'वेलकम टू रोम, माइ फ्रेंड' लिखकर उनका स्वागत किया। बुधवार को दोनों नेताओं की अगुआई में द्विपक्षीय बैठक हुई। इसके बाद संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में मोदी ने कहा, 'आज की बैठक में हमने भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की। भारत-इटली संयुक्त कार्य योजना 2025-29 इस साझेदारी को एक व्यावहारिक व भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करती है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।' मोदी और मेलोनी में भारत-ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। मेलोनी ने कहा कि, 'भारत-इटली के संबंध अब एक निर्णायक चरण में पहुंच गए हैं। हाल के वर्षों में हमारे संबंध अभूतपूर्व गति से विस्तारित हुए हैं, जो सौहार्दपूर्ण मित्रता से आगे बढ़कर विशेष रणनीतिक साझेदारी तक विकसित हो गए हैं। यह साझेदारी स्वतंत्रता, लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य की साझा दृष्टि पर आधारित है।'

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत-इटली ने आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने का फैसला किया है। मोदी ने कहा, 'भारत-इटली एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत-इटली ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करते, बल्कि उसके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम उठाते हैं। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान वार्ता व कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।'

द्विपक्षीय वार्ता से पहले मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। मोदी ने एक पोस्ट में बताया, "रोम पहुंचने पर मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रिभोज पर मिलने का मौका मिला, जिसके बाद हमने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए।" कोलोसियम रोम के बीचों-बीच स्थित एक अंडाकार एम्फीथिएटर (रंगभूमि) है। यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा व प्राचीन एम्फीथिएटर है।

रोम में बुधवार को अपनी इतालवी समकक्ष जार्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टाफी का पैकेट देते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएनआइ

मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट की 'मेलोडी' टाफी

मोदी ने इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी को बुधवार को एक अनोखा तोहफा दिया, 'मेलोडी' की टाफी का पैकेट। इस पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए मेलोनी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक उपहार लाए हैं- एक बहुत-बहुत अच्छी टाफी- मेलोडी।" इस दौरान दोनों नेताओं को बातचीत करते हुए हंसते-मुस्कुराते देखा गया। मेलोनी ने कैप्शन में लिखा, "इस उपहार के लिए धन्यवाद।" कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और 10 करोड़ से अधिक लोग इसे देख चुके थे। जबकि एक्स पर 74 लाख लोगों ने इसे देखा। गौरतलब है कि 'मेलोडी' मेलोनी और मोदी के नामों को मिलाकर बना संयुक्त शब्द है। यह शब्द असल में पहली बार तब वायरल हुआ था, जब मेलोनी ने 2023 में दुबई में आयोजित काप-28 शिखर सम्मेलन के दौरान एक्स पर एक सेल्फी पोस्ट की थी। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "कोप-28 में अच्छे दोस्त, मेलोडी।"

चार यूरोपीय देशों के साथ बढ़ा संबंधों का दर्जा

पीएम मोदी की चार यूरोपीय देशों की यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि हर देश के साथ मौजूदा संबंधों का दर्जा बढ़ाया गया। यह लंबे अरसे बाद उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र में भारत के शीर्ष नेतृत्व की एक साथ की गई लंबी यात्रा है। नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटली जैसे देश बदलते वैश्विक माहौल में नए साझेदार की तलाश में है। अभी तक इन देशों के संबंध अमेरिका से बेहद गहरे थे, लेकिन उसकी कई नीतियों से ये बेहद नाखुश हैं।

एक देश एक चुनाव से बचेंगे सात लाख करोड़ रुपये

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी का दावा, देश की जीडीपी में हो सकेगी 1.6 प्रतिशत की वृद्धि
- कहा-शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है इस धन का उपयोग

देश की पाई-पाई बचाने के सोच के बीच 'एक देश एक चुनाव' पर विचार के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सात लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस धन का उपयोग बुनियादी ढांचे, गरीबों का कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बुधवार को गांधीनगर में संयुक्त संसदीय समिति से मुलाकात की और 'एक देश एक चुनाव' का समर्थन किया। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे सत्ता के केंद्रीकरण का छिपा हुआ एजेंडा बताया।

प्रेट्र के अनुसार, संसदीय समिति ने मंगलवार को गुजरात के मुख्य सचिव एमके दास, विभिन्न विभागों के सचिवों और सत्तारूढ़ भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद पीपी चौधरी ने पत्रकारों को बताया था कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिन पर पहले विचार नहीं किया गया था। हमने उन्हें एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। आम चुनाव व विधानसभा चुनाव बार-बार होने से विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। मंत्रियों और अधिकारियों को चुनावी काम में जाना पड़ता है।

एक देश एक चुनाव योजना। फाइल

गांधीनगर से जागरण संवाददाता के अनुसार, चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने समिति के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि उनके राज्य का 43 प्रतिशत राजस्व पर्यटन से आता है। चुनावी वर्ष में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

दो प्रस्तावित कानूनों की जांच कर रही समिति पेज>>3

जागरण विशेष

अब कोई भी करा सकेगा सड़क की गुणवत्ता की जांच

नोएडा: अब कोई भी व्यक्ति सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता की जांच करा सकेगा। यह सुनिश्चित होगा कि सैंपल भेजने वाले की गोपनीयता बनी रहे। • पेज-7

संपादकीय

विकृत सोच से उपजा सनातन विरोध: यह विडंबना ही है कि जो सनातन परंपरा अपने मूल में सर्वाधिक सहिष्णु, उदार और समावेशी है, उसी पर सर्वाधिक प्रहार किया जाता है। **निरंजन कुमार** का दृष्टिकोण।

आसान होती अच्छी शिक्षा तक पहुंच: विदेशी शिक्षण संस्थानों का आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि भारतीय छात्रों को नए विकल्प देता है। **प्रमथ राज सिन्हा** का आलेख। • पेज-8

विमर्श

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था: प्रतियोगी परीक्षाएं केवल चयन की प्रक्रिया नहीं हैं, युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़ी हैं। **प्रो. श्रीप्रकाश सिंह** का विश्लेषण।

कानून एवं व्यवस्था की मिसाल: योगी सरकार ने 'जीरो टालरेंस' व 'माफिया को मिट्टी में मिला देंगे' जैसी बातों को कार्रवाई के जरिये धरातल पर उतारने का माडल पेश किया है। **विक्रम सिंह** का आलेख। • पेज-9

पेट्रोल में 30 प्रतिशत एथनाल मिलाने का रास्ता साफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ऊर्जा संकट के दौर में भारतीय मानक ब्यूरो ने जारी किए मानक
- विशेषज्ञ बोले, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एथनाल बहुत जरूरी

निर्धारित समय से काफी पहले पूरे देश में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल (ई-20) की बिक्री का लक्ष्य हासिल करने के बाद सरकार अब 30 प्रतिशत एथनाल मिश्रित ईंधन की तरफ बढ़ती दिख रही है। सरकारी एजेंसी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने पेट्रोल में उच्च स्तर के एथनाल मिश्रण के लिए नए ईंधन मानक जारी कर दिए हैं। इनमें ई-22, ई-25, ई-27 और ई-30 (यानी 22 से 30 प्रतिशत तक एथनाल मिश्रण) ईंधन के मानक तय किए गए हैं। बीआइएस ने उक्त मिश्रण वाले ईंधन की तकनीकी विशिष्टताएं, सैंपलिंग और टेस्टिंग के तरीके निर्धारित किए हैं। इससे पेट्रोल पंपों पर इन ईंधनों को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा, जैसे ई-22 पेट्रोल, ई-25 पेट्रोल आदि। स्पष्ट कर दें कि अभी सरकार ने पूरे देश में ई-20 ईंधन की बिक्री अनिवार्य नहीं की है।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार की तरफ से देश में एथनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री में और तेजी लाई जा रही है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है और अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल का आयात बिल करीब 123 अरब डालर रहा, जबकि पश्चिम एशिया संकट से कीमतें बढ़ने का खतरा बना हुआ है। भारतीय रुपये में गिरावट और महंगाई बढ़ने के लिए इसे जिम्मेदार माना जा रहा है।

ई-20 की बिक्री से बचे 1.44 लाख करोड़ : ई-20 मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने से 2014 से अब तक लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कच्चे तेल के आयात में करीब 245 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। यही वजह है कि सरकार इसे और बढ़ावा देने में जुटी है।

ब्राजील से सीख सकते हैं सबक

एथनाल से जुड़े विषय पर देश के प्रसिद्ध विशेषज्ञ एवं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस प्रेसीडेंट व प्रमुख (भारत) विक्रम गुलाटी ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, 'हमने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रण में जितनी तेजी से सफलता हासिल की है, उससे यह उम्मीद बनती है कि ई-30 की बिक्री शुरू होने के बाद हम तेजी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे।' उन्होंने ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ई-27 फार्मूला लागू है, लेकिन औसतन 50-55 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री हो रही है। ब्राजील में 95 प्रतिशत तक ऐसे वाहन हैं जो 100 प्रतिशत एथनाल से चल सकते हैं। हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए।

सस्ता होना चाहिए एथनाल मिश्रित पेट्रोल

गुलाटी ने कहा कि हमें ब्राजील की तरह ही एथनाल मिश्रित ईंधन को सामान्य पेट्रोल से सस्ता करने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां मिश्रित पेट्रोल 30 प्रतिशत तक सस्ता होता है। वहां मिश्रित पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट मिलती है।

छह दशक बाद कांग्रेस बनेगी तमिलनाडु सरकार का हिस्सा

नई दिल्ली: तमिलनाडु विस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा हो, पर छह दशक बाद पार्टी राज्य सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। कांग्रेस ने बहुमत से पीछे रहे विजय के सीएम बनने में अहम भूमिका निभाई। (पेज-4)

बंगाल में 'पुशबैक' कानून लागू, शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को करेगी डिपोर्ट

कोलकाता : बंगाल के सीएम शुभेंदु सरकार ने बुधवार को नवान्न (सचिवालय) में बीएसएफ के अफसरों के साथ बैठक के बाद राज्य में 'पुशबैक' कानून तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा कर दी। इसके तहत अब घुसपैठियों को पुलिस गिरफ्तार कर बीएसएफ के हवाले करेगी, जिसके बाद उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट (निर्वासित) किया जाएगा। (पेज-6)

अगले माह फ्रांस में मोदी-ट्रंप की बैठक संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फ्रांस में 15 से 17 जून तक होनी है जी-7 प्रमुखों की बैठक
- शनिवार को भारत आ रहे रूबियो, तय होगा वार्ता का एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बैठक अगले महीने फ्रांस में हो सकती है। फ्रांस में 15 से 17 जून तक जी-7 के प्रमुखों की बैठक है। फ्रांस पहले ही मोदी को आमंत्रित कर चुका है और पिछले वर्षों की तरफ इसमें पीएम के हिस्सा लेने की पूरी तैयारी है।

ट्रंप भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 23 से 26 मई तक की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों नेताओं के बीच बैठक का एजेंडा तैयार करना है। मोदी-ट्रंप की पिछली मुलाकात फरवरी, 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। उसके बाद भारत-अमेरिका संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं।

ट्रंप-मोदी के बीच इसके पहले भी जी-7 में मुलाकातें होती रही हैं। पिछले वर्ष भी मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने कनाडा गए थे, लेकिन ट्रंप पहले ही वहां से रवाना हो गए थे। लिहाजा दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद से ट्रंप ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने संबंधों को असहज कर दिया। खासकर भारतीय आयात पर टैक्स, रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंध और पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने की उनकी नीतियों का उलटा असर हुआ। लंबी वार्ता के बावजूद भारत-अमेरिका में अभी तक द्विपक्षीय कारोबारी समझौता नहीं हो पाया है।

ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे रूबियो

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान वह कोलकाता, आगरा, जयपुर व नई दिल्ली भी जाएंगे। रूबियो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करेंगे। इस दौरान उनकी नई दिल्ली में 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की संभावित बैठक में हिस्सा लेने की भी संभावना है। इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई जानकारी नहीं दी है और न ही अमेरिकी विदेश विभाग ने कुछ कहा है।

मार्को रूबियो।

वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे पीएम मोदी : शरद पवार

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

- देश के सम्मान के मामले में राजनीतिक मतभेद बीच में नहीं लाना चाहिए

राकांपा (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि भले ही वह नरेन्द्र मोदी से राजनीतिक रूप से असहमत हों, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने पवार से असहमति जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देना चाहिए।

मंगलवार शाम एक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया कि जब भी राष्ट्रीय हित के लिए सामूहिक रूप से काम करने का मौका मिले, तो सभी को एक साझा उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव एवं मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने हमेशा देश के भविष्य और प्रतिष्ठा को अपने नेतृत्व के केंद्र में रखा। पवार ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के मामले में राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश के सम्मान की बात आती है, तो राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाना चाहिए। यदि राष्ट्रहित में सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर मिले, तो आप सभी को एक साझा उद्देश्य के साथ देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान देना चाहिए।

शरद पवार। फाइल

राउत ने जताई असहमति, कहा- प्रधानमंत्री को देने चाहिए सवालों के जवाब

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने पवार से असहमति जाहिर की। पवार द्वारा मोदी का समर्थन करने संबंधी सवाल के जवाब में राउत ने कहा कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देना चाहिए। राउत ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जब भी विदेश जाते थे, प्रेस से बात करते थे।

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

गुजरात टाइटंस vs चेन्नई सुपर किंग्स

शाम 7:30 बजे स्थान: अहमदाबाद

प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

हड़ताल पर रहे अधिवक्ता, जुर्माना लगा पक्षकारों पर पेज>>2

टेट्रा पैक व सैशे में शराब की बिक्री का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेज>>7

नई पहल

एनएचएआइ ने कराई संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग, 16 हजार किमी पर है अधिक जोखिम, नेशनल हाईवे पर 70 प्रतिशत हादसों वाले 278 स्थानों पर जल्द पहुंचेगी एंबुलेंस

नेशनल हाईवे पर जल्द मिलेगी मदद, 10 मिनट में पहुंचेगी एंबुलेंस

जितेंद्र शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : सड़क दुर्घटनाओं के बाद गोल्डन आवर यानी कि एक घंटे के भीतर उपचार न मिलने के कारण हर साल 50 से 75 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने नेशनल हाईवे के उन 278 अति संवेदनशील स्थानों पर दस मिनट के भीतर एंबुलेंस पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया है, जहां लगभग 70 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दावा है कि यहां एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम ठीक करने के बाद एनएचएआइ बाकी क्षेत्रों पर भी उसी तर्ज पर काम करेगा ताकि गोल्डन आवर में ही गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बच सके।

नेशनल हाईवे के जिस हिस्से पर तीन वर्ष में पांच या उससे अधिक सड़क हादसे हुए हों, उसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ब्लैक स्पाट के रूप में चिह्नित करता है। इस आधार पर 80 हजार किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्तमान में 13 हजार से अधिक ब्लैक स्पाट हैं। इन्हें सुधारने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय लगातार चलते रहते हैं। वहीं, एनएचएआइ ने पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क की मैपिंग करवाकर उन बिंदुओं को चिह्नित किया है, जो सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

80 हजार किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे में से 20% हिस्से पर ही होते हैं अधिक हादसे

18 राज्यों के 100 जिलों में हैं हादसे वाले यह अति संवेदनशील करीब पौने तीन सौ स्थान

19 सर्वाधिक जिले महाराष्ट्र के, 18 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल।

प्रतीकात्मक

प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष यादव के मुताबिक, 80 हजार किमी का 20 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 16 हजार किमी के दायरे में 278 ऐसे स्थान हैं, जहां 70 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं। विडंबना यह है कि इन स्थानों पर एंबुलेंस पहुंचने में 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं, जबकि एंबुलेंस पहुंचने का सामान्यतः औसत समय 15 मिनट होता है। अब एनएचएआइ ने योजना बनाई है कि सबसे पहले इन अति संवेदनशील स्थानों पर एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम घटाकर 10 मिनट पर लाया जाए। इसकी रीयल टाइम मानीटरिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जिस तरह एप आधारित कैब का मूवमेंट देखा जा सकता है, वैसे ही यात्री देख सकेंगे कि एंबुलेंस कहां तक पहुंच गई। इस व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां भी देख सकेंगी कि दुर्घटना स्थल के सबसे करीब कौन सी एंबुलेंस है।

300 किमी दूर दुश्मन के लक्ष्यों का नाश करेगा सूर्यास्त्र

जागरण संवाददाता, बालेश्वर

- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी छलांग लगाते हुए देश ने किया सूर्यास्त्र राकेट का परीक्षण

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में निजी क्षेत्र की प्रमुख रक्षा कंपनी नीबे लिमिटेड ने लंबी दूरी के 'सूर्यास्त्र' राकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय सेना की ओर से कंपनी को दिए गए खरीद आर्डर के तहत किया गया है। 18 और 19 मई को हुए इन परीक्षणों में 150 और 300 किमी मारक क्षमता वाले राकेटों ने लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर अपनी क्षमता साबित की।

कंपनी के अनुसार, 150 किमी रेंज वाले राकेट ने 1.5 मीटर की सर्कुलर एरर प्राबेबिलिटी (सीईपी) हासिल की, जबकि 300 किमी रेंज वाले संस्करण ने दो मीटर सीईपी दर्ज की।

बता दें कि सीईपी किसी भी राकेट या मिसाइल प्रणाली की सटीकता का प्रमुख मानक होता है, जो लक्ष्य के आसपास गिरने वाले दायरे को दर्शाता है। इतनी कम सीईपी इस प्रणाली की सटीक मारक क्षमता को दर्शाती है।

इजरायल की पल्स तकनीक का भारतीय संस्करण है सूर्यास्त्र पेज>>3

20 मई मध्य रात्रि से आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआइएमटीसी) के आह्वान पर व्यावसायिक वाहनों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है, जिसका वास्तविक असर गुरुवार से दिखाई देगा। दावा है कि इस अवधि में दूसरे राज्यों से व्यावसायिक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे।

आज का मौसम

बृहस्पतिवार को आसमान साफ रहेगा। ज्यादातर जगह लू चलेगी। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने की भी संभावना है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
21 मई	46.0	28.0
22 मई	46.0	28.0
नोएडा		
21 मई	44.0	28.0
22 मई	43.0	28.0
गुरुग्राम		
21 मई	44.0	20.0
22 मई	45.0	30.0

डिग्री सेल्सियस में

सरकार में पहली बार हुआ वर्क फ्राम होम

मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट और मुख्य सचिव ने घर से किया काम

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

प्रधानमंत्री की वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरा देश, मेरा योगदान अभियान के तहत दिल्ली सरकार में बुधवार को वर्क फ्राम होम रहा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने घर से काम किया। सीएम रेखा गुप्ता और सरकार के सभी मंत्री और मुख्य सचिव भी सचिवालय नहीं आए, सभी ने घर से काम किया।

बुधवार को किए गए पहले वर्क फ्राम होम का असर सचिवालय में दिखाई दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने घर से काम किया और दिन में बैठकें आनलाइन कीं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता अपने घर से की। वर्क फ्राम होम के चलते सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या काफी कम थी। सीएम कार्यालय, मंत्रियों का स्टाफ और मुख्य सचिव की यूनिट में भी कर्मचारी न के बराबर थे। लोक निर्माण विभाग, होम, वित्त, योजना विभाग में अधिकारी कार्यालय नहीं आए,

मेरा देश मेरा योगदान अभियान के तहत वर्क फ्राम होम के कारण दिल्ली सचिवालय के बाहर पार्किंग में कम गाड़ियां दिखीं। जागरण

उन्होंने अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपने घर से काम किया। सरकार की ओर से भी केवल जरूरी सेवाओं से संबंधित विभागों के कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों को सरकार की ओर से अपने घर पर से काम करने की सलाह दी गई थी। वर्क फ्राम होम का असर दिल्ली सचिवालय के बाहर भी दिखाई दिया, जहां ओपन पार्किंग में प्रतिदिन पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी वहां बुधवार को लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए आसानी से जगह मिल जा रही थी। कोरोना महामारी को छोड़ दें तो सरकार का यह पहला प्रयोग था और पहली बार सरकार में कोई वर्क फ्राम होम किया गया। 10 मंजिला दिल्ली सचिवालय में विभिन्न मंत्रालयों, प्रशासनिक विभागों और मंत्री कार्यालयों के अंतर्गत लगभग 4,000 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। इस संख्या में आईएएस अधिकारियों से लेकर क्लर्क, सुरक्षाकर्मी, और प्रशासनिक कर्मचारी तक शामिल हैं।

सड़कों पर रोशनी व्यवस्था सुधारने को खर्च होंगे 473 करोड़

मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की अध्यक्षता करती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौजन्य : दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

राजधानी में कई सड़कों पर रोशनी की कमी, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत में देरी और डार्क स्पाट की समस्या बनी हुई है। रोशनी न होने से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल स्मार्ट एलईडी प्रणाली में बदलने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। लगभग 473.24 करोड़ रुपये खर्च कर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सड़कों पर करीब 96 हजार स्ट्रीट लाइटों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। दीवाली तक दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर 51,160 बिजली के खंभों पर लगभग 45 हजार पुरानी एचपीएसवी (हाई प्रेशर सोडियम वेपर) लाइटें और 51 हजार एचपीएसवी एलईडी लाइटें लगी हुई हैं। वर्तमान व्यवस्था में कई समस्याएं आ रही थीं।

दिल्ली में मुंगेशपुर का तापमान रहा 46.3 डिग्री, कई जगह चली लू

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

▸ चार इलाके मुंगेशपुर, आयानगर, रिज और लोधी रोड रहे लू से प्रभावित

भीषण गर्मी की चपेट में चल रही राजधानी में बुधवार को भी गर्मी के तेवर खासे तल्ख रहे। आरेंज अलर्ट के बीच साफ आसमान, तीखी धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से सभी का हाल बेहाल रहा। हालांकि तापमान में एक दिन पहले के मुकाबले आंशिक कमी देखने को मिली, लेकिन उससे राहत कोई नहीं मिली। लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली के अनेक इलाकों में लू चली। मौसम विभाग ने 26 मई तक यानी अगले छह दिनों के लिए आरेंज अलर्ट भी पहले से जारी किया हुआ है।

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 48 से 11 प्रतिशत रिकार्ड हुआ। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री के लिहाज से मुंगेशपुर और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.9 डिग्री की दृष्टि से राजघाट राजधानी के सबसे गर्म इलाके रहे। चार इलाके मुंगेशपुर, आयानगर, रिज और लोधी रोड लू से प्रभावित रहे।

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर-पश्चिमी हवाएं राजस्थान के थार रेगिस्तान और मध्य पाकिस्तान के हिस्सों से राष्ट्रीय राजधानी की ओर आ रही हैं। शुष्क क्षेत्रों से गुजरते हुए, ये हवाएं दिल्ली पहुंचते-पहुंचते और शुष्क हो जाती हैं। इससे गर्मी कम हो ही नहीं पाती। पलावत ने बताया कि दिन में भीषण गर्मी के कारण पिछले कुछ दिनों से रात का तापमान भी अधिक बना हुआ है। जमीन को संचित गर्मी छोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे रातें लगातार गर्म रहती हैं। अभी अगले सप्ताह भर तक कमोबेश यही स्थिति बनी रहेगी। गुरुवार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन भर आसमान साफ रहेगा। ज्यादातर जगह लू चलेगी। कहीं-कहीं गंभीर श्रेणी की लू भी चल सकती है। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 46 डिग्री जबकि न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

कश्मीरी गेट के पास भीषण गर्मी से बचने को गमछा ओढ़े दोपहिया पर जाते युवा। हरीश कुमार

इस बार नौतपा भी चौंकाएगा, बनाएगा नया रिकार्ड

संजीव गुप्ता • जागरण

नई दिल्ली : इस बार नौतपा भी चौंकाएगा। इस मौसम के सबसे गर्म माने जाने वाले इन नौ दिनों में भी चिलचिलाती धूप और लू का दौर जारी रहने के आसार हैं। तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग अभी से अलग- अलग दिनों के लिए यलो और आरेंज अलर्ट जारी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में इस बार नौतपा 15 साल में सबसे ज्यादा या दूसरा सर्वाधिक गर्म भी रह सकता है।

गौरतलब है कि सोमवार यानी 25 मई से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और नौ दिन यानी दो जून तक इसी में रहेगा। इस दौरान धरती पर सूर्य की गर्मी का ताप बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा के शुरुआती पांच दिन तापमान बढ़ने की संभावना रहती है। इस दिनों सूर्य सबसे अधिक बलवान रहता है। हालांकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक रहता है लेकिन नौतपा शुरुआती नौ दिनों को ही कहा जाता है। मौसम विभाग का भी मानना है कि सूर्य इन नौ दिनों के दौरान धरती के सर्वाधिक नजदीक होता है। इसीलिए धरती पर तपन भी अधिक रहती है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने और आसमान साफ रहने से झुलसा देने वाली धूप खासी तल्ख हो रही है।

न्यूज गैलरी

आप की मान्यता रद करने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की मान्यता रद करने और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और याचिकाकर्ता की दलीलें गलतफहमी पर आधारित और भ्रामक हैं। (जासं)

प्रबंधक ने कंपनी खाते से निकाले 1.50 करोड़ रुपये

नोएडा : सेक्टर 62 में आइटी कंपनी कार्यालय चलाने वाले निदेशक का सिम ब्लाक कराकर प्रबंधक ने पहले दूसरा सिम लिया। उस सिम से कंपनी के खाते से 1.50 करोड ट्रांसफर कर लिए। निदेशक के पूछने पर तकनीकी दिक्कत आने की बात कह टरकाया। तीन दिन बाद सिम चालू कराने पर निदेशक को फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ित निदेशक ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस फरार प्रबंधक की तलाश में जुटी है। (जासं)

कंबोडिया कनेक्शन वाले ठगी गिरोह का भंडाफोड़, आठ पकड़े

नई दिल्ली : स्टाक मार्केट में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ कर साइबर सेल थाना पुलिस ने आठ जालसाजों को गिरफ्तार किया है। कंबोडिया में बैठे सरगना के निर्देश पर वाट्सएप नंबरों का इस्तेमाल करके पीड़ितों को ठगी के जाल में फंसाते थे। (जासं)

निजी अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दिशा-निर्देश तय करे दिल्ली सरकार : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की नर्सिंग होम सुपरिंटेंडेंट को 23 मई को अधिकारियों की बैठक बुलाने का कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रियायती दर पर जमीन लेने वाले दिल्ली के निजी अस्पतालों में गरीबों के मुफ्त इलाज के बारे में दिशा-निर्देश और एसओपी तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की नर्सिंग होम सुपरिंटेंडेंट और ईडब्ल्यूएस इंचार्ज डा. कुसुम अरोड़ा को निर्देश दिया है कि वह 23 मई शाम चार बजे विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा-निर्देश तय करें।

यह आदेश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने रियायती दर पर जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों द्वारा गरीबों को मुफ्त इलाज देने के आदेश का पालन न करने के मामले में दिए हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक गरीबों को मुफ्त इलाज देने के अनुपालन का ब्योरा मांगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

वरिष्ठ वकील संजय जैन और वकील निनाद को कोर्ट की मदद करने के लिए न्यायमित्र नियुक्ति किया था।

कोर्ट ने न्यायमित्र से कहा था कि वे अस्पतालों द्वारा दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट को संयोजित कर कोर्ट मे रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट के निर्देश पर न्यायमित्र ने रिपोर्ट दाखिल की थी और कुछ सुझाव भी दिए थे जिसे देखने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की एक संयुक्त बैठक होनी चाहिए जिसमें गरीबों के इलाज के बारे में दिशा निर्देश तय किए जाएं। कोर्ट ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक करने का आदेश दिया है। बैठक में नोटिस मिलने अस्पतालों के प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के परिवार व स्वस्थ्य विभाग के सचिव, भारत सरकार के भूमि विकास आफिस के निदेशक, भूमि की मालिक एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी, एमसीडी और एनडीएमसी के डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी, डीडीए के निदेशक स्तर के अधिकारी और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव होंगे। बैठक डा. कुसुम अरोड़ा बुलाएंगी और यह बैठक तब तक चलेगी जब तक कि दिशा निर्देश तैयार नहीं हो जाते। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 29 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्देश दिया था कि दिल्ली में जिन निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन आवंटित हुई है वे गरीबों को मुफ्त इलाज देंगे।

सीबीएसई पोर्टल से स्कैन कापी लेने में दूसरे दिन भी आई समस्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: सीबीएसई की आनलाइन व्यवस्था में तकनीकी गड़बड़ी के चलते 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी प्राप्त करने की प्रक्रिया आवेदन की शुरुआत के दूसरे दिन (बुधवार को) भी प्रभावित रही। बोर्ड ने समस्या की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी प्राप्त करने के लिए आनलाइन आवेदन पोर्टल फिलहाल तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है, जिसे ठीक करने के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। बोर्ड की ओर से परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि समस्याओं के बाद बुधवार दोपहर दो बजे तक दोबारा पोर्टल शुरु करने का प्रयास किया गया।

बोर्ड के अनुसार, जिन छात्रों को पुनर्मूल्यांकन या शिकायत निवारण के उद्देश्य से उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कापी चाहिए, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं केवल रिकार्ड या आर्काइव उद्देश्य से स्कैन कापी लेने वाले छात्रों को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद पर सुरक्षा बढ़ाई गई

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से कड़ा कर दिया है। किसी भी संभावित विरोध-प्रदर्शन, पूजा-अर्चना के प्रयास की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए एएसआइ ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाए हैं। एएसआइ ने कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में पर्यटकों की निगरानी के लिए एक सुरक्षाकर्मी लगा दिया है। वहीं, माता पार्वती की मूर्ति तथा मस्जिद के पीछे के भाग में कांच के बाक्स में बंद गणेश जी की मूर्ति के पास भी एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती कर दी है। एएसआइ को आशंका है कि कुछ हिंदू संगठन या दक्षिणपंथी कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं।

बता दें कि कुतुबमीनार परिसर यहां की मस्जिद की दीवारों और खंभों में लगी देवी देवताओं की मूर्तियों के कारण विवादों में है। एएसआइ के अधिकारियों ने बुधवार को मस्जिद परिसर का निरीक्षण भी किया।

घर में घुसकर युवती से गैंगरेप, अगले दिन फिर बुलाया तो पीड़िता ने दी जान

जागरण संवाददाता, नूंह

▸ गांव के ही पांच युवकों पर मुकदमा दर्ज, आरोपितों ने वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

हरियाणा में नूंह के बिछौर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच युवकों ने घर में घुसकर एक 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने दुष्कर्म का वीडियो बना लिया और युवती को अगले दिन फिर मिलने के लिए बुलाया। ब्लैकमेल से आहत पीड़िता ने जहर निगलकर जान दे दी। पुलिस ने पिता की शिकायत पर दो नामजद समेत पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित पिता ने कहा है कि 18 मई को वह रिश्तेदारी में गए थे। बेटी और पत्नी घर पर अकेली थीं। पत्नी छप्पर में सो रही थी, जबकि बेटी मकान में अकेली थी। रात करीब एक बजे आरोपित अरशद, जाहुल व उनके तीन साथी जबरन घर में घुस आए। इन लोगों ने बारी-बारी बेटी से दुष्कर्म किया। बेटी ने चीखने की कोशिश की तो मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, इंटरनेट मीडिया पर वीडियो

प्रतीकात्मक

प्रसारित करने की धमकी देकर 19 मई को दिन में मिलने के लिए बुलाया। युवती ने दोपहर में जहर निगल लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। दूसरे अस्पताल ले जाते समय 19 मई की शाम बेटी ने दम तोड़ दिया। बिछोर थाना प्रभारी राजबीर सिंह ने बताया कि मामले में स्वजन की शिकायत पर दो नामजद सहित पांच युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दीपिका नागर की मौत के मामले में सास और चचिया ससुर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र स्थित जलपुरा गांव में विवाहिता दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले में पुलिस ने दीपिका की सास पूनम व चचिया ससुर विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में दीपिका के पति ऋतिक व ससुर मनोज को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ननद नेहा व तन्नी के साथ चचिया ससुर प्रमोद अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। ईकोटेक तीन कोतवाली पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी को चार टीमों का गठन किया है।

ज्ञात हो कि जलपुरा गांव में रविवार रात मकान की चौथी मंजिल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर 25 वर्षीय दीपिका की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 13 जगह गंभीर चोट मिली हैं। हालांकि छत से गिरकर मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो सका है। जहरीले पदार्थ की आशंका के चलते बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा है।

हड़ताल पर रहे अधिवक्ता, जुर्माना लगा पक्षकारों पर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ न्यायिक समय बर्बाद करने पर सोमवार को कई अदालतों ने दो से 30 हजार तक का लगाया जुर्माना

राजधानी की जिला अदालतों में सोमवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के बीच कई अदालतों ने मुकदमों में स्थगन देने से इन्कार करते हुए सख्त रुख अपनाया, जिसका खामियाजा सीधे-सीधे पक्षकारों को भुगतना पड़ा। विभिन्न अदालतों ने अधिवक्ताओं की गैरहाजिरी व कार्यवाही में देरी को लेकर पक्षकारों पर दो हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया। कुछ जिला अदालतों ने आदेश में कहा कि हड़ताल के कारण न्यायिक समय की बर्बादी और असुविधा हुई है।

पटियाला हाउस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने एक मामले में एक पक्ष पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि मामला समयबद्ध सुनवाई वाला है और दिल्ली हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शुरू में प्रतिवादी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। बाद में जब अदालत प्रतिकूल आदेश पारित करने वाली थी तब प्राक्सी अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

कोर्ट ने दी चेतावनी : मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता ने स्थगन की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के

प्रतीकात्मक

निर्देशों के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, अदालत ने प्रतिकूल आदेश पारित करने के बजाय मामले को 30 मई तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन प्रतिवादी पर 30 हजार का जुर्माना लगाया। यह राशि नई दिल्ली जिला के लायर्स वेलफेयर फंड में जमा कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आगे किसी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली बार कोआर्डिनेशन कमेटी के अनुरोध पर जिला अदालतों में सोमवार को वकीलों ने हड़ताल की थी।

दवा दुकानदारों के देशव्यापी बंद का दिखा मिलाजुला असर

नई दिल्ली, प्रेट्र : आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स द्वारा बुलाई गई एक दिवसीय हड़ताल का मिला जुला असर दिखा। हालांकि, संगठन ने दावा किया कि देश भर में उन्हें भारी समर्थन मिला। यह बंद आनलाइन विक्रेताओं द्वारा अत्यधिक छूट के खिलाफ था। संगठन का दावा है कि वह 12.4 लाख केमिस्टों, फार्मासिस्टों और वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है और आनलाइन फार्मेसियों के "अवैध" संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। संगठन ने कहा कि देशव्यापी हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और इसे देशभर के केमिस्ट और दवा विक्रेताओं का भरपूर समर्थन मिला।" उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी और हड़ताल को सफल बनाया। संगठन ने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक व आपातकालीन दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ संगठित फार्मेसी श्रृंखलाओं की दुकानें खुली थीं।

विरोध प्रदर्शन के नाम पर कोई हिंसा स्वीकार नहीं : हाई कोर्ट

सख्ती

केंद्रीय मंत्री नड्डा के आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में आरोपितों को राहत देने से इन्कार, कोर्ट ने कार्रवाई को बेहद विघटनकारी गतिविधि करार दिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सरकारी आवास के बाहर पुतला जलाने के मामले में आरोपितों को राहत देने से इन्कार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने आरोपितों की आरोपमुक्त किए जाने की याचिका खारिज करते हुए उनकी कार्रवाई को बेहद विघटनकारी गतिविधि करार दिया।

न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि आरोपित जगदीप सिंह उर्फ जग्गा और अन्य लोगों ने सड़क पर केवल पुतला ही नहीं जलाया, बल्कि सुरक्षाकर्मियों के विरोध के बावजूद सड़क, फुटपाथ और सर्विस लेन पार कर जलते हुए हिस्सों को सुरक्षा कक्ष की छत पर फेंका।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर उद्देश्य केवल विरोध प्रदर्शन होता, तो आरोपितों के पास चौड़ी सड़क और फुटपाथ पार कर जलते

विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन मारो और भाग जाओ जैसी हिंसक गतिविधियों को वैध प्रदर्शन नहीं माना जा सकता। समाज का एक वर्ग विरोध के नाम पर विघटनकारी गतिविधियों में शामिल हो रहा है।
– दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

हुए पुतले को सुरक्षा कक्ष की ओर फेंकने का कोई कारण नहीं था। सुरक्षाकर्मियों के मौजूद रहने के बावजूद जलता हुआ पुतला फेंकना ऐसा कृत्य था, जिससे मौत या गंभीर चोट लगने की पूरी संभावना थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आइपीसी की धारा 436 केवल विस्फोटक पदार्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि आग से की गई शरारत पर भी लागू होती है। धारा 285 लागू करने की दलील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपितों का कृत्य लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कार्य था।

याचिका को किया खारिज : याचिका को निरर्थक बताते हुए हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और आरोपितों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि एक सप्ताह के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा संचालित भारत के वीर ट्रस्ट में जमा कराई जाए। अभियोजन के अनुसार, 21 जून 2022 को जेपी नड्डा के सरकारी आवास के बाहर आरोपित एकत्र हुए थे। उन्होंने नारेबाजी की और पुतला जलाया। आरोपित जलते हुए पुतले को लकड़ी की मदद से उठाकर गेट और सुरक्षा कक्ष की छत की ओर फेंककर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसका फुटेज आरोपपत्र का हिस्सा है।

कोर्ट फीस वापसी में देरी पर चार माह में नीति बनाने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालतों में जमा कोर्ट फीस की वापसी में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को चार माह के भीतर स्पष्ट नीति या दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब पक्षकारों के बीच विवाद सुलझ जाता है, तो कोर्ट फीस लौटाने में अनावश्यक देरी का कोई औचित्य नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि दिल्ली में कोर्ट फीस रिफंड की प्रक्रिया बेहद लंबी है और आवेदन देने के बाद राशि वापस मिलने में डेढ़ से दो साल तक लग जाते हैं।

फर्जी विश्वविद्यालयों पर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार व यूजीसी से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

▸ मामले की अगली सुनवाई अब होगी अगस्त में, कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी

देश में खुल रहे फर्जी उच्च शिक्षण संस्थानों (फर्जी विश्वविद्यालयों) को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इन फर्जी संस्थानों के चक्कर में फंसने वाले छात्र अक्सर छोटे शहरों से आते हैं, जो समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं और अंत में उन्हें ऐसी डिग्रियां मिलती हैं जिनसे नौकरी नहीं मिल पाती है। मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी।

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने वकील शशांक देव सुधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसे संस्थानों की तरफ आकर्षित होने वाले छात्र अगर वहां पढ़ाई पूरी भी कर लेते हैं तो अंत में उनका समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी ही होती है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस हलफनामे में बताना होगा कि उन्होंने ऐसे फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने फर्जी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। कोर्ट ने पूछा है कि इस कमेटी ने अब तक क्या जानकारी जुटाई है और ऐसे संस्थानों को बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

15.4 लाख नामांकित वकील हैं देश में, इनमें से केवल 2.84 लाख (लगभग 15.31 प्रतिशत) ही महिलाएं हैं। हैरत की बात यह है देश के विभिन्न संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्राएं पास होकर निकल रही हैं,पर पेशेवर वकीलों के रूप में उनकी संख्या काफी कम है।

इसी वर्ष वायुसेना को मिल जाएंगे 'तेजस मार्क 1ए' लड़ाकू विमान

रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार बोले, वर्तमान वित्तीय वर्ष में एचएएल द्वारा विमानों की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी

तेजस विमान लगभग 90 प्रतिशत तैयार, कुछ हथियारों के एकीकरण (इंटीग्रेशन) का काम अंतिम चरण में है

वायुसेना ने दो किश्तों में 180 तेजस मार्क 1ए विमानों का आर्डर दिया है, जो देश की हवाई संप्रभुता को नई ताकत देंगे

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूत करने वाले स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस मार्क 1ए' की आपूर्ति को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर आई है। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने पूर्ण विश्वास जताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा इन विमानों की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि, इस परियोजना में कुछ कारणों से देरी हुई है, लेकिन अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है।

संजीव कुमार ने बताया कि तेजस विमान लगभग 90 प्रतिशत तैयार है, लेकिन कुछ हथियारों के एकीकरण (इंटीग्रेशन) का काम अंतिम चरण में है। उन्होंने साफ किया कि विमान की डिलीवरी में देरी की मुख्य वजह अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस से इंजनों की आपूर्ति में रुकावट है। कोविड-19 महामारी और वैश्विक स्तर पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ी इंजनों की मांग के कारण जीई की सप्लाई चेन प्रभावित हुई। साथ ही, पश्चिम एशिया संकट के चलते साफ्टवेयर मिलने में भी देरी हुई है।

भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि वह पूरी तरह संचालित और

तेजस मार्क 1ए लड़ाकू विमान। फाइल

अपडेटेड कान्फिगरेशन में ही विमान स्वीकार करेगी। तेजस विमाानों की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई देशों ने इसे खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

रक्षा उत्पादन सचिव के अनुसार, तेजस के लिए दुनिया भर के कई देश इच्छुक दिख रहे हैं, लेकिन भारत ने एक रणनीतिक फैसला लिया है। हमारी पहली प्राथमिकता भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करना है, उसके बाद ही रक्षा निर्यात शुरू किया जाएगा। वर्तमान में वायुसेना ने दो किश्तों में 180 तेजस मार्क 1ए विमानों का आर्डर दिया है, जो भारत की हवाई संप्रभुता को नई ताकत देंगे।

ड्रोन निर्माण एवं रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी और आत्मनिर्भरता पर जोर

संजीव कुमार के अनुसार, भारत में एक मजबूत ड्रोन विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने के लिए निजी क्षेत्र अधिक सक्षम और कुशल है। सरकार की नीतियों का मुख्य फोकस रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है, जो रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और डीआरडीओ की पहलों में भी झलकता है। उन्होंने 'दोहरे उपयोग वाली तकनीक' पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई, ताकि युद्ध के समय नागरिक फैक्ट्रियां तेजी से रक्षा उत्पादन में बदलाव कर सकें। रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका अर्थ देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला पर भारत का नियंत्रण होना है। वास्तविक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य डिजाइन क्षमताओं को भारत के पास रखना और सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुसार हथियारों में बदलाव करना है।

इजरायल की पल्स तकनीक का भारतीय संस्करण है सूर्यास्त्र

सूर्यास्त्र के परीक्षण का दृश्य। स्रोत: डीआरडीओ

प्रथम पृष्ठ से आगे

सूर्यास्त्र प्रणाली को इस तरह विकसित किया गया है कि यह दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला कर सके, जिससे प्रक्षेपण प्लेटफार्म सुरक्षित दूरी पर रहकर भी प्रभावी कार्रवाई कर सके। 'सूर्यास्त्र' इजरायली रक्षा कंपनी एलबिट सिस्टम्स की प्रिसिजन एंड यूनिवर्सल लान्चिंग सिस्टम (पल्स) तकनीक का भारतीय संस्करण है, जिसे नीबे लिमिटेड संग मिलकर विकसित किया गया है। इस परियोजना में 'मेक इन इंडिया' व 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत स्वदेशी विनिर्माण-तकनीकी हस्तांतरण को शामिल किया गया है। सेना ने इस वर्ष जनवरी में 293 करोड़ रुपये के आपातकालीन क्रय आदेश के तहत इस प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसमें लांचर, सप्लाई-कम-लोडर वाहन, राकेट, पुर्जे और तकनीकी सहायता शामिल हैं।

'संघमित्रा' का जलावतरण, नौसेना को मिलेगी नई ताकत

कोलकाता में बुधवार को एनजीओपीवी संघमित्रा के जलावतरण के दौरान नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, उनकी पत्नी व अन्य। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- जीआरएसई ने नौसेना के लिए पहले नेक्स्ट जेनरेशन आफशोर पेट्रोल वेसल 'संघमित्रा' का किया जलावतरण
- 3000 टन वजनी यह युद्धपोत समुद्री निगरानी, एंटी पाइरेसी और राहत अभियानों में निभाएगा अहम भूमिका

गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने बुधवार को भारतीय नौसेना के लिए पहले नेक्स्ट जेनरेशन आफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी) 'संघमित्रा' का जलावतरण किया। कोलकाता स्थित शिपयार्ड में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वाइस एडमिरल संजय वात्सायन की पत्नी सरिता वात्सायन ने इस युद्धपोत का जलावतरण किया।

जीआरएसई नौसेना के लिए ऐसे चार अत्याधुनिक युद्धपोत बना रहा है। 'संघमित्रा' नाम सम्राट अशोक की पुत्री से प्रेरित है, जिन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। करीब 113 मीटर लंबे और 3000 टन वजनी ये युद्धपोत 23 नाट्स तक की रफ्तार से चल सकेंगे। इनमें 8500 नाटिकल मील तक समुद्र में लगातार अभियान चलाने की क्षमता होगी। युद्धपोत का उपयोग समुद्री निगरानी, तस्करी व घुसपैठ रोकने, एंटी पाइरेसी अभियान, खोज एवं बचाव कार्य व आपदा राहत अभियानों में किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इन्हें अस्पताल और विशेष अभियान सहायता पोत के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने कहा, नौसेना अब युद्ध के लिए ही नहीं, समुद्री क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग बनाए रखने के लिए भी तैयार है। उन्होंने युद्धपोतों के निर्माण में जीआरएसई की भूमिका की सराहना की। जीआरएसई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पीआर हरि ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भी कई नए युद्धपोतों का जलावतरण और सुपुर्दगी की जाएगी।

विज्ञान और पर्यावरण की स्थायी संसदीय समिति की अध्यक्ष बनीं मेधा कुलकर्णी

नई दिल्ली, प्रेट्र: राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्ण ने भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थायी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह समिति सरकार की नीतियों की समीक्षा, बजटीय आवंटनों का आकलन, प्रमुख वैज्ञानिक और पर्यावरणीय विभागों के लिए विधायी प्रविधानों का मूल्यांकन करती है।

लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भाजपा सदस्य सुधीर गुप्ता को कार्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विनोद श्रीधर तावड़े, सुजीत कुमार, उज्ज्वल देओराव निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, विवेक के. टंका, आर. गिरिराजन, एस. निरंजन रेड्डी, संजय कुमार झा (सभी राज्यसभा से) कार्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 की संयुक्त समिति के सदस्य हैं। लोकसभा के जिन सदस्यों को समिति में नामित किया गया है, उनमें कमलजीत सेहरावत, मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल, सुधीर गुप्ता, बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, पीपी चौधरी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, शशांक मणि, वरुण चौधरी, सुधा आर, धनोरकर प्रतिभा सुरेश, राहुल कासवान, डिंपल यादव, महुआ मोइत्रा, दयानिधि मारन, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, सुप्रिया सुले, देवेश चंद्र ठाकुर, अनिल यशवंत देसाई और नरेश गणपत म्हासके शामिल हैं।

भारत में कोई इबोला संक्रमित नहीं, पर केंद्र सरकार सतर्क

- केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए सतर्कता के निर्देश
- इबोला वायरस के विश्व में फैलने का खतरा क्षीण : डब्ल्यूएचओ

नई दिल्ली, प्रेट्र : अफ्रीकी देश कांगो और यूगांडा में फैले इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला भारत में सामने नहीं आया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने बुधवार को इस बाबत बैठक करके स्थितियों और तैयारियों की समीक्षा की।

रायटर के अनुसार कांगो और यूगांडा में फैले इबोला वायरस संक्रमण से अभी तक 139 लोग मरे हैं जबकि करीब 600 मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में आठ लोगों के मरने की सूचना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि वायरस संक्रमण की जो रफ्तार है उससे इसके क्षेत्रीय देशों में ही फैलने की आशंका है, वायरस के पूरे विश्व में संक्रमण का खतरा बहुत कम है। स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस

अधानम गेब्रेसस ने कहा है कि इबोला का संक्रमण वैश्विक महामारी का रूप लेने का खतरा बहुत कम है। इबोला वायरस के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के संक्रमण से जुड़े खतरों और उसके नियंत्रण पर विचार के लिए संगठन द्वारा गठित इमर्जेंसी कमेटी की मंगलवार को जिनेवा में हुई बैठक में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि इस स्ट्रेन को निष्प्रभावी करने के लिए वैक्सीन बनाने में कई महीने का समय लग सकता है, ऐसे में लक्षणों को खत्म करने वाली दवाओं के जरिये बीमारी का इलाज किया जाए और संक्रमण फैलने से रोकने के तरीकों को अमल में लाया जाए।

साइप्रस के राष्ट्रपति चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे

नई दिल्ली, एएनआइ: साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने व्यापार, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर बुधवार को भारत पहुंचे। वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों और कारोबारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए क्रिस्टोडौलाइड्स ने मुंबई से अपनी यात्रा शुरू की और गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल जून में साइप्रस का दौरा किया था। दो दशक से अधिक समय में भारत के प्रधानमंत्री की साइप्रस की यह पहली यात्रा थी। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को व्यापक वार्ता होने वाली है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्स व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, गतिशीलता, रक्षा एवं सुरक्षा, एआई, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

बदलाव के दशक में है भारत, कोई ताकत रोक नहीं सकती

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में कहा-किसी प्रकार के परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेंगे
- भारत और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा, सूचना साझा करने का किया समझौता

सियोल, एएनआइ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। बारह साल पहले, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाला दशक भारत के लिए एक बदलाव का दशक होगा, लेकिन इन 12 वर्षों में हुए परिवर्तनों ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और दुनिया की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। भारत अब किसी प्रकार के परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। इसी के साथ, द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया ने एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य रक्षा, साइबर और रक्षा सूचना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है।

सियोल में बुधवार को भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ उसकी बढ़ती वैश्विक स्थिति को उजागर किया। उन्होंने भारत की रक्षा तैयारियों का उल्लेख कर चेताया कि यदि उकसाया गया तो भारत कड़ी प्रतिक्रिया देगा। कोई भी भारत को रक्षा मामलों में कमजोर नहीं समझे। कोई हमें चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो हम दृढ़ता से जवाब देंगे। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर अप्रत्यक्ष संदेश देते हुए कहा, "कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोग हमारी संयम और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोरी समझ लेते हैं। जबकि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज़ नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, वह किसी भी प्रकार के परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। यह नया भारत है।" उन्होंने कहा "किसी नेता या पार्टी के लिए बार-बार चुनाव जीतना केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, यह जन विश्वास के स्तर को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं।"

सियोल में बुधवार को अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष आंन ग्यू-बैक को स्मृति चिह्न भेंट करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक विशेषज्ञ हमारे विकास माडल को कल्याणकारी राजनीति का नया माडल बता रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में विकसित विक्रम 32-बिट चिप को सेमीकान इंडिया-2025 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इंटरनेट पहुंच पर कहा, "जो कभी विलासिता थी, वह अब लाखों लोगों के लिए सुलभ है। डाटा बेहद सस्ता हो गया है और डिजिटल सेवाएं देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं। यूपीआइ ने देश में एक क्रांति ला दी है और कई देश अब इसे अपना रहे हैं। चंद्रयान-3 भारत की वैज्ञानिक सफलता का गर्वित उदाहरण है।"

रक्षा मंत्री सिंह की सियोल की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनके दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आंन ग्यू-बैक की उपस्थिति में द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, साइबर व रक्षा सूचना के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। यह सहमति पत्र नई दिल्ली और सियोल के बीच रणनीतिक संबंधों को गहरा करता है, विशेष रूप से आधुनिक युद्ध और खुफिया चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। दक्षिण कोरिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह यात्रा 18 से 21 मई तक है।

केरलम सरकार ने सिल्वरलाइन परियोजना को किया रद

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने तिरुअनंतपुरम से कासरगोड तक सिल्वरलाइन नामक सेमी-हाई स्पीड रेल परियोजना को रद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, सरकार इस परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को अदालत के फैसले के अधीन वापस लेने की सिफारिश भी करेगी। उल्लेखनीय है कि यह पिछली एलडीएफ सरकार की महत्वाकांक्षी पहल थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि परियोजना को छोड़ दिया गया था और अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि पर कोई लेन-देन नहीं हो सका, जिससे आम जनता प्रभावित हुई। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार की 530 किमी लंबी सिल्वरलाइन परियोजना से राज्य के दोनों छोर पर स्थित दो जिलों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र चार घंटे होने की उम्मीद थी। कांग्रेस के नेतृत्व में इस परियोजना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।

संसदीय पैनल ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर चिंता जताई

- ऐसे सभी डिजिटल लेनदेन पर कर जारी रखने का समर्थन किया
- हितधारकों के दृष्टिकोण को समझने के लिए समिति बैठक करेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक संसदीय पैनल ने क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश को "चिंताजनक" करार दिया और सभी ऐसे डिजिटल लेनदेन पर कर जारी रखने का समर्थन किया।

भाजपा सांसद भर्तहरी महताब की अध्यक्षता में बुधवार को वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की। भाजपा सांसद ने कहा, बहुत से लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं। इसलिए इस पहलू पर यह आवश्यक है कि जो भी निवेश किया जा रहा है और पैसा अर्जित किया जा रहा है, उसे हमारे देश में कर लगाया जाना चाहिए और आयकर कानून में भी यह प्रविधान है। हितधारकों के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है और समिति इस विषय पर आगे की बैठक करेगी। आरबीआइ वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के संचालन के लिए विनियमन या अनुमति देने के खिलाफ है।

सूत्रों ने बताया कि पैनल के कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जब क्रिप्टोकरेंसी पर कोई नीति नहीं है तो सरकार 30 प्रतिशत कर कैसे लगा रही है। वर्तमान में भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक कानूनी ग्रे क्षेत्र है, जिसमें उनकी वैधता को नियंत्रित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी आयकर और जीएसटी के अधीन है। महताब ने कहा कि बैठक में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के बारे में चर्चा की गई, जहां भारत में कार्यरत और पंजीकृत हितधारकों ने प्रस्तुतियां दीं। लेकिन हमें यह चिंता है कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों में हजारों करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है, जो वास्तव में बहुत चिंताजनक है और यह सब देश से बाहर जा रहा है। इसके साथ ही, हमने राजस्व सचिव, आयकर विभाग के अधिकारियों और कार्पोरेट मामलों के सचिव को भी को भी बुलाया क्योंकि कराधान से संबंधित मामले में तीनों शामिल हैं।

दो प्रस्तावित कानूनों की जांच कर रही समिति

प्रथम पृष्ठ से आगे

सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 41 सदस्यीय संसदीय समिति एक साथ चुनाव से संबंधित दो प्रस्तावित कानूनों-संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण यह है कि चुनाव सुधारों से राष्ट्र को लाभ होना चाहिए।

एक साथ चुनाव से कोई संवैधानिक समस्या नहीं : पीपी चौधरी ने कहा, वह एक साथ चुनाव कराने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। देश के छह पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने समिति को बताया कि इससे संघीय संरचना, मूल संरचना या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। कोई संवैधानिक समस्या नहीं होगी। विधि आयोग और नीति आयोग ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की है। संसद की स्थायी समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

अलकनंदा-भागीरथी पर कोई नई पनबिजली परियोजना नहीं लाएंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
- पूर्व में हुई त्रासदियों को ध्यान में रखते हुए लिया निर्णय

पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और सांस्कृतिक महत्व की अलकनंदा-भागीरथी नदियों पर कोई नई पनबिजली परियोजना नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चल रही सात परियोजनाओं, जिनमें ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरी होने वाली हैं, के अलावा सरकार अलकनंदा-भागीरथी नदियों पर किसी नई पनबिजली परियोजना को अनुमति नहीं देगी।

यह हलफनामा 2013 में केदारनाथ में बादल फटने की त्रासदी के बाद उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के मामले में दाखिल किया गया है। कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं के बारे में अदालत द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों पर तीन माह में फैसला लेकर हलफनामा दाखिल करे। सरकार ने यह हलफनामा वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के आपसी परामर्श के बाद दाखिल किया गया है।

हलफनामे में कहा गया है कि उत्तराखंड में अलकनंदा व भागीरथी नदी बेसिन में किसी नई पनबिजली परियोजना को अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार ने जिन सात लंबित परियोजनाओं की बात कही है, उनमें भागीरथी नदी पर बनी 1000 मेगावाट की टीएचडीसीआइएल की टेहरी स्टेज टू, टेहरी पीएसपी परियोजना है जो चालू हो चुकी है। धौलीगंगा नदी पर एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाद परियोजना निर्माणाधीन है। इसका 75.28 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार अलकनंदा नदी पर टीएसडीसीआइएल की 444 मेगावाट की विष्णुगाद पीपल कोटी परियोजना भी निर्माणाधीन है। इस परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मंदाकिनी नदी पर एलएनटी की 99 मेगावाट की सिंगोली भाटवारी परियोजना नवंबर 2020 में चालू हो चुकी है। लैंको की 76 मेगावाट की फाटा ब्यूंग परियोजना का 74 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मधमहेश वार गंगा नदी पर यूजेवीएनएल की 15 मेगावाट की मधमहेश्वर परियोजना चालू हो गई और कालीगंगा नदी पर चमोली हाइड्रो की 4.5 मेगावाट की कालीगंगा टू परियोजना मई 2022 में चालू हो चुकी है। सरकार ने कहा है कि इन सात में से चार परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और पूर्व में हुई त्रासदियों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाएं शुरू न करने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' द्वारा दायर जनहित याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए यह नोटिस जारी किया, अदालतों में आधी आबादी को उनका हक दिलाने, न्याय प्रणाली में लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम

सरकारी पैनलों में महिला वकीलों के 30% कोटा पर केंद्र-राज्य दें जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश की अदालतों में आधी आबादी को उनका हक दिलाने और न्याय प्रणाली में लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया है। कोर्ट ने सरकारी पैनलों और विधि अधिकारी (ला आफिसर) के पदों पर महिला वकीलों को न्यूनतम 30 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' द्वारा दायर इस याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि महिला वकीलों की स्थिति पर किए गए एक हालिया सर्वेक्षण के बाद यह याचिका दायर की गई है। सरकारी पैनलों में महिलाओं को शामिल किया जाना उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए बेहद जरूरी है।

कानूनी दुनिया में लैंगिक असमानता खत्म करने की गुहार

याचिका में कहा गया है कि देश में कुल 15.4 लाख नामांकित वकीलों में से केवल 2.84 लाख (लगभग 15.31 प्रतिशत) ही महिलाएं हैं। बेटियां रिकार्ड संख्या में ला कालेजों में दाखिला तो ले रही हैं, लेकिन पेशेवर प्रगति के स्तर पर उन्हें व्यवस्थागत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सरकारी पैनलों से महिलाओं का यह बहिष्कार केवल पेशेवर असमानता नहीं, बल्कि एक गंभीर संवैधानिक चूक है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट पैनल, हाई कोर्ट पैनल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कानूनी स्तरों पर महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाए जाएं, ताकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 19(1)(जी) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

75 वर्षों में एक भी महिला अटार्नी जनरल नहीं : 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' की ओर से दायर याचिका में देश की कानूनी प्रणाली में महिलाओं की कम भागीदारी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े और कड़वी सच्चाई सामने रखी गई है। याचिका के अनुसार, आजादी के 75 से अधिक वर्षों के बाद भी आज तक कोई महिला भारत की अटार्नी जनरल या सालिसिटर जनरल नहीं बन सकी है।

वर्ष 1989 में जस्टिस एम. फातिमा बीवी के देश की पहली महिला जज बनने के बाद से पिछले 35 वर्षों में केवल 11 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केवल 5.88 प्रतिशत और हाई कोर्ट्स में करीब 13.76 प्रतिशत महिला जज हैं।

सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने भी एक वाकया साझा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के एक बार निकाय की महिला प्रतिनिधि उनसे मिली थीं, जिन्हें वहां सचिव नियुक्त किया गया है। सीजेआइ ने जब वहां की कुल संख्या पूछी, तो पता चला कि 19 हजार वकीलों में से करीब दो हजार महिला वकील हैं, लेकिन पद पर केवल एक महिला को जगह मिली है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

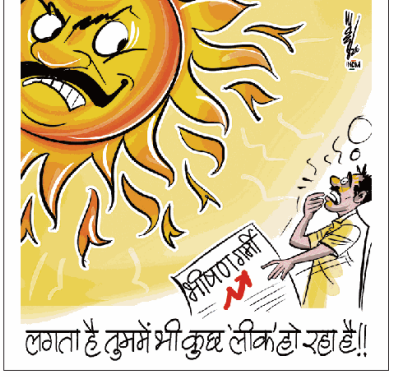

20 मई को कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और पार्टी के अनुसूचित जाति सेल के चेयरमैन राजेन्द्र पाल गौतम ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात का प्रयास कर राज्य में राजनीतिक हलचल मचा दी। सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों के बीच इस मुलाकात के प्रयास से निकले संदेशों से कांग्रेस असहज हो गई।

छह दशक बाद कांग्रेस बनेगी तमिलनाडु सरकार का हिस्सा

पार्टी के दो विधायक आज विजय की सरकार में बतौर मंत्री लेंगे शपथ

दो दशक साथ रहने के बाद भी द्रमुक ने कभी कांग्रेस को सत्ता में भागीदार नहीं बनाया

1952 से 1967 तक कांग्रेस ने तमिलनाडु (तबके मद्रास राज्य) में सत्ता संभाली थी

पी. विश्वनाथन।

राजेश कुमार।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा हो, मगर करीब छह दशक के लंबे अंतराल के बाद पार्टी राज्य सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रमुक के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस ने बहुमत से पीछे रहे विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह बनाने में अहम भूमिका निभाई। द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व वाले तमिलनाडु में कांग्रेस के दो विधायकों का मंत्री बनना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वस्तुतः छह दशक बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी राज्य की सत्ता में भागीदार बन रही है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विधायक एडवोकेट राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है और गुरुवार को दोनों मंत्री पद की शपथ लेंगे।

तमिलनाडु की सत्ता-सियासत में पार्टी के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो दशक तक गठबंधन में होने के बाद भी द्रमुक ने कांग्रेस को कभी सत्ता में भागीदारी नहीं दी। वेणुगोपाल ने भी माना कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि 59 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल हो रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों मंत्री तमिलनाडु की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रह गए विजय को मुख्यमंत्री बनाने में राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों के समर्थन का एलान कर टीवीके के पक्ष में विधायकों की संख्या 113 तक पहुंचा दी। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य छोटे दलों के गठबंधन में आने की राह बनी। द्रमुक संग पुराने गठबंधन को तोड़कर तत्काल विजय को समर्थन देने के कांग्रेस के एलान ने स्टालिन को भी हतप्रभ किया और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना भी की। चुनाव नतीजों ने पार्टी को राज्य की राजनीति में नए विकल्प के रास्ते पर चलने का मौका दे दिया है।

1952 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु (तत्कालीन मद्रास राज्य) की सत्ता संभाली। इस दौरान सी. राजगोपालाचारी, के. कामराज और एम. भक्तवत्सलम राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 1967 में द्रमुक ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। तब से लेकर पिछले छह दशकों तक राज्य में द्रमुक और अन्नाद्रमुक का शासन रहा।

सनातन धर्म का अपमान करने से बचें तमिलनाडु के नेता : कर्ण सिंह

कर्ण सिंह। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने बुधवार को तमिलनाडु के राजनेताओं से सनातन धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देशभर में असंख्य लोगों को दुख पहुंचाते हैं।

सिंह ने कहा कि वरिष्ठ तमिल राजनेताओं द्वारा सनातन धर्म को निशाना बनाकर की गई बार-बार की टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि तमिलनाडु के बाहर करोड़ों लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में देखते हैं और इसे जातिवादी व्याख्या देना और फिर इसकी निंदा करना पूरी तरह से अनुचित है।

उनकी यह टिप्पणी तमिलनाडु के नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयानों को लेकर नए सिरे से उठे विवाद के बीच आई है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 13 मई को सनातन धर्म के 'उन्मूलन' की अपनी मांग दोहराते हुए दावा किया कि यह लोगों को विभाजित करता है।

उत्तराखंड में राहुल के दौरे से कांग्रेस करेगी चुनावी शंखनाद

केदार दत्त • जागरण

- **लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस माह के आखिर या अगले माह के प्रथम सप्ताह में दौरा प्रस्तावित**

प्रतीकात्मक

देहरादून : उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश धीरे-धीरे महसूस की जाने लगी है। सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुनावी शंखनाद की तैयारी की है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस माह के आखिर या अगले माह के प्रथम सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। गढ़वाल व अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्रों में उनकी जनसभाएं हो सकती हैं।

राज्य की चुनावी पिच पर भाजपा पहले ही फ्रंट फुट पर खेल रही है। भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी चुनावी अभियान की तैयारी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस संगठन के बीच से भी पार्टी के केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारने की उठ रही मांग के क्रम में अब राहुल गांधी राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान से राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम का संदेश मिलने के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डा हरक सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के मध्य इसे लेकर मंथन चल रहा है। राहुल गांधी के दौरे के दृष्टिगत गढ़वाल व अल्मोड़ा में जनसभाओं के कार्यक्रम निर्धारित कर हाईकमान को जल्द ही सूचना भेजी जाएगी।

उत्तराखंड कांग्रेस में अभी धड़ेबाजी, अंदरूनी खींचतान, अविश्वास के बादल अभी छंटे नहीं हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं तो सबकी निगाह इस पर होगी कि राहुल किस तरह गुटबाजी में बंटी कांग्रेस को एकजुट करते हैं। राज्य में कांग्रेस की स्थिति यह है कि सात माह बाद भी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं।

हिमाचल में मंत्रियों के क्षेत्रों में हार के कारणों व सुधार पर होगा मंथन

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला: व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को उपचुनाव जीतने के बाद शहरी निकाय चुनाव में कुछ मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है। 22 मई को बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्री धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी व रोहित ठाकुर हार के कारणों पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को फीडबैक देंगे। बैठक में शहरी निकाय चुनाव परिणाम पर चर्चा होगी।

चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पार्टी के लिए चिंता का विषय यह है कि दिग्गज मंत्रियों के विधानसभा व गृह जिलों में कई नगर परिषद व नगर पंचायतों में हार का सामना करना पड़ा है। जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार हुई है, उनसे हार के कारण भी पूछे जाएंगे। मंत्री जो कारण बताएंगे, उन कमियों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि चार नगर निगमों व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव परिणाम 31 मई को आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट होगी। ऊना जिले के हरोली की नगर पंचायत टाहलीवाल पर भाजपा का कब्जा हुआ है, जो उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का गृह क्षेत्र है।

ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर रोक के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं महुआ

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- **तृणमूल कांग्रेस के विधायक अखरुज्जमान ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की याचिका**
- **याचिकाकर्ताओं का दावा, प्रतिबंध से कुर्बानी की परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी**

महुआ मोइत्रा। फाइल

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध को नियंत्रित करने संबंधी बंगाल सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने की। यह याचिका तृणमूल कांग्रेस विधायक अखरुज्जमान की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बंगाल सरकार की हालिया अधिसूचना से धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

मालूम हो कि यह अधिसूचना इसी महीने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लाटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत जारी की गई थी। इसके तहत पशुओं की आयु और शारीरिक स्थिति का पशु चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने के बाद ही वध की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार की अधिसूचना में बैल, सांड, गाय, बछड़े और भैंसों के वध से पहले 'फिटनेस प्रमाणपत्र' लेना अनिवार्य किया गया है। सुनवाई के दौरान महुआ ने दलील दी कि इस अधिसूचना से पशुपालन और पशु बिक्री पर निर्भर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों पर गंभीर वित्तीय असर पड़ेगा। यह प्रतिबंध ईद-उल-अजहा के दौरान होने वाली कुर्बानी की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप है।

फलता विस सीट पर आज बेहद कड़ी सुरक्षा में पुनर्मतदान

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : बंगाल की फलता विधानसभा (विस) सीट पर गुरुवार को बेहद कड़ी सुरक्षा में पुनर्मतदान होगा। हालिया संपन्न विस चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण के तहत 29 अप्रैल को यहां हुए मतदान में गड़बड़ी की ढेरों शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फिर से मतदान कराने का निर्णय लिया था। मालूम हो कि पुनर्मतदान से 48 घंटे पहले तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान चुनाव से हट गए।

उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्रतिद्वंद्विता नहीं करने की घोषणा करते हुए इसका कारण मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा फलता के लिए विशेष पैकेज की घोषणा बताया था। चूंकि नामांकन वापस लेने की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए नियमानुसार मतदान में प्रयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर उनका भी नाम रहेगा। पार्टी ने उनके निर्णय को निजी फैसला बताया है।

राहुल ने मोदी और शाह को गद्दार कहा, भड़की भाजपा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- **कांग्रेस सांसद बोले, युवा डिप्रेशन में और मेलोनी के साथ 'मेलोडी' खा रहे पीएम**
- **नितिन नवीन ने कहा- 'राहु' बन राजनीति का वातावरण दूषित कर रहे राहुल गांधी**

राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में 'बहुजन स्वाभिमान सभा' को संबोधित किया। प्रेट्र

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। भाजपा ने इस पर करारा पलटवार किया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को 'राहु' की संज्ञा देते हुए कटाक्ष किया कि वह राजनीति के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। यह बयान राहुल गांधी की अराजकतावादी और हताश मानसिकता को दर्शाता है।

जागरण संवाददाता के अनुसार, राहुल ने रायबरेली में आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा में कहा कि जब आप घर जाओगे और आरएसएस के लोग आपके सामने आकर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की बात करें, तो उनसे साफ कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है और आपका संगठन गद्दार है। आपने देश को बेचने और संविधान को नष्ट करने का काम किया है। राहुल ने यही बात अमेठी में भी दोहराई। कहा कि इन लोगों ने देश के महापुरुषों और जनता से गद्दारी की है। मैं इसके लिए उन्हें गद्दार ही कहूंगा और इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा।

राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। हम बड़े-बड़े आयोजन करते हैं, मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने महापुरुषों की विचारधारा का अपमान किया जाता है, तो हम मौन धारण कर लेते हैं। डाक्टर भीमराव आंबेडकर के संविधान पर आरएसएस खुलकर प्रहार कर रहा है। रायबरेली से अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर अंगुली उठाते हुए कहा कि देश में गैस नहीं, रोजगार नहीं, युवा डिप्रेशन में हैं और प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम मेलोनी के साथ 'मेलोडी' खा रहे हैं।

नई दिल्ली से जागरण ब्यूरो के अनुसार, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सवाल किया कि क्या माओवाद को समाप्त करना गद्दारी है? क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या पूरे विश्व में भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाना गद्दारी है? आने वाले समय में राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने बयानों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को भारत का विकास पसंद नहीं है। अपनी राजनीतिक हताशा और कुंठा के कारण वह लगातार देश की जनता को अपमानित करते हैं। राहुल को अमर्यादित, अशोभनीय और असंसदीय बयान के लिए 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल के इतने हल्के शब्द उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।

खरगे ने कहा-भाजपा के लिए लूट 'मेलोडी' है

प्रेट्र के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत के बावजूद प्रधानमंत्री अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखे हुए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया-मोदीजी चाहते हैं कि सरकार द्वारा लूट की तकलीफ झेलने के बावजूद जनता उनके भाषणों की 'मेलोडी' का आनंद ले। उन्होंने एक पोस्टर भी साझा किया, जिसका शीर्षक था-भाजपा के लिए लूट 'मेलोडी' है, लेकिन नागरिकों के लिए तकलीफ! कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि मोदीजी, देश संकट में है। कैंडी बांटना बंद कीजिए। कार्रवाई शुरू कीजिए।

अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की सूची में सायोनी घोष का सह मालकिन के तौर पर नाम!

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- **भाजपा ने अभिषेक व उनके परिवार से जुड़ीं कथित 43 संपत्तियों की सूची जारी की**
- **ममता ने फिरहाद से पूछा कि आखिर यह नोटिस कैसे और क्यों भेजा गया?**

भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ीं कथित 43 संपत्तियों की सूची जारी की गई है। कुछ संपत्तियों में सायोनी घोष नामक महिला का नाम सह मालकिन के तौर पर है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह तृणमूल सांसद सायोनी घोष हैं या कोई अन्य महिला। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक की मां लता बनर्जी को नोटिस भेजा था। निगम ने कालीघाट रोड स्थित एक भवन में स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण होने का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब तलब किया है। इसके बाद भाजपा ने अभिषेक व उनके परिवार से जुड़ीं कथित 43 संपत्तियों की सूची सार्वजनिक की है।

मालूम हो कि निगम के भवन विभाग की टीम ने अभिषेक व उनके करीबी लोगों से जुड़ीं विभिन्न संपत्तियों का गत सोमवार को निरीक्षण किया था। दूसरी तरफ अभिषेक ने कहा कि चाहे उनका घर तोड़ दिया जाए, लेकिन वे सिर नहीं झुकाएंगे। इन संपत्तियों में अभिषेक, उनकी पत्नी, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं। सूची में ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इन संपत्तियों की विस्तृत जांच कराई जाएगी।

कोलकाता नगर निगम के असेसमेंट विभाग की टीम ने अभिषेक के कालीघाट रोड स्थित आवास पर नोटिस जारी किया है। साथ ही हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनके आवास सहित कई कथित संपत्तियों से जुड़े मामलों में भी नोटिस दिए जाने की जानकारी है। मौके पर टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और संबंधित दस्तावेज सौंपे। अभिषेक की मां लता बनर्जी, पिता अमित बनर्जी और लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम भी नोटिस में शामिल बताए जा रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक कुणाल घोष ने इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अभिषेक सहित कुछ नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए उनकी संपत्ति से जुड़े जो आंकड़े फैलाए जा रहे हैं, वह पूरी तरह निराधार हैं।

नोटिस की जानकारी मेयर को नहीं, ममता नाराज

अभिषेक बनर्जी का घर तोड़ने के नोटिस की जानकारी तृणमूल संचालित कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम को नहीं है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ममता काफी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर ममता ने फिरहाद से पूछा कि आखिर यह नोटिस कैसे और क्यों भेजा गया। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त अपने अधिकार से सीधे ऐसा नोटिस जारी कर सकते हैं।

केंद्र से बात कर रही सब कमेटी की बैठक में शामिल होंगे सोनम वांगचुक

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू: लेह अपेक्स बाडी ने पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार से बात कर रही सब कमेटी में शामिल कर लिया है। उन्हें लेह अपेक्स बाडी से बाहर किए पूर्व सांसद थुप्सतन छिवांग की जगह लाया है। लेह अपेक्स बाडी ने 22 मई को दिल्ली में गृह मंत्रालय की सब कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वाले अपने तीन सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी। बैठक में हिस्सा लेने वाले लेह अपेक्स बाडी के तीन सदस्यों में सह अध्यक्ष छेरिंग दोरजे, जोधपुर जेल से हाल में ही में रिहा किए सोनम व लद्दाख गोंपा एसोसिएशन के प्रधान दोरजे स्टेंजिन शामिल हैं। दिल्ली में सब कमेटी की बैठक शुक्रवार शाम चार बजे होगी। दूसरी ओर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष कमर अली अखून के निधन के बाद अब गुलाम रसूल को उनकी जगह पर सब कमेटी में लाया है। वह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह अध्यक्ष असगर अली करबलई व सज्जाद कारगिली के साथ सब कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे।

अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ लगे पोस्टर, सांसद केएल शर्मा पर टिप्पणी

जासं, अमेठी

- **भाजपा ने कहा, स्थानीय जनता की आवाज हैं पोस्टर**
- **कांग्रेस ने बताया, हताशा और निराशा का परिणाम**

अमेठी रेलवे स्टेशन के पास लगा पोस्टर : जागरण

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन पर बुधवार को अमेठी में राजनीतिक माहौल गरमा गया। कई जगह सांसद किशोरी लाल शर्मा को निशाना बनाने वाले पोस्टर लगे दिखे। कांग्रेस कार्यालय, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड और मुंशीगंज में संजय गांधी अस्पताल के बाहर सहित कई स्थानों पर लगाए गए इन पोस्टरों में कांग्रेस सांसद के काम-काज पर सवाल उठाए गए हैं और उनके कार्यकाल की तुलना पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति इरानी से की गई है।

पोस्टरों पर मुख्य रूप से लिखा गया है- "दो साल किशोरी तुमने लाल क्या किया?" इसके जरिये सांसद बनने के बाद उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का हिसाब मांगा गया है।

एक पोस्टर में आरोप लगाया गया है कि सांसद निधि से केवल एक स्कूल बस दी गई, वह भी एक कांग्रेस नेता के निजी विद्यालय को आवंटित कर दी गई। इसके अलावा, एक एंबुलेंस को भी किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में सेवा में लगाए जाने का उल्लेख किया गया है।

वहीं, कुछ अन्य पोस्टरों में वर्तमान सांसद किशोरी लाल शर्मा के दो वर्ष के कार्यकाल की तुलना पूर्व सांसद स्मृति इरानी के पांच वर्ष के कार्यकाल से की गई है। इसमें पूर्व भाजपा सांसद के समय हुए विकास कार्यों का हवाला देते हुए मौजूदा सांसद की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए गए हैं।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने इन पोस्टरों को भाजपा की हताशा और निराशा का परिणाम बताया। कांग्रेस नेता शेष नाथ सिंह चुन्नू ने कहा कि भाजपा अमेठी में कांग्रेस की बढ़ती ताकत को देखकर परेशान है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि ये पोस्टर अमेठी की जनता की आवाज और भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने दावा किया कि दीदी स्मृति द्वारा किए गए विकास कार्य कांग्रेस 70 साल में भी नहीं कर सकी।

प्रतिक्रिया

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद, आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले अभिजीत डिपके ने बनाई पार्टी

इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड कर रही 'काकरोच जनता पार्टी'

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों 'काकरोच जनता पार्टी' की जमकर चर्चा हो रही है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद मचे राजनीतिक विवाद और युवाओं के गुस्से से शुरू हुई यह आनलाइन मुहिम अब इंटरनेट पर बड़ा ट्रेंड बन चुकी है। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इससे लोग जुड़ चुके हैं।

दरअसल, यह ट्रेंड उस वक्त शुरू हुआ, जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले हफ्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान काकरोच का जिक्र किया। उन्होंने टिप्पणी की थी कि कुछ युवा काकरोच जैसे होते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे मीडिया, इंटरनेट मीडिया या आरटीआइ एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। हंगामे के बाद हालांकि अगले दिन सीजेआइ सफाई में कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा, 'मुझे दुख है कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया और इसे देश के युवाओं पर हमला बताकर दिखाया'। लेकिन इंटरनेट पर कई यूजर्स ने युवाओं, बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसी माहौल में 'काकरोच जनता पार्टी' नाम से एक डिजिटल आंदोलन शुरू हुआ, जिसने मीम्स, व्यंग्य और राजनीतिक नाराजगी को मिलाकर इंटरनेट मीडिया पर तेजी से पकड़ बना ली है।

पार्टी ने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, जो व्यंग्य और गंभीर राजनीतिक मांगों का मिश्रण है। इसमें कैबिनेट में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध, सेवानिवृत्ति के बाद जजों को राज्यसभा पद न देने की मांग, चुनावों में वैध वोट हटाने पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। काकरोच जनता पार्टी के इंटरनेट मीडिया पर पांच दिन में लाखों फालोअर हो गए हैं।

5 दिन में काकरोच जनता पार्टी के इंटरनेट मीडिया पर लाखों फालोअर हो गए

प्रतीकात्मक

किसने शुरू किया अभियान

अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे 30 साल के अभिजीत डिपके ने इस अभियान की शुरुआत की। वह 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की इंटरनेट मीडिया टीम के साथ वालंटियर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 16 मई को एक्स पर एक गूगल फार्म शेयर कर लोगों को पार्टी से जुड़ने का न्योता दिया था। पार्टी के अनुसार सदस्य बनने के लिए आपको होना चाहिए. बेरोजगार, आलसी, हमेशा आनलाइन रहने वाला और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत या गुस्सा जाहिर करने में सक्षम। इंटरनेट कल्चर के जरिये अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है।

क्या है काकरोच जनता पार्टी

काकरोच जनता पार्टी एक आनलाइन राजनीतिक व्यंग्य (सटायर) समूह है, जिसे आम लोगों, खासकर युवाओं की नाराजगी और सिस्टम से निराशा को आवाज देने के लिए बनाया गया बताया जा रहा है। इसका टैगलाइन है-वायस आफ लेजी एंड अनएप्लाइड यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज।

विस परिसर में धरना प्रदर्शन से तृकां के आधे से ज्यादा विधायक रहे नदारद

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- **चुनाव बाद हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ तृणमूल का धरना महज आधे घंटे में हुआ समाप्त**

विधानसभा चुनाव में करारी हार के पश्चात बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के बाद राज्य की नई भाजपा सरकार के खिलाफ बंगाल विधानसभा परिसर में तृणमूल द्वारा बुधवार को आयोजित पहला बड़ा धरना प्रदर्शन ही सवालों के घेरे में आ गया। चुनाव नतीजों के बाद राज्यभर में कथित राजनीतिक हिंसा, नई सरकार की बुलडोजर कार्रवाई और रेलवे भूमि एवं स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों से फेरीवालों को कथित तौर पर जबरन हटाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा परिसर में डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के सामने आयोजित पार्टी के धरना-प्रदर्शन से तृणमूल के नवनिर्वाचित 80 में 46 विधायक गैरहाजिर रहे। मालूम हो कि एक दिन पहले तृणमूल सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आयोजित पार्टी विधायकों की बैठक से भी 15 विधायक गैरहाजिर रहे थे।

आधे से अधिक विधायकों की गैरहाजिरी ने पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायकों की अनुपस्थिति के बीच तृणमूल का धरना महज आधे घंटे में समाप्त हो गया। धरना प्रदर्शन में तृणमूल विधायक दल के नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय, पूर्व मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

2013 से अब तक बीएचयू के 60 शोध पत्रों में गड़बड़ी मिली है। ये शोध पत्र विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों, साहित्यिक चोरी विरोधी नीतियों और डेटा सत्यापन की कसौटी पर खरे नहीं उतरे।

नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा में इंटरनेट मीडिया पर भी रहेगी चौकस नजर

शिक्षा मंत्री प्रधान ने केंद्रीय सुरक्षा और इंटेलीजेंस एजेंसियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

गलत जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से संबंधित नीट-यूजी की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को फुलप्रूफ बनाने के लिए इस बार केंद्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस बार मोर्चा संभालेंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को परीक्षा से जुड़े सुरक्षा इंतजामों को लेकर इन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि तीन मई को आयोजित नीट-यूजी को पेपर लीक के कारण रद कर दिया गया था।

प्रधान ने कहा कि परीक्षा को सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के साथ-साथ छात्रों को गुमराह होने से बचाना और लोगों का भरोसा बनाए रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने एनटीए परीक्षा से जुड़ी कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सख्ती से निपटने और फेक इंटरनेट अकाउंट को बंद करने के निर्देश भी दिए। प्रधान ने बड़े इंटरनेट प्लेटफार्म जैसे मेटा, गूगल और टेलीग्राम के प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक भी की और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी गलत जानकारी के बढ़ते फैलाव को रोकने के निर्देश दिए। उन्हें अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरतने को कहा।

शिक्षा मंत्रालय व एनटीए के अधिकारियों ने एक ब्योरा भी पेश किया है, जिसमें बताया गया कि बड़ी परीक्षाओं से पहले कुछ ऐसे चैनल है जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इन पर गलत पेपर लीक के दावे और बिना जांच-परख के झूठी जानकारी फैलाई जाती है। इससे छात्र व अभिभावकों में घबराहट, चिंता और भ्रम पैदा होता है। इसका पूरा गिरोह है। प्रधान ने इससे निपटने के लिए शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी।

गौरतलब है कि नीट-यूजी पेपर लीक के बाद उठे सवालों के बीच एनटीए में डा. राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए चार वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती दी गई है, इनमें दो अधिकारी संयुक्त सचिव और दो निदेशक स्तर के हैं।

नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा के सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एएनआइ

नीट पेपर लीक मामले में पांच आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने सीबीआइ द्वारा जांच किए जा रहे नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को पांच आरोपितों को दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और एक आरोपित की सीबीआइ हिरासत बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सीबीआइ की याचिका स्वीकार करते हुए आरोपित मांगीलाल खटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। एक अन्य आरोपित शुभम खैरनार की सीबीआइ हिरासत भी पांच दिन के लिए बढ़ा दी, ताकि एजेंसी आगे पूछताछ कर सके।

मुर्शिदाबाद में तीन साल में बना कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसी का आलीशान 'महल'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: मुर्शिदाबाद के कांदी इलाके में कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसी (उपायुक्त) शांतनु सिन्हा विश्वास के पैतृक घर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जहां तीन वर्ष पहले तक एक जर्जर ईंट का छोटा घर था, वहां अब आलीशान महल बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल शांतनु ईडी की हिरासत में हैं। जमीन कब्जा, वसूली और अन्य आरोपों की जांच में हाल में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह भवन अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। घर के प्रवेश द्वार पर सिंह की प्रतिमा लगी है और अंदर भव्य लकड़ी के दरवाजे हैं। लोगों का दावा है कि पूरे भवन में इटालियन मार्बल लगा हुआ है तथा बड़े-बड़े झाड़फानूस और महंगे फर्नीचर इसकी भव्यता बढ़ाते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, इस भवन में मखमली चेस्टरफील्ड सोफा सेट, सागौन और महोगनी लकड़ी के महंगे फर्नीचर लगाए गए हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले तीन वर्षों में धीरे-धीरे यह तैयार हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि शांतनु कभी-कभी यहां आते थे। वर्तमान में इस घर में उनकी बहन और कांदी नगरपालिका की तृणमूल उपाध्यक्ष गौरी सिंह विश्वास रहती थीं। फिलहाल घर पर ताला लटका है और उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है।

सांस्कृतिक समागम में उठेगा जनजातियों के मतांतरण का मुद्दा

संजय कुमार • जागरण

- दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को होगा आयोजन, अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि
- बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से पहुंचेंगे हजारों लोग

रांची: बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई को आयोजित होने वाले जनजाति सांस्कृतिक समागम में देश के विभिन्न राज्यों से जनजाति समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से किया गया है। समागम को बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। बिहार-झारखंड से भी बड़ी संख्या में आदिवासी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। इनके पहुंचने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, जो अलग-अलग स्टेशनों से यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

इस आयोजन के माध्यम से लोग जनजातियों के अस्तित्व, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए उलगुलान आंदोलन के बारे में जानेंगे। साथ ही मतांतरण के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष, उनकी ओर से चलाए गए बिरसाइत धर्म और उनके जीवन से जुड़ी अन्य जानकारियों की भी झलक कार्यक्रम में दिखेगी।

जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजकिशोर हांसदा ने बताया कि रविवार 24 मई को दिल्ली में समागम शुरू होने से पूर्व तीन बजे पांच स्थानों से विशेष शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। राजघाट चौक, रामलीला मैदान, अजमेरी गेट चौक, कुदशिला बाग और श्यामगिरि मंदिर से निकलने वाली इन शोभायात्राओं में जनजाति समाज के लोग पारंपरिक वस्त्रों एवं वाद्य यंत्रों के साथ शामिल होंगे।

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग प्रांतों से 46 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेनों से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली के 80 विद्यालयों में आवास तथा भोजन की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के लोग बस, ट्रेन व अन्य वाहनों से भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक छत्तीसगढ़ के गणेशराम भगत करेंगे।

झारखंड से 4500 लोगों ने कराया है पंजीकरण : जनजाति सुरक्षा मंच के क्षेत्र संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि समागम में जाने के लिए झारखंड से जनजाति समाज के 4,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

बकरीद से पहले जमीयत की बड़ी मांग, गाय को मिले राष्ट्रीय पशु का दर्जा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कुर्बानी के त्योहार ईद उल अजहा (बकरीद) के पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग रखी है। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश के मुसलमानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उन्हें खुशी होगी और गोवंशी के नाम पर होने वाली भीड़ की हिंसा और हत्या की घटनाएं रुकेंगी।

बकरीद 28 मई को है, जिस दिन अन्य पशुओं के अलावा गोवंशी की भी कुर्बानी के मामले सामने आते हैं। इस पर भारी विवाद होता है। कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा की भी घटनाएं होती हैं। जारी बयान में मदनी ने कहा कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती, बल्कि उसे मां का दर्जा देती है, तब ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बच रही है? यह मांग तो कई साधु-संत भी लंबे समय से कर रहे हैं।

अरशद मदनी।

मौलाना अरशद मदनी बोले- देश के मुसलमानों को नहीं होगी इस पर कोई आपत्ति

गाय की कुर्बानी से बचें मुस्लिम

मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद लगातार मुसलमानों को यह सलाह देती रही है कि ऐसा कोई काम न किया जाए, जिससे दूसरों धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि बहुधार्मिक समाज में आपसी सम्मान के साथ रहने की शिक्षा देता है। जमीयत अपने मंच से लगातार मुसलमानों को यह संदेश देती रही है कि गाय जैसे पशुओं की कुर्बानी से बचा जाए। ताकि समाज में सौहार्द बना रहे।

तृणमूल सांसद काकोली घोष को केंद्र की 'वाई' श्रेणी सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तिदार को केंद्र सरकार ने 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। काकोली की सुरक्षा में सीआइएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं और 19 मई से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है।

राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में अपने संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से काकोली को हटा दिया था। उनकी जगह फिर से कल्याण बंद्योपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पद से हटाए जाने के बाद काकोली ने इंटरनेट मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, 1976 से पहचान, 1984 से साथ की शुरुआत। चार दशक की निष्ठा का आज पुरस्कार मिला।

बलिया से खरीदी गई थी चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार

जागरण संवाददाता, बलिया

- इंजन और चेसी नंबर के आधार पर वाहन मालिक के घर पहुंची सीबीआइ
- आरोपित राजकुमार के साथ ज्ञानेंद्र की तस्वीर मिलने से जांच हुई आसान

बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में इस्तेमाल की गई सिल्वर रंग की निसान माइक्रा कार बलिया के बालू व्यवसायी जितेंद्र सिंह की निकली। पूछताछ में उसने बताया कि कार घटना से पांच दिन पहले एक मई को शीतलदवनी के ज्ञानेंद्र सिंह को बेची थी। छह मई की रात कोलकाता में चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को मौके से एक कार मिली थी, जिसका इंजन व चेसी नंबर खुरचा गया था। प्रारंभ में तो यह कार सिलीगुड़ी के जेम्स विलियम्स के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही थी, लेकिन कई स्तर पर जांच के बाद इसकी डोर बलिया के जितेंद्र से जुड़ गई।

19 मई को सीबीआइ अधिकारियों ने जितेंद्र सिंह से उनके घर फुलवरिया पहुंचकर पूछताछ की। उसने बताया कि वर्ष 2025 में यह कार हुसैनाबाद गांव के एक व्यक्ति से 35 हजार में खरीदी थी। 30 अप्रैल को पूर्व परिचित दीपक और ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु ने कार खरीदने के लिए उनसे संपर्क किया। एक मई को ही कार 50 हजार में ज्ञानेंद्र को बेच दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, निसान माइक्रा कार 16 साल पुरानी है। जितेंद्र सिंह से पूछताछ के बाद सीबीआइ ज्ञानेंद्र सिंह के घर पहुंची, लेकिन वह फरार मिला।

चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में अब तक पांच आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गत 18 मई को बलिया के रतोपुर गांव के राजकुमार सिंह को मुजफ्फरनगर से सीबीआइ ने पकड़ा। वहीं, वाराणसी से गाजीपुर के विनय राय को 19 मई को गिरफ्तार किया गया। राजकुमार व ज्ञानेंद्र सिंह की तस्वीरें एक साथ मिलने के बाद आरोपितों तक सीबीआइ के पहुंचने का रास्ता आसान हो गया।

बांसडीह रोड क्षेत्र के फुलवरिया निवासी जितेंद्र सिंह। स्रोत- पुलिस

राजकुमार सिंह (बाएं) के साथ ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु। स्रोत- इंटरनेट मीडिया

कानपुर आइआइटी निदेशक को मिला लंदन की रायल सोसायटी का फेलो सम्मान

जासं, कानपुर : आइआइटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल को गणित व कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'फेलो आफ द रायल सोसायटी (एफआरएस)' के लिए चुना गया है।

मणीन्द्र अग्रवाल।

लंदन की रायल सोसाइटी का फेलो (एफआरएस) सम्मान दुनियाभर के उन विशिष्ट विज्ञानियों, इंजीनियरों व तकनीकी विशेषज्ञों को दिया जाता है, जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व क्रांतिकारी योगदान दिया हो। वैश्विक स्तर पर इस सम्मान को उत्कृष्ट शोध, नवाचार व बौद्धिक क्षमता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है।

प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल अब दुनिया के उन चुनिंदा विज्ञानियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांतों व शोध कार्यों से विज्ञान और तकनीक को नई दिशा दी है। इससे देश का मान बढ़ा है।

बीएसएफ की महिला टीम की एवरेस्ट फतह के बाद वंदे मातरम् गाने की योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : माउंट एवरेस्ट पर फतह पाने के लिए निकली बीएसएफ की महिला पर्वतारोही की टीम की चोटी पर पहुंचकर वंदे मातरम् गाने की योजना है। पर्वतारोहियों को छह अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी से उनके पहले अभियान के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। महिला टीम की चार सदस्यों ने अनुकूलन चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वर्तमान में वे साउथ कोल में तैनात हैं, जो एवरेस्ट शिखर से पहले अंतिम पड़ाव शिविर है।

बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया, मौसम अनुकूल रहने पर अंतिम शिखर चढ़ाई 21 मई की सुबह निर्धारित है। देशभक्ति का भाव जोड़ने के लिए शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई के बाद दल 'वंदे मातरम्' गाएगा।

8,849 मीटर ऊंचे शिखर पर महिलाओं का पहला अभियान और राष्ट्रगान, ये दोनों ही आयोजन विशेष महत्व रखते हैं। यह योजना बीएसएफ की हीरक जयंती और 2026 में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाई गई है।

350 रुपये में किशोरों को अश्लील वीडियो बेचता था इंजीनियर

जागरण संवाददाता, हरदोई

- टेलीग्राम-इंस्टाग्राम पर 21 चैनल बनाकर चला रहा था बड़ा नेटवर्क, हजारों नाबालिग जुड़े
- साइबर पुलिस की जांच में बैंक खातों से करोड़ों का लेनदेन और डिजिटल कारोबार उजागर

साइबर अपराध का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका एक युवक इंटरनेट के जरिये अश्लील सामग्री का बड़ा नेटवर्क चलाकर 1.20 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करता पाया गया। आरोपित टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर 21 चैनल बनाकर नाबालिगों को निशाना बना रहा था और सब्सक्रिप्शन के नाम पर प्रति वीडियो 350 रुपये वसूल रहा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित की पहचान प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र के न्यू मार्केट शिवाला निवासी विकास सिंह के रूप में हुई है। वह वर्ष 2020 में प्रयागराज के यूनाइटेड कालेज से बीटेक करने के बाद साइबर अपराध की दुनिया में उतर गया। उसने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर 21 चैनल बनाए, जिनसे लगभग सात हजार से अधिक लोग जुड़े हुए थे। इन चैनलों पर बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो शेयर किए जाते थे, जिनका मुख्य निशाना अवयस्क थे। आरोपित अपने चैनलों पर सब्सक्रिप्शन माडल के जरिये कमाई करता था। एक व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी के तहत एक सब्सक्राइबर बनाकर पूरे सिस्टम को समझा।

जांच में पता चला कि वीडियो देखने के लिए 350 रुपये प्रति माह, 450 रुपये छह माह और 600 रुपये एक वर्ष के सब्सक्रिप्शन पैकेज उपलब्ध थे। भुगतान के लिए जिस बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा था, वह एचडीएफसी बैंक में विकास सिंह के नाम से दर्ज पाया गया। इसी खाते के माध्यम से पुलिस आरोपित तक पहुंची।

ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल

- सीबीआइ जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताई सहमति

शादी के पांच माह बाद अपनी ससुराल में मृत पाई गई नोएडा की ट्विशा शर्मा के स्वजन की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अपील भोपाल स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अनुदिता गुप्ता की कोर्ट ने खारिज कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मप्र के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सीबीआइ जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने की सहमति जताई है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्विशा का पोस्टमार्टम भोपाल स्थित एम्स जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में किया गया था। अब तक पुलिस ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 197 के तहत स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं। भोपाल कोर्ट दिल्ली स्थित एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश नहीं दे सकती।

इस बीच ट्विशा शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह पूर्व सेना अधिकारियों और जवानों द्वारा भोपाल में बाइक रैली निकाली गई। कोर्ट का निर्णय आने से पहले ट्विशा के स्वजन मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने मामले की सीबीआइ जांच, गिरिबाला की जमानत याचिका खारिज कराने, पति समर्थ की तत्काल गिरफ्तारी, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने और पार्थिव शरीर के स्थानांतरण के लिए लाजिस्टिक सहायता की मांग की।

मुख्यमंत्री ने इनमें से चार बिंदुओं पर सहमति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका कोर्ट का मामला है।

बता दें कि भोपाल स्थित ससुराल में 33 वर्ष की ट्विशा शर्मा 12 मई की रात्रि को फांसी के फंदे से लटकी पाई गई थी। ट्विशा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू थी। ट्विशा के स्वजन ने उसके पति समर्थ व सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम में ट्विशा के सिर, कान और हाथ पर चोट के निशान की पुष्टि हुई थी। डाक्टरों ने साफ किया था कि ये चोटें मौत से पहले की थीं जो किसी ठोस वस्तु (ब्लंट आब्जेक्ट) से पहुंचाई गई प्रतीत हो रही थीं।

इस मामले से जुड़े दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को जिला कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इधर पुलिस ने फरार पति समर्थ पर इनाम 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया है।

पुलिस को शव सुरक्षित रखने का आदेश

कोर्ट ने शहर के कटारा हिल्स थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि शव को मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर किसी बड़े चिकित्सा संस्थान में माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी आवश्यकता की स्थिति में साक्ष्य प्रभावित न हों।

ट्विशा शर्मा के स्वजन ने बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से भेंट की। एएनआइ

चिंताजनक

वर्ष 2022 से 2025 के बीच आए मामले, 2013 से अब तक कुल 60 शोध पत्रों में सामने आई गड़बड़ी, उच्च स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयासों के बीच शोधपत्र तैयार करने में अनियमितता

साहित्यिक चोरी पर कार्रवाई, बीएचयू के 19 शोध पत्र खारिज

जागरण संवाददाता, वाराणसी

उच्च स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता और अकादमिक शुचिता बनाए रखने के प्रयासों के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध पत्र तैयार करने में गंभीर अनियमितता की गई। पिछले चार वर्षों में विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों और शोधकर्ताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में जमा किए गए 19 शोध पत्र वापस किए गए। वर्ष 2022 से 2025 के बीच आए ये शोध पत्र विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों, साहित्यिक चोरी विरोधी नीतियों और डेटा सत्यापन की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। वर्ष 2013 से अब तक 60 शोध पत्रों में गड़बड़ी मिली है।

विश्वविद्यालय की आंतरिक मूल्यांकन समिति और पीयर-रिव्यू टीमों ने गहन जांच के बाद इन शोध पत्रों में पूरी तरह से सुधार के आदेश दिए हैं, जिनमें से तीन मामले पिछले साल के ही हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ शोध पत्रों में तय सीमा से अधिक साहित्यिक व बौद्धिक चोरी की गई, जबकि कुछ अन्य मामलों में अनुसंधान के दौरान इस्तेमाल किए गए वैज्ञानिक डेटा, तस्वीरों और निष्कर्षों में भारी विसंगतियां देखी गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि वैश्विक मंचों पर संस्थान की छवि धूमिल न हो, इसके लिए आने वाले समय में भी ऐसे त्रुटिपूर्ण या साहित्यिक चोरी वाले शोध कार्यों पर यह नीति अपनाई जाएगी।

आइएमएस बीएचयू में आथरशिप विवाद और डेटा गड़बड़ी: सर सुंदरलाल अस्पताल के स्त्री व प्रसूति रोग विभाग के डाक्टरों के बीच अक्टूबर 2022 में शोध पत्र को लेकर बड़ा विवाद हुआ। शोधकर्ताओं के बीच आपसी सहमति न बनने और डेटा में गड़बड़ी के बाद जर्नल क्युरियस ने प्रसवोत्तर रक्तस्राव पर आधारित शोध पत्र को वापस कर दिया था। यह शोध उत्तर भारत के एक टर्शियरी केयर अस्पताल में पीपीएच इमरजेंसी केयर के 'बंडल अप्रोच' से जुड़ा था।

आइआइटी-बीएचयू संयुक्त रिसर्च में तस्वीरों की हेरफेर: स्कूल आफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और विज्ञान संकाय के शोधकर्ताओं द्वारा अप्रैल 2025 में तैयार किए गए मेडिकल रिसर्च पेपर को पब्लिशर एल्सेवियर के 'इंटरनेशनल जर्नल आफ बायोलाजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स' ने निरस्त कर दिया। यह शोध गंभीर रूप से जलने के घावों को ठीक करने के लिए एक खास 'थ्रीडी-नैनोफाइब्रोपोरस मैट्रिक्स' के मूल्यांकन पर आधारित था। जर्नल प्रबंधन को मिली शिकायतों के बाद आंतरिक जांच में पाया गया कि डेटा और इमेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

फाइल फोटो

मनी लांड्रिंग मामले में सात दिन के रिमांड पर आप नेता दीपक सिंगला

जागरण संवाददाता, पंचकूला: मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के आप नेता दीपक सिंगला को ईडी ने बुधवार को पंचकूला स्थित विशेष अदालत में पेश किया। सुनवाई लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें ईडी ने सिंगला के लिए 10 दिन के रिमांड की मांग की। अदालत ने अंततः सिंगला को सात दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

सिंगला को बुधवार सुबह 11:45 बजे सेंट्रल जेल अंबाला से अदालत लाया गया। यह मामला 155 करोड़ रुपये के बैंक फ्राड से संबंधित है। ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स से कथित तौर पर 155.21 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में 10 अगस्त 2017 को बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर राजबीर सिंह धनखड़ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह मामला कथित बैंक फ्राड से जुड़े मनी लांड्रिंग नेटवर्क की जांच से संबंधित है।

हरभजन की सुरक्षा मामले में पंजाब सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह की सुरक्षा से जुड़े मामले में पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अदालत पहले ही स्पष्ट आदेश दे चुकी थी, तब फिर समय मांगने का क्या औचित्य है। अदालत ने टिप्पणी की कि यह रवैया मामले के प्रति गंभीरता की कमी दर्शाता है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को अंतिम अवसर प्रदान किया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि विस्तृत जवाब अगले बुधवार तक हर हाल में दाखिल किया जाए। चेतावनी भी दी कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो एडीजीपी सिक्योरिटी को स्वयं हाई कोर्ट में उपस्थित होकर इसका जवाब देना होगा। गौरतलब है कि हरभजन ने याचिका में दावा किया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने की सार्वजनिक घोषणा के तुरंत बाद उनकी सुरक्षा बिना किसी नए खतरे के आकलन, नोटिस या सुनवाई के हटा दी गई।

हरभजन सिंह। फाइल

76 साइबर अपराध मामलों में हैदराबाद पुलिस ने देशव्यापी 'घोस्ट सिम कार्ड' नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 66 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में धोखाधड़ी से जुड़ी 101.87 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार, 21 मई, 2026

बंगाल में 'पुशबैक' कानून लागू, घुसपैठियों को अब डिपोर्ट करेगी शुभेंदु सरकार

बड़ा फैसला ▶ बीएसएफ को फेंसिंग के लिए सौंपी 27 किमी क्षेत्र की 75 एकड़ जमीन

नई सरकार का सख्त संदेश– 'तुष्टीकरण नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सूबे की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला किया है। बुधवार को नवान्न (सचिवालय) में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आला अधिकारियों के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में 'पुशबैक' कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा कर दी। इसके तहत अब सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों को राज्य पुलिस सीधे गिरफ्तार कर बीएसएफ के हवाले करेगी, जिसके बाद उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट (निर्वासित) किया जाएगा।

तुष्टीकरण की राजनीति पर कड़ा प्रहार : मुख्यमंत्री शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत सरकार ने 14 मई 2025 को ही घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने की गाइडलाइन भेजी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने तुष्टीकरण के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के दिन खत्म हो चुके हैं। पिछले कुछ समय में लव जिहाद, जबरन मतांतरण और महिला सुरक्षा से जुड़े जितने भी बड़े अपराध हुए हैं, उनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संलिप्तता रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके बाद अब आने वाले दिनों में सीमा क्षेत्रों में पुलिस-बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई और तेज होने के संकेत हैं।

दिए गए तीन मंत्र- डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट : राज्य सरकार ने सीमावर्ती सभी थानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इस प्रक्रिया को 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' के तीन सूत्रों पर चलाया जाएगा। भारत-बांग्लादेश की 2200 किलोमीटर लंबी बंगाल सीमा में से करीब 569 किलोमीटर पर जमीन नहीं मिलने की वजह से कंटीले तार (बाड़) नहीं लग पाए हैं। इस बाधा को घोषणा के महज दस दिनों के भीतर ही दूर करते हुए शुभेंदु सरकार ने बुधवार को ही बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए शुरुआती 27 किलोमीटर इलाके में फेंसिंग के लिए 75 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को पूर्व में घोषित 45 दिनों के भीतर बाकी जमीन सौंपने का भी निर्देश दिया है।

कोलकाता में बुधवार को बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार को जमीन के दस्तावेज सौंपते मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल। एएनआइ

सीएए के तहत शरणार्थियों को पूर्ण सुरक्षा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर मतुआ और अन्य हिंदू समुदायों के मन में बैठी शंकाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। स्पष्ट किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी। पुलिस उन्हें परेशान या गिरफ्तार नहीं करेगी।

बदरीनाथ से लौट रहे चार्टर हेलीकाप्टर की टिहरी में आपात लैंडिंग, सभी सवार सुरक्षित

जागरण संवाददाता, नई टिहरी

- महिला पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, एक ही परिवार के छह सदस्य थे सवार
- उतरते समय विद्युत लाइन के संपर्क में आया हेलीकाप्टर

बदरीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर देहरादून जा रहे चार्टर हेलीकाप्टर की टिहरी में एक खेत में आपात लैंडिंग की गई। उतरते समय हेलीकाप्टर का पिछला हिस्सा घरेलू विद्युत लाइन (एलटी) के संपर्क में आ गया। इस दौरान हेलीकाप्टर घिसटता हुआ आगे बढ़ा तो उसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, महिला पायलट की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। हेलीकाप्टर में एक ही परिवार के छह सदस्य सवार थे। पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित हैं।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) और हेली सेवा संचालित कर रही ट्रांस भारत एविएशन कंपनी आपात लैंडिंग का कारण वायुमंडल में तेज हवा के चलते बने दबाव (डाउन ड्रिफ्ट) को मान रही है। पहाड़ों में तेज हवा चलने के कारण हेलीकाप्टर पर नीचे की ओर दबाव बढ़ता है, जिसे डाउन ड्रिफ्ट कहते हैं।

चारधाम यात्रा रूट पर संचालित इस हेलीकाप्टर ने सुबह 7:53 बजे बदरीनाथ से उड़ान भरी थी। टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र के अंतर्गत नवागांव-सत्यों के ऊपर से गुजरते समय डाउन ड्रिफ्ट का अहसास होने पर करीब 8:45 बजे पायलट ने सुरक्षित आपात लैंडिंग का निर्णय लिया। लैंडिंग के दौरान हेलीकाप्टर विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। इससे उसका संतुलन गड़बड़ा गया। इस दौरान पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ। हालांकि, पायलट अनुपम चौधरी ने सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। इसके बाद सभी यात्रियों को टैक्सी से देहरादून भेजा गया। टिहरी के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ से घटना की जानकारी ली। सीईओ ने बताया कि हेलीकाप्टर के रखरखाव व तकनीकी निरीक्षण के लिए कंपनी की मेंटेनेंस टीम को मौके पर बुलाया गया है।

चारधाम से लौट रहा था दिल्ली का परिवार : हेलीकाप्टर में पंजाबी बाग, नई दिल्ली का सूरी परिवार सवार था, जो चारधाम यात्रा से लौट रहा था। इनमें 64 वर्षीय राज सूरी उनका बड़ा बेटा साहिल, बहू भूमि, छोटा बेटा पारथ, बहू हिमांशी और पोती निष्का शामिल हैं।

निर्धारित रूट बदलना पड़ा : ट्रांस एविएशन कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ के अनुसार, हेलीकाप्टर पहले बदरीनाथ धाम से यात्रियों को लेकर गुप्तकाशी जा रहा था, लेकिन किसी वीआइपी मूवमेंट के कारण पायलट को सीधे देहरादून जाने का मैसेज मिला। गुप्तकाशी नहीं रुककर देहरादून जाने के लिए पायलट को अपना निर्धारित रूट बदलना पड़ा।

महिला पायलट की सराहना : यात्रियों के अनुसार विद्युत लाइन के संपर्क में आने पर हेलीकाप्टर हिचकोले खाने लगा और अनियंत्रित होने लगा, लेकिन महिला पायलट अनुपम चौधरी ने सूझबूझ का परिचय दिया। वह तार के साथ ही हेलीकाप्टर को संभालते हुए आगे बढ़ीं। इसके बाद सत्यो-सकलाना के खेत में हेलीकाप्टर की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। यात्रियों ने महिला पायलट की सराहना की है।

टिहरी के सत्यों-सकलाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद क्षतिग्रस्त हेलीकाप्टर और टूटा बिजली का तार। साभार-पुलिस विभाग

जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर गिराई हेरोइन की खेप

जागरण संवाददाता, जम्मू

- सीमांत क्षेत्र अरनिया में खेत में पड़े मिले तीन किलो हेरोइन के पैकेट
- एफएसएल की प्रारंभिक जांच में हेरोइन की पुष्टि, तलाशी अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर में नशा विरोधी अभियान के दौरान जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई से हताश हो चुका पाकिस्तान अब भी सुधर नहीं रहा है। बुधवार को जम्मू जिले के सीमांत क्षेत्र अरनिया में खेत से हेरोइन की खेप बरामद की गई। यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये भारतीय सीमा में गिराई गई थी। प्रारंभिक जांच में पैकेट में मादक पदार्थ हेरोइन होने की पुष्टि हुई है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम ने जांच शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षाबल ने गांव में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार करीब तीन किलो हेरोइन को छह पैकेट में बांधा गया था। दूसरी ओर पुलिस उन तस्करों की तलाश भी करने में जुट गई, जिन्होंने इस हेरोइन को लेने आना था।

सुबह छह बजे बहादुरपुर निवासी किसान बोध राज सुबह खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। इसी दौरान उसकी नजर खेत में पड़े पैकेट पर पड़ी। किसान ने तुरंत इसकी सूचना बिश्नाह पुलिस को दी। जांच में पाया कि पैकेट को उसी तरीके से सील किया था, जैसा सीमापार ड्रोन से गिराई जाने वाली खेपों में किया जाता है। बीते कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि सीमा पार से ड्रोन के जरिये नशे की खेप भेजी जाएगी।

बिश्नाह के सीमावर्ती गांव बहादुर पुर के खेत में पड़े हीरोइन के पैकेट को देखते लोग और आस पास पहरा देते पुलिस व आर्मी के जवान।

देहरादून के अस्पताल में एसी के धमाके से आइसीयू में लगी आग, एक मरीज की मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून

- नवजात समेत 10 घायल, शीशे तोड़ मरीजों को निकाला गया बाहर
- जिलाधिकारी के आदेश पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू

दून का पैनेसिया अस्पताल बुधवार सुबह अचानक चीख-पुकार से गूंज उठा। अस्पताल के आइसीयू में एसी में धमाके के बाद आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरा वार्ड जहरीले धुएं से भर गया। आइसीयू में भर्ती 60 वर्षीय बीरवती धुएं के बीच जिंदगी की जंग हार गईं, जबकि नवजात समेत 10 मरीज घायल हो गए। बचाव अभियान में जुटे तीन पुलिसकर्मी भी झुलस गए। जिला-प्रशासन ने अस्पताल सील कर घटना की मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी है।

सुबह 9:21 बजे फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली। फायर स्टेशन से टीम महज छह मिनट में मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आइसीयू धुएं से भर चुका था।

अस्पताल के भीतर अफरा-तफरी का माहौल था। मरीजों के स्वजन चीखते हुए बाहर भाग रहे थे और अंदर फंसे मरीज मदद के इंतजार में थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने जान जोखिम में डालकर राहत-बचाव अभियान शुरू किया।

देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में एसी फटने की घटना के बाद निरीक्षण करते एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल व अन्य पुलिस अधिकारी। जागरण

आइसीयू के शीशे तोड़े गए, ताकि धुआं बाहर निकल सके। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के सहारे मरीजों को बाहर लाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आइसीयू में भर्ती नवजात समेत पांच मरीजों को तत्काल नजदीकी कैलाश अस्पताल भेजा गया।

राहत-बचाव के दौरान कई पुलिसकर्मी धुएं और आग की चपेट में आ गए। एएसआइ नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बृजमोहन रावत और कांस्टेबल बृजमोहन कनवासी घायल हो गए। तीन मंजिला अस्पताल की बीच वाली मंजिल में स्थित आइसीयू में यह हादसा हुआ। ऐहतियातन पूरे अस्पताल को खाली करा दिया गया।

अस्पताल में कुल 11 मरीज भर्ती थे। इनमें पांच आइसीयू और छह सामान्य वार्ड में थे। आइसीयू के सभी मरीजों को कैलाश अस्पताल शिफ्ट किया गया। दो मरीजों को हालत सामान्य होने पर छुट्टी दे दी गई।

जेल में बंद लारेंस को डीएसपी ने बर्थडे गिफ्ट में भेजीं टोपियां व मुरब्बे

रोहित कुमार • जागरण

- वर्ष 2024 में डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने लारेंस के साथी राजवीर के हाथ भेजे थे गिफ्ट
- 2022 में संधू की ही निगरानी में खरड़ में सीआइए कार्यालय में हुआ था लारेंस का साक्षात्कार

चंडीगढ़: गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के जन्मदिन पर पंजाब पुलिस के एक डीएसपी की ओर से कथित तौर पर तोहफे में टोपियां, मुरब्बे का डिब्बा व अन्य उपहार पहुंचाए जाने के राजफाश ने पुलिस और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच संभावित गठजोड़ की बहस को फिर तेज कर दिया है। यह दावा ऐसे समय सामने आया है, जब लारेंस के विवादित टीवी साक्षात्कार मामले की जांच पहले से चल रही है। जांच एजेंसियों के रिकार्ड में आए नए बयान ने संकेत दिया है कि कुछ मामलों में पुलिस अधिकारियों और कुख्यात गैंगस्टरों के बीच संबंध सिर्फ पूछताछ या हिरासत तक सीमित नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क भी बने रहे।

यह राजफाश बिश्नोई गिरोह से जुड़े राजवीर सिंह उर्फ रवि राजगढ़ के बयान में हुआ है। जुलाई 2025 में आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार राजवीर ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि 10 फरवरी 2024 को लारेंस बिश्नोई ने उसे फोन कर मोहाली के फेज-7 स्थित डीएसपी कार्यालय से सामान लेने को कहा था। अगले दिन 11 फरवरी को लारेंस का जन्मदिन था। वह साथी सुपिंदर सिंह के साथ विमान से अहमदाबाद पहुंचा और साबरमती जेल में सामान पहुंचाया। बताया गया कि इस सामान में टोपियां, मुरब्बे का डिब्बा और अन्य उपहार शामिल थे। जांच में यह सामान पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू की ओर से भेजा गया बताया जा रहा है। गुरशेर सिंह संधू वही अधिकारी है, जिसे लारेंस के विवादित साक्षात्कार मामले में कथित भूमिका के कारण सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

खिलाड़ी से छेड़छाड़ के दोषी तीरंदाजी कोच को पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, सोनीपत: राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी से छेड़छाड़ के दोषी तीरंदाजी कोच कुलदीप कुमार वेदवान को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में हुए मामले में सजा के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अप्रैल, 2023 में सोनीपत स्थित स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया कैंपस में आयोजित यूथ चैंपियनशिप ट्रायल में भाग लेने आई थी। वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा स्टेडियम में तीरंदाजी का अभ्यास करती थी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को सोनीपत के अलग-अलग होटलों में ठहराया गया था। सात अप्रैल, 2023 की सुबह करीब चार बजे बागपत के गांव टीकरी का कोच कुलदीप कुमार वेदवान उसके होटल कमरे में पहुंच गया। उसने कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें कीं और पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। नींद खुली तो कोच से बचकर भागी।

नम आंखों से अंतिम विदाई, पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी
- उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने खंडूड़ी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित की

हरिद्वार में बुधवार को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की अंतिम विदाई यात्रा में पार्थिव शरीर को कंधा देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेनि) बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। हरिद्वार के खड़खड़ी श्मशान घाट पर राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना और पुलिस के जवानों ने गार्ड आफ आनर दिया। दिवंगत खडूड़ी के पुत्र मनीष खंडूड़ी ने मुखाग्नि दी। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिवंगत खंडूड़ी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बेहद भावुक रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास से लेकर भाजपा कार्यालय और फिर हरिद्वार में दिवंगत नेता खंडूड़ी की अंतिम विदाई यात्रा में शामिल हुए और उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। देहरादून से हरिद्वार तक लोगों ने पुष्पवर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

बिहार में मिड-डे मील खाने के बाद 60 बच्चे बीमार

जासं, नालंदा : बिहार में नालंदा जिले के मध्य विद्यालय कैला में बुधवार को मिड-डे मील खाने के बाद 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चने की सब्जी-चावल खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत होने लगी।

कई बच्चे स्कूल परिसर में ही बेहोश हो गए।नगरनौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में पहले से प्रसूताएं भर्ती होने के कारण वहां 25 बच्चों को रखा गया, जबकि 30 बच्चों का उपचार चंडी रेफरल अस्पताल में चल रहा है। एक छात्रा बिहारशरीफ माडल अस्पताल तथा चार अन्य बच्चों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

अस्पताल में भर्ती पांचवीं की छात्रा अमृता कुमारी ने बताया कि मिड-डे मील में परोसी गई चने की सब्जी में दवा जैसी संदिग्ध गोली दिखाई दे रही थी। छात्राओं ने आरोप लगाया कि भोजन परोसने से पहले शिक्षकों द्वारा स्वाद परीक्षण नहीं किया गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद शिक्षक अमरेश ने भी भोजन किया, जिसके बाद उन्हें भी चक्कर आने लगा और अस्पताल ले जाना पड़ा।

भोजशाला पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अब शुक्रवार पर नजर, धार प्रशासन अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार

- हाई कोर्ट के फैसले से पहले तक भोजशाला में शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच पढ़ी जाती रही है नमाज

धार। भोजशाला परिसर के अंदर उपस्थित श्रद्धालु। फाइल फोटो- नईदुनिया

लोगों से अपील है कि वे किसी भी अफवाह या बहकावे में न आएं और ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, जो कानून या कोर्ट के निर्देशों के विपरीत हो। - **सचिन शर्मा, एसपी, धार**

भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद शुक्रवार पर लोगों की नजर है। भोजशाला को मंदिर मानने के निर्णय के उपरांत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा वर्ष के 365 दिन निर्बाध पूजा की व्यवस्था लागू किए जाने के बाद धार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशीलता को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने बुधवार को एडवाइजरी जारी कर लोगों से शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। बता दें, निर्णय के पहले तक भोजशाला में शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज पढ़ी जाती रही है। अब नई परिस्थितियों में शुक्रवार को होने वाली गतिविधियों और प्रशासन की व्यवस्था पर सबकी नजर बनी हुई है।

अपील में यह स्पष्ट किया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश और निर्देश बाध्यकारी हैं, उनका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर, मंदिर पक्ष ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार को भी परिसर में महाआरती की जाएगी।

'भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्त बर्बाद न करें' : इस बीच, आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने भोजशाला मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने की अपील की है।

एक टीवी चैनल से चर्चा के दौरान गुलाम सरवर ने कहा कि अब यह बहस मायने नहीं रखती कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। एएसआइ अपनी जांच पूरी कर चुका है और हाई कोर्ट भी निर्णय सुना चुका है। कुछ मुस्लिम नेता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसा न करें। इससे परिणाम नहीं बदलेंगे। अब इसे यहीं समाप्त कर आगे बढ़ना चाहिए।

बिहार का मामला

एक दशक से तटबंध पर कट रही 143 परिवारों की जिंदगी

भरैन मुशहरी के 104 और चौकीया के 39 परिवार जी रहे विस्थापित जिंदगी, बीते साल जमीन का पर्चा तो मिला पर प्रशासनिक सुस्ती से अब तक कब्जा नहीं

अरुण कुमार राय • जागरण

कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) : कमला बलान नदी के कटाव से बिहार में दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के भरैन मुशहरी और चौकीया गांव के 143 विस्थापित परिवार पिछले 10 वर्षों से पश्चिमी तटबंध पर झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। आज तक न तो इनके पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था हो सकी और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकी हैं। सरकार और प्रशासन की उदासीनता से विस्थापित परिवारों में आक्रोश व्याप्त है। वर्ष 2015 में कमला बलान के पश्चिमी तटबंध निर्माण के बाद नदी की तेज धारा में भरैन मुशहरी के 104 तथा चौकीया गांव के 39 परिवारों के घर समा गए थे। इसके बाद सभी परिवार तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो गए।

सितंबर 2025 में अंचल प्रशासन द्वारा तीन-तीन डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया, लेकिन नौ माह बीत जाने के बाद भी प्रशासन पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा तक नहीं दिला सका है। पर्चा वाली जमीन पर गांव के दबंगों का कब्जा है।

अभाव और डर के साय में गुजर रही जिंदगी : भरैन मुशहरी में 104 परिवारों के लिए मात्र दो तथा चौकिया में 39 परिवारों के लिए एक चापाकल ही पेयजल का सहारा है। बिजली, सड़क, शौचालय और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। शाम ढलते ही पूरा तटबंध अंधेरे में डूब जाता है। मोमबत्ती के सहारे रात कटती है। बच्चों को नदी पार कर गांव के स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है।

यहां रह लोग बताते हैं कि यदि कोई बीमार हो जाए तो करीब सात किलोमीटर दूर कुशेश्वरस्थान बाजार स्थित सीएचसी जाना पड़ता है।

ग्रामीण पार्वती देवी, रूपम देवी, शीशम देवी, मीरा देवी और सोनिया देवी ने बताया कि वर्षों की लड़ाई के बाद जमीन का पर्चा तो मिला, लेकिन आज तक बसने का अधिकार नहीं मिला। तटबंध पर जंगली जानवर और सांप-बिच्छु का डर बना रहता है। रातभर परिवार के बड़े सदस्य बच्चों की सुरक्षा के लिए जागते हैं।

तटबंध पर बसे विस्थापित परिवार। जागरण।

वर्ष 2024 में आए भीषण बाढ़ के दौरान सांसद तथा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री ने क्षेत्र का दौरा किया था। इसके बाद अंचल प्रशासन ने सरकारी जमीन तलाश कर सभी विस्थापित को तीन-तीन डिसमिल जमीन का पर्चा निर्गत किया। अब पर्चाधारियों को पीएम आवास योजना से मकान बनाकर दिया जाएगा। **-गोपाल पासवान, अंचलाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी।**

सुप्रीम कोर्ट चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध खनन रोकने को लेकर सख्त

- राजस्थान सरकार को वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के भीतर अवैध बालू खनन को रोकने के लिए वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज करे। उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों में फैले 5,400 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में संकटग्रस्त घड़ियाल (लंबी-नाक वाला मगरमच्छ), लाल-मुकुट वाली छतरी कछुआ और संकटग्रस्त गंगा नदी डाल्फिन निवास करती हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि वह 26 मई को अपना आदेश देगी। यह अभयारण्य चंबल नदी के किनारे फैला है जिसे 1978 में मध्य प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। स्वतः संज्ञान में लिए गए मामले में शीर्ष अदालत द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल ने पीठ को सूचित किया कि तीनों राज्यों ने कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन के लिए रोडमैप का संकेत देते हुए अपने हलफनामे दाखिल किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

सर्वोच्च अदालत उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों पर 26 मई को देगी आदेश

20 मई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने भारत विरोधी आतंकी साजिश के तहत पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को गोपनीय सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के आरोप में कोलकाता के जफर रियाज उर्फ रिजवी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।

500-500 रुपये का लालच देकर भारतीय युवाओं को गुमराह कर रही आइएसआइ

आपरेशन सिंदूर के बाद हर मोर्चे पर विफल रहने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का नया हथकंडा

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, सीसीटीवी जासूसी आपरेशन व इन्फ्लूएंसरों के नेटवर्क से जुड़े कई मामले सामने आए

नई दिल्ली, आइएएनएस : आपरेशन सिन्दूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को गहरी चोट देने के साथ सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। वहीं, पाकिस्तान बड़े जवाबी हमले के बावजूद भारत में कोई बड़ा नुकसान करने में विफल रहा। इस शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत के भीतर अपने जासूसी नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए आक्रामक अभियान चला रही है। भारतीय एजेंसियों ने ऐसे कई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें सीसीटीवी जासूसी आपरेशन और इन्फ्लुएंसर्स का एक नेटवर्क शामिल है। हालांकि ये बड़े मामले हैं, पर एजेंसियां उन युवाओं के एक बड़े नेटवर्क को लेकर ज्यादा परेशान हैं जो मात्र 500 रुपये जैसी छोटी रकम के लिए जानकारी देने को तैयार हो जाते हैं।

प्रतीकात्मक

व्हाइट कालर नेटवर्क

व्हाइट-कालर यानी पढ़े-लिखे लोगों का नेटवर्क। इन लोगों को 50 से 75 हजार रुपये के बीच मिलते हैं। यह वही नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल हनी ट्रैप और भारत के रक्षा, विज्ञान और तकनीक क्षेत्रों के बारे में बहुत संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है।

पैसे का लालच कर रहा नेटवर्क का विस्तार

एक अधिकारी ने कहा, ऐसे मामलों में भर्ती की रणनीति भी बहुत आसान होती है। भारत में मौजूद हैंडलर्स को इस जासूसी काम के लिए बस कुछ युवाओं की पहचान करने को कहा जाता है। बदले में इन लड़कों को अपने दोस्तों के ग्रुप से ऐसे ही और लोगों को ढूंढने को कहा जाता है। इन युवाओं के लिए, सिर्फ पैसे का लालच ही उन्हें इस नेटवर्क में खींच लाता है। इन लोगों से काम करवाने के लिए यह कम भुगतान ही काफी होता है।

ये कम लागत वाले जासूस 500 से 1,000 रुपये के बीच चार्ज करते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक हैं और इनको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। आइएसआइ इनसे जो जानकारी मांगती है, वह भले ही छोटी लग सकती है, पर बहुत अहम होती है। उदाहरण के लिए, किसी युवक को रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने को कहा जाता है।

सैन्य गतिविधियों पर नजर: भारतीय सेना सैनिकों की आवाजाही, टैंक, तोपखाने व भारी रसद ले जाने के लिए रेलवे पर बहुत ज्यादा निर्भर है। रेलवे नियमित रूप से विशेष सैन्य ट्रेनें चलाती है। इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। इन नए लड़कों को बस ट्रेन का समय, उसकी आवाजाही का विवरण व गंतव्य की जानकारी देनी होती है।

रणनीतिक संपत्ति बने जासूस: इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा, ऐसे कामों के लिए आइएसआइ उन युवाओं की तलाश करती है जो रेलवे स्टेशनों पर बिना किसी काम के घूमते रहते हैं। ये लोग आइएसआइ के लिए रणनीतिक संपत्ति बन गए हैं।

सस्ते फोन को ट्रैक करना मुश्किल : कम लागत वाला यह नेटवर्क बिना जीपीएस या बिना रिकार्डिंग सुविधा वाले सस्ते फोन का प्रयोग करता है, जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। काम पूरा होने के बाद इन फोन के सिम कार्ड फेंक दिए जाते हैं।

जासूसी नेटवर्क के अलग-अलग स्तर : एक अधिकारी ने कहा, आइएसआइ कई स्तरों पर जासूसी नेटवर्क बनाने में लगी है। इसके पास कुछ ऐसे नेटवर्क भी हैं, जो संवेदनशील जगहों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। इन लोगों को हर कैमरा लगाने के लिए 10,000- 15,000 रुपये के बीच भुगतान किया जाता है।

जातिगत गणना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी और कहा, यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है। सरकार को कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए पिछड़ी जातियों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जानना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने जनहित याचिकाकर्ता सुधाकर गुम्मुला की इस दलील से असहमति जताई कि सरकार के पास जातिगत विवरणों से संबंधित पर्याप्त जानकारी और आंकड़े उपलब्ध हैं। सुधाकर स्वयं अपनी दलीलें पेश करने के लिए उपस्थित हुए थे। मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, "जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए या नहीं, ये सभी नीतिगत मामले हैं। इसमें गलत क्या है। सरकार को यह जानना आवश्यक है कि पिछड़े वर्ग में कितने लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार के कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए। यह नीतिगत दायरे में आता है।" 2027 की जनगणना, जिसे आधिकारिक तौर पर 16वीं राष्ट्रीय जनगणना कहा जाएगा, 1931 के बाद पहली बार व्यापक जाति गणना को शामिल करने वाली जनगणना होगी और देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी।

टेट्रा पैक व सैशे में शराब की बिक्री का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एक एनजीओ ने की है ऐसी पैकेजिंग में शराब बिक्री पर रोक की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक और सैशे में जूस जैसे पैकेजिंग में शराब की बिक्री को बहुत भ्रामक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिका में प्रतिपक्षी बनाए गए केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण विभाग के सचिव व राज्यों के आबकारी विभागों के आयुक्तों से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण विभाग के सचिव, राज्यों के आबकारी आयुक्तों को भेजा नोटिस

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची व विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बुधवार को एनजीओ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और केंद्र और सभी राज्यों के एक्साइज विभागों को नोटिस जारी किए। संस्था की ओर से पेश वकील विपिन नायर ने कहा, शराब उत्पाद, फलों की तस्वीर वाले आकर्षक डिजाइन की पैकिंग में बेचे जा रहे हैं जो जूस उत्पादों जैसे दिखते हैं। चिली मैंगो वोदका, ग्रीन एप्पल जैसे उत्पाद बच्चों व युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं, जबकि इन पर तंबाकू उत्पादों की तरह स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी भी नहीं होती। कहा, टेट्रा पैक व सैशे जैसी छुपाई जा सकने वाली पैकेजिंग सार्वजनिक स्थानों, वाहनों, शैक्षणिक संस्थानों में शराब सेवन को बढ़ावा देती हैं। इससे कम उम्र के लोगों तक शराब की पहुंच आसान हो जाती है। नायर ने ऐसी पैकेजिंग के टेट्रा पैक की फोटो दिखाई तो सीजेआइ ने कहा, ये बहुत भ्रामक है। याचिका में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर ऐसी पैकेजिंग को हतोत्साहित किया जाए और उसे आर्थिक लाभों की वेदी पर कुर्बान न किया जाए। चूंकि हर राज्य की बाटलिंग की अपनी अलग नीति है, अतः जरूरी है कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और अस्पष्ट पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर रोक लगाए। समान व सुसंगत दिशा-निर्देश तय किए जाएं ताकि जन स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर शराब की बाटलिंग को रेगुलेट किया जा सके। केंद्र, राज्यों के संबंध में नीति तैयार करे। राज्य सरकारें अपने आबकारी कानूनों, और नीतियों में संशोधन करें और बाटलिंग की समान परिभाषा अपनाएं जो कि केवल कांच के पात्रों या स्पष्ट रूप से दिखने वाले पात्रों तक ही सीमित हो।

आतंकवाद के खिलाफ मेघालय में 13 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू

- दो सप्ताह का अभ्यास अर्ध-पर्वतीय और जंगल के इलाके में हो रहा
- भूटान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश शामिल

गुवाहाटी, प्रेट्र : मेघालय में 13 देशों के रक्षा कर्मियों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी संचालन है। सैन्य अभ्यास 'प्रगति-2026' उमराय मिलिट्री स्टेशन पर 12 मित्र देशों (भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम) की भागीदारी के साथ शुरू हुआ। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बुधवार को कहा, "यह दो सप्ताह का अभ्यास अर्ध-पर्वतीय और जंगल के इलाके में आतंकवाद विरोधी संचालन पर केंद्रित होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त योजना अभ्यास, सामरिक स्तर के ड्रिल और समन्वित संचालन शामिल होंगे, जो भाग लेने वाले सैनिकों की अनुकूलनशीलता, सहनशक्ति और सामरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।" रावत ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन करते समय शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और समन्वय पर जोर दिया जाएगा। अभ्यास के हिस्से के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी और रक्षा कंपनियां आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी उपकरणों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी, जो ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा और रक्षा उत्पादन, नवाचार और आत्मनिर्भरता में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करेगा। अभ्यास के उद्देश्यों में संयुक्त संचालन में भाग लेने वाले देशों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम करना, सहयोग के सामान्य क्षेत्रों की पहचान करना, विशेषज्ञता साझा करना और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना शामिल है।

एअर इंडिया एआइ-171 विमान हादसे की जांच अंतिम चरण में, रिपोर्ट जल्द : नायडू

- नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा - जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से की जा रही है
- सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान

रांची, एएनआइ : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने बुधवार को रांची में कहा कि एअर इंडिया (एआइ-171) विमान हादसे की जांच अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह जांच पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान होने के कारण इस जांच का वैश्विक महत्व है और इसकी वैश्विक स्तर पर समीक्षा की जा सकती है। ज्ञात हो, 12 जून 2025 को एअर इंडिया की उड़ान एआइ-171 (बोइंग 787-8 विमान) अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद मेघानीनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भीषण हादसे में 229 यात्रियों, चालक दल के 12 सदस्यों और जमीन पर मौजूद 19 लोगों सहित कुल 260 लोगों की जान चली गई थी।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि यात्रियों की मांग पर रांची हवाई अड्डे पर 'उड़ान यात्री कैफे' शुरू किया जा रहा है, ताकि किफायती दरों पर खान-पान की सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, उन्होंने रांची की सुंदरता की तारीफ की और पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट से निपटने के लिए देश के सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।

राम मोहन नायडू किंजरापु। फाइल

कर्तव्य की आखिरी सांस, मलबे में भी विमान थामे रहे कैप्टन

अहमदाबाद, प्रेट्र: अहमदाबाद विमान हादसे का ऐसा झकझोर देने वाला सच सामने आया है, जो कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा बयां करता है। इस हादसे में अपने भाई, भतीजी व चाची को खोने वाले रोमिन वोहरा ने दावा किया है कि शवगृह में उन्होंने फ्लाइट के कैप्टन सुमीत सभरवाल के शव को देखा था, जो मृत्यु के बाद भी काकपिट की तरह ही बैठी हुई मुद्रा में था। वर्दी पहने कैप्टन का शरीर पीछे से झुलसा था, पर पैर मुड़े हुए थे और हाथ आगे की ओर स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, मानो वे आखिरी सांस तक विमान को बचाने की जंग लड़ रहे हों। इस मर्मस्पर्शी दावे के बाद अमेरिकी ला फर्म ने मांग की है कि किसी एक पर दोष मढ़ने के बजाय निष्पक्ष जांच हो, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

कोर्ट का सिखों की धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा व आडिट पर विचार से इन्कार

- कोर्ट ने इसे विधायी मामला बताते हुए कानून में संशोधन की जरूरत बतायी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सिखों की धार्मिक और विरासत संपत्तियों की सुरक्षा, आडिट व नियमन के लिए दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। इस याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे अदालत में "अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सिख धार्मिक, ऐतिहासिक और दान संपत्तियों की पूरी सूची पेश करें। इसमें स्वामित्व, पट्टा, हस्तांतरण व अतिक्रमण के विवरण शामिल हों।"

सीजेआइ सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता चरणजीत सिंह से कहा, उन्हें अपनी शिकायतें संसदीय याचिका समिति के समक्ष उठानी चाहिए। दिल्ली के एक सिख संगठन से जुड़े चरणजीत ने पीठ के समक्ष झुककर कहा, कृपया मेरी याचिका पर नोटिस जारी करें।" इसमें "सभी खालसा सिख विरासत संपत्तियों की पहचान, संरक्षण, आडिट और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय खालसा सिख विरासत संरक्षण प्राधिकरण का गठन करे।"

सीजेआइ ने कहा, कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं, पर मांगी गई राहत विधायी क्षेत्र में आती है। इसके लिए आपको संसद में जाना होगा। आपको संसद की याचिका समिति से संपर्क करना चाहिए। यदि हम हस्तक्षेप करते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी हो रही है। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, यदि वह संसदीय प्रतिक्रिया से असंतुष्ट रहते हैं तो कोर्ट लौट सकते हैं।

मणिपुर में बंधकों का पता लगाने को सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर में सुरक्षा बल कांगपोकपी जिले के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तलाश में अभियान चला रहे हैं। अभियान में खोजी कुत्तों का भी प्रयोग हो रहा है। पुलिस ने कहा, "कांगपोकपी जिले के लेइलोन वाइफेई, सोंगटुन, खुनखो व पी मोल्डिंग गांवों के आसपास की पहाड़ी श्रृंखलाओं में लापता लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बल तलाशी अभियान जारी रखे हैं।" 13 मई को कांगपोकपी में चर्च से जुड़े तीन पदाधिकारियों की घात लगाकर हत्या के कुछ घंटे बाद कांगपोकपी और सेनापति जिलों में सशस्त्र समूहों ने 38 से अधिक लोगों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था। उनमें से 31 को रिहा कर दिया गया है। लियांगमाई नागा समुदाय के एक नेता ने मंगलवार को मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह से मुलाकात की और कहा कि भले ही लापता लोग मर चुके हों, उनके शव उनके परिवारों को सौंप दिए जाने चाहिए।

आय से अधिक संपत्ति मामले में नौसेना के पूर्व कैप्टन के खिलाफ मामला दर्ज

- सीबीआइ ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की

नई दिल्ली, प्रेट्र: सीबीआइ ने भारतीय नौसेना के एक पूर्व कैप्टन के खिलाफ तीन करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि एक जुलाई, 1989 को सब-लेफ्टिनेंट के रूप में नौसेना में भर्ती हुए इस अधिकारी ने छह अगस्त, 2016 को कैप्टन के पद तक तरक्की की, जो थलसेना में कर्नल के समकक्ष होता है। वे 2024 में सेवानिवृत्त हो गए।

अपने कार्यकाल में उन्होंने नेटवर्क सेंट्रिक आपरेशंस निदेशालय, मुख्यालय एसएफसी (रणनीतिक बल कमान), नौसेना डाकयार्ड, मुंबई, बीएचईएल में गुणवत्ता निगरानी (नौसेना) प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और नौसेना डिजाइन निदेशालय (पनडुब्बी डिजाइन समूह) सहित कई संवेदनशील पदों पर कार्य किया। एफआइआर के अनुसार, अधिकारी कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक अचल संपत्ति अर्जित की थी।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने 2010 से 2020 के बीच कई संपत्तियां अर्जित कीं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान, परिवार की संपत्ति कथित तौर पर 2.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.90 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें अचल संपत्तियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। आरोपित अधिकारी ने कथित तौर पर 2011 में पंचकुला में खरीदी गई जमीन पर एक फार्महाउस का निर्माण कराया था। उक्त फार्महाउस के निर्माण और उसके रखरखाव पर हुए खर्च को ध्यान में नहीं रखा गया है।

बांद्रा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

बांबे हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के समीप बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोपहर तीन बजे के बाद माहौल बिगड़ गया। कुछ युवकों ने कार्रवाई के विरोध में पुलिस और निगम के दस्ते पर पथराव शुरू कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे स्टेशन के पास अवैध निर्माण-अतिक्रमण की शिकायतें मिली थीं। हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में बीएमसी टीम मंगलवार सुबह फोर्स के साथ मौके पर पहुंची थी। पहले दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी, पर बुधवार दोपहर जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़े, भीड़ में शामिल युवकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।

मुंबई में बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर में बुधवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव के बाद तैनात पुलिस। प्रेट्र

हिंदू समुदाय पर अन्याय करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा : मंगलप्रभात लोढ़ा

राज्य ब्यूरो, मुंबई: मुंबई के पश्चिमी उपनगर मालवणी क्षेत्र में स्थानीय पार्षद और विधायक के संरक्षण में अवैध निर्माण को बढ़ावा देकर बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने यह आरोप लगाते हुए कहा, ये अवैध निर्माण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और इन पर कार्रवाई जारी रहेगी। मालवणी क्षेत्र स्थित सावरिया मस्जिद परिसर में रहने वाली रागिनी रमाशंकर चौरसिया नामक के घर का दरवाजा बंद कर अवैध निर्माण किया गया है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पता चला कि आबिद और हुसैन द्वारा किया गया निर्माण अवैध था।

ईडी को दुष्कर्म के आरोपित ढोंगी बाबा खरात की हिरासत मिली

मुंबई, प्रेट्र : ईडी ने बुधवार को अदालत को बताया कि दुष्कर्म के आरोपित ढोंगी बाबा अशोक खरात ने दिव्य शक्तियों का दावा करके सुनियोजित तरीके से जबरन वसूली की। उसने 60 बैंक खातों के माध्यम से 47 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध धनराशि का लेन-देन किया। विशेष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को उसकी 26 मई तक के लिए हिरासत दे दी। दुष्कर्म व धोखाधड़ी के कई मामलों का सामना कर रहे खरात को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट में पेश किया। ईडी ने नासिक पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर का संज्ञान लेते हुए छह अप्रैल को खरात के खिलाफ केस दर्ज किया था।

ईडी का दावा है कि खरात ने बेनामी या प्राक्सी बैंक खातों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली व मनी लांड्रिंग का रैकेट चलाया।

जागरण विशेष

अब कोई भी करा सकेगा सड़क की गुणवत्ता की जांच

सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अहम पहल, नोएडा में बनेगी नेशनल क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी

चेतना राठौर • जागरण

नोएडा : गड्ढों में तब्दील होती नई सड़कें, पहली वर्षा में उखड़ता डामर और आम आदमी के मन में उठता वही सवाल... क्या सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई? यह प्रश्न सिर्फ शिकायत बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि इस शंका का समाधान भी किया जा सकेगा। अब कोई भी व्यक्ति सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता की जांच करा सकेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नोएडा के सेक्टर 62 स्थित इंडियन अकादमी आफ हाईवे इंजीनियर्स (आइएएचई) परिसर में अत्याधुनिक नेशनल क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित कर रहा है। छह महीने में यह लैब पूरी तरह से काम करने लगेगी। यह लैब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त होगी। यहां सभी परीक्षण एनएबीएल के दिशानिर्देश के अनुसार किए जाएंगे, जिससे जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

इस लैब की सबसे खास बात यह होगी कि केवल सरकारी एजेंसियां ही नहीं, आम नागरिक भी सड़क निर्माण सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगर निगम सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता को लेकर लोग परेशान होते हैं, लेकिन कहीं शिकायत नहीं कर पाते। जनप्रतिनिधि भी बहुत ध्यान नहीं देते। लेकिन, अब कोई भी व्यक्ति कूरियर के जरिये सड़क से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज सकेगा। एक माह के भीतर रिपोर्ट भी आ जाएगी। इसके लिए शुल्क देना होगा, जिसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है। सैंपल की रिपोर्ट कोडिंग के माध्यम से दी जाएगी, जो संबंधित व्यक्ति और संस्था के पास ही उपलब्ध होगा। सैंपल में जो भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी, उन्हें रिपोर्ट के माध्यम से अकादमी संबंधित विभाग से भी साझा करेगी, जिससे आसानी से सड़क निर्माण में खामियों को दूर किया जा सके। संस्थान सैंपल भेजने वाली संस्था या आम व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखेगा।

नोएडा में सेक्टर-62 स्थित भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी • जागरण

तीन हिस्सों में बनेगी अत्याधुनिक लैब

मशीनों का आकार बड़ा होने के कारण लैब को आइएएचई परिसर में तीन अलग-अलग भागों में विकसित किया जा रहा है, ताकि परीक्षण कार्य जल्द और व्यवस्थित तरीके से हो सके। यहां सड़कों में उपयोग होने वाले डामर, सीमेंट, मिट्टी, कंक्रीट और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच अलग-अलग होगी। लैब में बिटुमिन, एफडब्लूडी, मिट्टी, सीमेंट, यूटीएम, जियो टेस्टिंग, जियो ग्रिड टेस्टिंग, सरिया, पेंट, तार सहित अन्य सड़क निर्माण सामग्री को बारीकी से जांचा जाएगा। प्रशिक्षण लेने पहुंचने वाले देश-विदेश के इंजीनियरों को लैब में भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का सैंपल

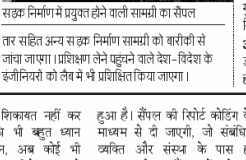

> कोई भी संस्थान या व्यक्ति सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल भेज सकता है। यह लैब एनएबीएल से मान्यता प्राप्त रहेगी। छह माह में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इसके शुरू होने के बाद सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही बढ़ेगी और घटिया निर्माण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
>
> **आलोक कुमार पांडे,**
> डायरेक्टर, इंडियन एकेडमी आफ हाईवे इंजीनियर्स

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आयकर अधिकारी व उनकी पत्नी 19 साल बाद भ्रष्टाचार के मामले में बरी

ठाणे, प्रेट्र : विशेष सीबीआइ अदालत ने एक निलंबित आयकर अधिकारी और उनकी पत्नी को 2007 के आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी कर दिया है। साथ ही सीबीआइ की गलत व लापरवाह जांच पर सवाल उठाया है।

न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित को निर्दोष साबित करने की जरूरत नहीं है और संभाव्यता का प्रबल होना ही पर्याप्त है। अदालत ने अनिल रत्नाकर मल्लेल (45), जो तब महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तैनात आयकर अधिकारी थे और उनकी पत्नी सुवर्णा (43) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (उकसाने) के तहत आरोपों से मुक्त कर दिया। सीबीआइ के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी-मुंबई) ने जनवरी 2007 में यह मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सितंबर 1991 से दिसंबर 2006 के बीच अनिल ने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति जमा की। प्रारंभिक एफआइआर में संपत्तियों का मूल्य 15.34 लाख रुपये बताया गया, जबकि सीबीआइ ने नवंबर, 2008 में दायर अंतिम चार्जशीट में इस आंकड़े को 28,57,984 रुपये कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि सीबीआइ ने नकद प्रवाह के वैध स्रोतों को नजरअंदाज किया, जिसमें मल्लेल की पत्नी और उनकी दिवंगत मां द्वारा लिया गया 8 लाख रुपये का संयुक्त आवास ऋण, 2000 से पत्नी द्वारा दाखिल किए गए स्वतंत्र आयकर रिटर्न, सामान्य भविष्य निधि से निकासी और रिश्तेदारों से लिए गए दस्तावेजित ऋण शामिल हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार, 21 मई, 2026

दैनिक जागरण

शिक्षा में किया निवेश जीवनपर्यंत प्रतिफल प्रदान करता है

आदत से लाचार राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह गद्दार करार दिया, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें रह-रह कर कुछ बेतुके, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान देने की आदत पड़ गई है और वे इस आदत से लाचार भी हो गए हैं। विशेष बात यह है कि वे कई बार अपने भोंडे और ओछे बयान दोहराते भी रहते हैं और यह प्रतीति भी कराते हैं मानो उन्होंने कोई बहादुरी का काम कर दिखाया हो। उन्होंने गद्दार वाले अपने बयान को दोहराते हुए कहा, 'आरएसएस वालों सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूं कि मोदी और शाह गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है।' संविधान खतरे में है, उनका पुराना जुमला है। इसे वे जाने कितनी बार दोहरा चुके हैं। इसी तरह वे एक समय चौकीदार चोर है... का जुमला दोहराते थे। वे प्रधानमंत्री को सैनिकों के खून की दलाली करने वाला और न जाने क्या-क्या कह चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी के ऐसे अशोभनीय बयान उन पर ही भारी पड़े हैं, लेकिन वे कुछ समझने के लिए तैयार नहीं।

ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक विफलताओं से हताश और कुंठित होकर राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और वे राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ओछी और अपमानजनक बयानबाजी विरोध अथवा आलोचना का पर्याय नहीं हो सकती। समस्या यह है कि राहुल यह साधारण सी बात समझने को तैयार नहीं कि राजनीति की अपनी एक भाषा होती है और आलोचना-निंदा का यह मतलब नहीं होता कि किसी के प्रति अशोभनीय टिप्पणियां की जाने लगें। चूंकि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वे किसी से कुछ सीखेंगे, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से तो यह सीखना ही चाहिए कि शब्दों की मर्यादा लांघे बिना प्रधानमंत्री अथवा उनके सहयोगियों की कड़ी आलोचना कैसे की जा सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल की तुलना में प्रियंका कहीं अधिक प्रभावी वक्ता हैं। राहुल अपने बेतुके बयानों से चर्चा में अवश्य आ जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी छवि अक्खड़, अशिष्ट और अगंभीर नेता के रूप में ही अधिक उभरती है। उनकी एक समस्या यह भी है कि वे ऐसे नेताओं से घिरे हैं, जो उनके हर बेतुके बयान की केवल वाह-वाही ही नहीं करते, बल्कि उनमें इसके लिए होड़ भी मचती है कि कौन कितनी अधिक अशिष्ट बयानबाजी कर सकता है।

जीवन होगा आसान

बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने सात निश्चय (तीन) के अंतर्गत सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य पर काम शुरू कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि विकास का वास्तविक अर्थ जनता की खुशहाली और सम्मान से जुड़ा है। पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर इसका सकारात्मक उदाहरण है। राशन कार्ड, पेंशन, प्रमाण पत्र, जमीन विवाद और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती रही हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर प्रशासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने की पहल सराहनीय है। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र की भावना मजबूत होगी। हालांकि इसके पहले भी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जाती थीं, लेकिन उनका समुचित निदान कम ही हो पाता था। मंत्री से लेकर जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह तय किया गया है कि शिविर में आने वाली शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों में करना होगा। व्यवस्था प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने वाली है। क्रियान्वयन के जरिये जनता में यह भरोसा पैदा करना होगा कि सरकार उनका जीवन बेहतर बनाने के प्रति गंभीर है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होने से काम में भी तेजी आएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था के फिर से लागू होने से लोगों की अनेक प्रकार की शिकायतों का समाधान संभव होगा।

> लोकतंत्र की सफलता केवल योजनाएं बनाने में नहीं, बल्कि उनको जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में है

विकृत सोच से उपजा सनातन विरोध

निरंजन कुमार

यह विडंबना ही है कि जो सनातन परंपरा अपने मूल में सर्वाधिक सहिष्णु, उदार और समावेशी है, उसी पर सर्वाधिक प्रहार किया जाता है

अवधेश राजपूत

वैश्विक विचार श्रृंखला को भारत की एक अनुपम भेंट है- सनातन धर्म, जो मूल रूप से समावेशी, सहिष्णु, शांतिप्रिय और सर्वकल्याणकारी है। दुर्भाग्य से विदेशी विचारधाराओं ने सनातन धर्म के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ रखी है। इन विदेशी षड्यंत्रों के प्रभाव और राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत भारत में भी कुछ राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सनातन धर्म के विरुद्ध मोर्चा खोला हुआ है। इसका ताजा उदाहरण है पिछले दिनों तमिलनाडु विधानसभा में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन का विषवमन कि सनातन को मिटा देना चाहिए। उनके अनुसार सनातन समाज को बांटता है। पहले भी उदयनिधि या ऐसे लोग सनातन विरोधी बयान देते रहे हैं। ऐसे खतरनाक वक्तव्यों के पीछे दुर्भावना और राजनीतिक स्वार्थ के साथ ही सनातन धर्म को लेकर एक विकृत समझ भी है।

'सनातन' शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की 'सद' धातु से हुआ है। पाणिनि सूत्र के अनुसार 'सद' धातु पर 'नुम्' प्रत्यय लगकर 'सना' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है 'शाश्वत' या 'सदा रहने वाला' जबकि 'तन' का अर्थ है विस्तारित। इस प्रकार सनातन का अर्थ है-जो शाश्वत रूप से विस्तारित और प्रवाहित है। कहा भी गया है, 'सनातनस्य धर्मः इति सनातन धर्मः' अर्थात् जो सदा से है और सदा रहेगा, वही सनातन है। इसका न कोई आदि (शुरुआत) है और न अंत। सनातन विरोधियों को समझ लेना चाहिए कि जिस सनातन धर्म का कोई आदि और अंत नहीं, जो शाश्वत और चिरंतन है, उसे मिटाने या नष्ट करने की कल्पना एक दिवास्वप्न ही है। अतीत में भी सिकंदर, मिहिरकुल, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, खिलजी, चंगेज खां, तैमूर लंग, बाबर, औरंगजेब आदि ने भी सनातन धर्म-संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी सनातन धर्म अपराजेय खड़ा है।

सनातन की चिरंतनता का आधार है कुछ ब्रह्माण्डीय नियम, जो सार्वदेशिक, सर्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। ये नियम हैं-सत्य, कर्म, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, सर्वकल्याण, सहिष्णुता, प्रकृति-पूजा और भक्ति इत्यादि। अर्थात सनातन केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की समग्र पद्धति भी है। सनातन धर्म से इस्लाम या ईसाइयत आदि रिलीजन या मजहब काफी अलग हैं, जो एक पैगंबर, एक किताब या एक विशिष्ट पूजा-उपासना पद्धति पर आधारित हैं और अन्य को स्वीकार नहीं करते। जबकि सर्वसमावेशी सनातन धर्म में सभी के कल्याण की कामना के साथ समूची पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने की परंपरा रही है। फिर भी, दुर्भावनावश सनातन धर्म को विभाजनकारी या भेदभावपूर्ण कहा जाता है? इस सनातन धर्म को बाद में हिंदू धर्म भी कहा जाने लगा। समय के साथ इसमें जाति प्रथा जैसी कुछ बुराइयां भी प्रविष्ट कर गईं, जिनका आंतरिक स्तर पर विरोध भी हुआ। ऐसे में कुछ बुराइयों के कारण संपूर्ण सनातन धर्म को ही मिटा देने की बात करना घोर निंदनीय है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मार्क्सवाद एवं अन्य विदेशी विचारधाराओं के साथ-साथ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण द्रमुक ही नहीं, कुछ अन्य दल भी सनातन या हिंदू धर्म की अवमानना करते रहते हैं। इससे पहले 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, 'जिस प्रकार मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को समाप्त किया जाता है, उसी प्रकार सनातन धर्म का केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।' मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके इस बयान को 'हेट स्पीच' के समान बताया था। अफसोस की बात है कि इस बयान पर कांग्रेस और अन्य दलों की मौन सहमति सी रही। उदयनिधि के हालिया बयान की निंदा करने के बजाय कांग्रेस ने इसे उनका 'निजी विचार' या 'क्षेत्रीय राजनीति' करार देकर किनारा कर लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने तो उदयनिधि के बयान का परोक्ष रूप से समर्थन ही किया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उदयनिधि के बयान की निंदा करने के बजाय धर्म को एक व्यक्तिगत विषय बताकर कन्नी काट ली। उलटे अखिलेश यादव ने तो स्वयं सनातन पर परोक्ष प्रहार किए थे। अयोध्या में राम मंदिर के प्रश्न पर मई 2022 में उन्होंने कहा, 'हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है।' यह टिप्पणी हिंदू आस्था का उपहास ही थी। इसी तरह 2025 में अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें सुगंध पसंद है, इसलिए उनकी सरकार ने कन्नौज में इत्र पार्क बनाया, जबकि भाजपा 'दुर्गंध' पसंद करती है तो गौशालाएं बनवा रही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से प्रेरित राजनीति में यह प्रवृत्ति नई नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलवाने के बचाव में कहा था कि अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता।

सनातन पर प्रहार को लेकर कांग्रेस का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। इस क्रम में इंदिरा गांधी द्वारा नवंबर 1966 में गौ-भक्तों पर गोली चलवाना, 2007 में रामसेतु प्रकरण में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार द्वारा न्यायालय में श्रीराम से संबंधित घटनाक्रम को ऐतिहासिक प्रमाण मानने से शुरू में इनकार करना या फिर अप्रैल 2025 में अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा प्रभु श्रीराम को एक मिथकीय पात्र बताने जैसे कई उदाहरण हैं।

जो सनातन परंपरा अपने मूल में सर्वाधिक सहिष्णु, उदार और समावेशी है, उसी पर सर्वाधिक प्रहार किया जाता है। जबकि ये राजनीतिक दल कट्टरपंथी विचारधाराओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलते। वहां विरोध करने पर हिंसक प्रतिक्रियाओं का भय रहता है। 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' जैसे कट्टर नारों पर तथाकथित पंथनिरपेक्ष और प्रगतिशील राजनीति प्रायः मौन रहती है। आज जबकि विश्व आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, सांस्कृतिक असहिष्णुता और सामाजिक विघटन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है तब ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता के लिए एक संतुलित और टिकाऊ समाधान सनातन के मार्ग से ही निकलेगा। सनातन धर्म को मिटाने या अवमानना करने वालों को यह ठीक से समझ लेना चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

आसान होती अच्छी शिक्षा तक पहुंच

प्रमथ राज सिन्हा

विदेशी शिक्षण संस्थानों का आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि छात्रों को नए विकल्प देता है

एक समय था जब भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की डगर बहुत कठिन हुआ करती थी। फीस, रहने का खर्च और वीजा की लागत तो ज्यादा थी ही, साथ ही उन्हें भाषा की दिक्कतों और परिवार से दूर रहने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। विदेश जाकर पढ़ाई करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हालांकि यह अब भी आसान नहीं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए नए अवसर आ गए हैं। दुनिया की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं अब भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने कैंपस यहां खोल रही हैं। भारत ने भी उन्हें यहां लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। किसी संस्थान को यहां आने के लिए दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में होना चाहिए या उस संस्थान की किसी खास विषय में असाधारण विशेषज्ञता होनी चाहिए। कई संस्थाओं ने भारत में अपने कैंपस खोल दिए हैं या खोलने की घोषणा कर दी है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी आफ एबरडीन की पांच सौ साल की शैक्षणिक विरासत है। यूनिवर्सिटी आफ साउथैंपटन के दुनिया भर में 2.85 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं।

यूनिवर्सिटी आफ वोलोंगोंग का मानना है कि अच्छी विश्वस्तरीय शिक्षा और वैश्विक करियर हर छात्र की पहुंच में होने चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। ये विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान अपने साथ गहरा अनुभव और शैक्षणिक व्यवस्था ला रहे हैं। वे भारत में ऐसे आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं, जो भारत के युवाओं के लिए उत्साहपूर्ण और उपयोगी हैं, जैसे टेक्नोलाजी, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और फाइनेंस। एक समय था जब इन संस्थानों में पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए यह न तो किफायती था और न सुलभ। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भारतीय कैंपस में पढ़ने वाला छात्र वही डिग्री पाता है, जो उसे विश्वविद्यालय के मूल कैंपस में पढ़ने पर मिलती। इससे छात्रों के लिए न सिर्फ खर्च कम हुआ है, बल्कि कई संस्थान तो अपने शुरुआती वर्षों में छात्रवृत्तियां भी दे रहे हैं। कुछ को मिलने वाले अवसर अब सबके लिए उपलब्ध हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक। फाइल

भारत एक युवा देश है और अच्छी उच्च शिक्षा देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। यहां लाखों ऐसे सक्षम और मेहनती छात्र हैं, जिन्हें सीटों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उत्कृष्ट संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। भारत में अपनी क्षमता बढ़ा रहे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भारत की इस वास्तविक और तात्कालिक आवश्यकता को भी पूरा कर रहे हैं। उनका आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि भारतीय छात्रों को नए विकल्प देता है। इस दृष्टि से इनका आना शिक्षा क्षेत्र में एक आवश्यक कदम है। क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ विविधता भी महत्वपूर्ण है।

जहां एक तरफ भारतीय उच्च शिक्षा कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, वहीं दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें विकास की आवश्यकता है। विदेशी संस्थान अपने साथ भिन्न-भिन्न बौद्धिक माहौल में विकसित अध्ययन शैली, शोध की परंपरा और नई पाठ्यक्रम संरचनाएं लाते हैं। इससे छात्र प्रश्न करने और अपने विचार रखने के नए तरीके सीखते हैं, जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलती है। जब ऊंची रैंक वाले संस्थान भारत में आते हैं, तो वे अपने साथ अपेक्षाओं के ऊंचे मानक भी लाते हैं और शिक्षा क्षेत्र के लिए उदाहरण बनते हैं। पहले भी कारपोरेट जगत में ऐसा हुआ है। वैश्विक कंपनियों के भारत आने पर भारतीय उद्योग खत्म नहीं हुए, बल्कि और बेहतर बने। सबमें सुधार का दबाव बना और जो कंपनियां बदलाव ला पाईं, वे और भी मजबूत हुईं। संभव है ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में भी हो।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का भारतीय कैंपसों में निवेश करना इसका प्रमाण है कि वे भारत के भविष्य में भागीदारी चाहते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा रुचि ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया से आई है, लेकिन दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं। सिंगापुर, यूएई और चीन जैसे देशों ने वर्षों पहले समझ लिया था कि विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से देश शिक्षा का केंद्र बनता है। भारत भी इस दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरे देशों विशेषकर करीबी देशों के छात्र भारत को केवल भारतीय संस्थानों के लिए नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में भी देख सकेंगे। इससे उद्योग में सहयोग, शोध साझेदारी, बेहतर रोजगार जैसी नई संभावनाएं खुलेंगी।

विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से देश में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि वैश्विक शैक्षिक जीवन और भारतीय बौद्धिक शक्ति साथ-साथ आगे बढ़ेंगी। इस नए अवसर में स्पष्ट नियम व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय रुचि, युवा आबादी की मांग और नीतिगत समर्थन, सब एक साथ एक बिंदु पर मिल रहे हैं और यह कोई मामूली बात नहीं। यह भारत के भविष्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए सक्रिय निर्णयों का परिणाम है। प्रश्न यह है कि इस अवसर का कार्यान्वयन कैसा होगा? क्या आने वाले शिक्षण संस्थान अपने ऊंचे मानक बनाए रखेंगे? क्या हर क्षेत्र और हर आय वर्ग के छात्रों को इन अवसरों का लाभ मिलेगा? और क्या पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था अपने आप को नए स्तर के अनुरूप तेजी से ढाल पाएगी?

(लेखक अशोका यूनिवर्सिटी, दिल्ली-एनसीआर के संस्थापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन जीने की कला

एक ऐसे समय जब बाहर का तापमान अंगारों को छू रहा है, तब अगर भीतर का तापमान भी आग उगलने लग जाए तो हमारा झुलसना तय है। इस तपिश का असर हमारे तन-मन के साथ ही करीबियों को भी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव मन सांसारिक विषयों के सुख को भोगने की इच्छा करता है और इस इच्छा में बाधा आती है या वे पूर्ण नहीं होतीं तो स्वभाव में नरमी-गर्मी होना भी स्वाभाविक है। हमारी भोग की प्यास की यही तीव्रता हमें इतना स्वार्थी बना देती है कि हमें किसी और की प्यास महसूस ही नहीं होती है। इस 'मैं और मेरे' की चिंता और तनाव से तपते इस मरू में थोड़ी सी शीतल चांदनी का समावेश ही सार्थक होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने मन के ताप को नियंत्रित करें। अगर मन को शांत रखा जाए तो हर स्थिति में आनंद ही आनंद है।

हमारा चेहरा हमारे अंदर के सच का आईना होता है। मन के विचारों की छाया को चेहरे पर उतरने से रोकना संभव नहीं। इसलिए अच्छा सोचते ही हमारा व्यक्तित्व भी खिलखिला उठता है। हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व सौम्य बन जाता है। उदासी के माहौल में हास्य की लहर से बिखरती मुस्कान नकारात्मकता की तपन को सकारात्मकता की ठंडक में बदल देती है। किंतु कई बार भरसक प्रयास करने पर भी कतिपय अज्ञानता और परिस्थितिवश हमारी छवि नकारात्मक दिखने लगती है। तनिक भी ऐसा आभास हो तो अपने सोच-विचार में अपेक्षित परिवर्तन लाएं। कामना पूर्ति के पीछे हम क्रोध, नफरत, लालच और विषाक्त विचारों के बीच फंसकर जीने का सही तरीका ही भूल गए हैं। हर परिस्थिति में जीवन के पक्षों में संतुलन साधने की समझ के साथ जीवन के उतार-चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना और वर्तमान में जीना ही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है।

डा. निर्मल जैन

आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट नीति

डा. आशीष त्रिपाठी

आतंकवाद-रोधी दिवस

आतंकवाद के विरुद्ध सभी देशों को साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी ताकि इसका समूल नाश किया जा सके

आतंकवाद समकालीन विश्व की सबसे ज्वलंत एवं जटिल समस्याओं में से एक है यह एक ऐसी समस्या है जिसने समूचे विश्व को अपने प्रकोप से प्रभावित किया हुआ है। हमारा देश भारत भी आतंकवाद जैसी समस्या से ग्रसित है और हम दशकों से इस समस्या से लड़ते आ रहे हैं। भारत में अस्थिरता लाने और देश में अशांति फैलाने के उद्देश्य से भीषण आतंकवादी हमले किए गए। यहां तक हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी इसी घटना में खो दिया। यह घटना भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी थी। लिहाजा 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी दिवस के रूप में घोषित किया।

वैसे भारत में होने वाली इन सभी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की षड्यंत्रकारी भूमिका रही है। इसी कारण से इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी आतंकवाद देश के लिए एक नासूर बना हुआ है। पिछले वर्ष कश्मीर के पहलगाम में आम पर्यटकों पर हुआ हमला भी बहुत दर्दनाक था जिसने मानव जाति की सभी संवेदनाओं को नष्ट कर दिया था। इस हमले में निर्दोष लोगों से उनका धर्म पूछ कर उनके परिवार के सामने उन पर गोलियां बरसाई गई थीं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में 26 पर्यटकों को मार दिया गया था। इस घटना के माध्यम से दंगे को भड़काकर समाज का सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र भी रचा गया था, परंतु देश ने बड़े ही संयम से काम लिया और इस घटना को अंजाम देने वाली पाकिस्तान में बैठी ताकतों को उनकी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया।

भारत की वायु सेना ने अदम्य साहस और पुरुषार्थ का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर और मुरीदके जैसे बड़े आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया और सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत की सरकार के इस मजबूत इरादे और सेना की बहादुरी को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। यह अपने आप में एक बदलते हुए नए भारत की तस्वीर है। यही नहीं, भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए एक संसदीय दल को विश्व के अनेक देशों में भेजा और पाकिस्तान के सरकार समर्थित आतंकवाद का पर्दाफाश किया। इस दल में अनेक राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया और भारत की बात को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखा।

भारत के प्रधानमंत्री अनेक मंचों से आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट करते रहते हैं। वह आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टालरेंस' की नीति की वकालत करते हैं। समूचे विश्व को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का परिचय देते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए और इसका समूल नाश करना चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

मेलबाक्स

भारत को साधना होगा संतुलन

श्रीराम चौलिया का आलेख 'अमेरिका-चीन संबंधों के नए समीकरण' केवल दो महाशक्तियों के संबंधों का विश्लेषण नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की धड़कनों को समझने का एक गंभीर प्रयास भी है। आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है, जहां वैचारिक नारों से अधिक महत्व आर्थिक हितों, तकनीकी प्रभुत्व और सामरिक संतुलन का हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री नियंत्रण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू-राजनीतिक प्रभाव के वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। विडंबना यह है कि दोनों एक-दूसरे को रणनीतिक खतरा बताते हैं, फिर भी दोनों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि पूर्ण टकराव स्वयं उनके लिए अहितकारी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि बयानबाजी में आक्रामकता और व्यवहार में व्यावहारिकता दिखाई देती है। भारत के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक है। एक ओर चीन की विस्तारवादी नीति, सीमा विवाद और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी अपने सामरिक हितों के अनुरूप ही मित्रता निभाता है। इतिहास गवाह है कि महाशक्तियां नैतिकता नहीं, बल्कि अपने व्यापक हितों के अनुसार ही संबंध तय करती हैं। इसलिए भारत को किसी भी शक्ति-गुट का 'उपकरण' बनने के बजाय स्वयं को एक स्वतंत्र, निर्णायक और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा। आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता भावनात्मक विदेश नीति नहीं, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता है। क्वाड, ब्रिक्स, जी-20 या इंडो-पैसिफिक-प्रत्येक मंच पर भारत को अपने हितों की स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। यदि भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और सामरिक क्षमता को समानांतर रूप से विकसित करता है, तभी वह अमेरिका-चीन संघर्ष के बीच अवसरों को अपने पक्ष में परिवर्तित कर सकेगा। वर्तमान विश्व व्यवस्था में वही राष्ट्र सम्मान पाता है जो दबाव में झुकता नहीं, बल्कि संतुलन के साथ अपनी दिशा स्वयं तय करता है। भारत को अब प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्णायक निर्माता बनने की आवश्यकता है।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

न्यायालय के निर्णय का स्वागत

आवारा आतंक पर सख्ती- शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख पढ़ा। यह विषय आज देश के करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा और चिंता से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेबीज से पीड़ित, हिंसक एवं खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दिया जाना वास्तव में एक अत्यंत आवश्यक और सराहनीय फैसला है। आज देश के अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आवारा कुत्तों का आतंक गंभीर रूप धारण कर चुका है। आजकल कहीं भी किसी समय कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं, जो कई बार घायल भी कर देता है। स्कूल जाते छोटे बच्चे, वृद्धजन, महिलाएं और राहगीर आए दिन इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी के कारण लोगों की दर्दनाक मृत्यु तक हो चुकी है। इसके बावजूद कुछ तथाकथित "डाग लवर" केवल भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर मानव जीवन की सुरक्षा को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं। यदि किसी को वास्तव में इन कुत्तों से इतनी हमदर्दी है तो उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ने के बजाय स्वयं उनकी देखभाल और पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे एवं बस स्टेशनों पर आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय मानव जीवन की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इस आदेश को कठोरता एवं गंभीरता से लागू करें, ताकि आमजन भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन कर सकें।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

22 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे इस माह आयोजित नीट की परीक्षा में, जिसे पेपर लीक की आशंका के कारण रद कर दिया गया और अब 21 जून को दोबारा इसकी परीक्षा कराए जाने का कार्यक्रम है।

आजकल

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल चयन की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि युवाओं के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा, जिसके माध्यम से लाखों विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक जैसी गंभीर शिकायतें सामने आती हैं, तो परीक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा डगमगाता है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से यह भी पता चलता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर गंभीर है

प्रो. श्रीप्रकाश सिंह
कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

नीट यूजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका के कारण इसे रद करते हुए दोबारा से आयोजित की जाएगी परीक्षा। फाइल

पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जैसे ही परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, सरकार ने मामले को केवल एक प्रशासनिक त्रुटि मानकर छोड़ने के बजाय कठोर कदम उठाए। परीक्षा रद करना और तुरंत सीबीआइ जांच के आदेश देना यह स्पष्ट करता है कि सरकार व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए राजनीतिक जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहती। यह निर्णय आसान नहीं था। परीक्षा रद होने से लाखों विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी है, मानसिक दबाव बढ़ा है और कई परिवारों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह समझा कि यदि थोड़े समय की असुविधा सहकर पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बचाया जा सकता है, तो वही लोकतांत्रिक रूप से उचित कदम होगा। यदि सरकार केवल सीमित कार्रवाई करती या शिकायतों को नजरअंदाज करती, तो छात्रों और अभिभावकों के बीच यह संदेश जाता कि व्यवस्था भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन है।

प्रतियोगी परीक्षाएं केवल विद्यार्थी ही नहीं देते, बल्कि उनके साथ पूरा परिवार इस प्रक्रिया से गुजरता है। माता-पिता अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद बच्चों की कोचिंग, पढ़ाई और रहने की व्यवस्था में वर्षों तक मेहनत करते हैं। परिवार अपनी उम्मीदों, सपनों और त्याग को इन परीक्षाओं से जोड़ कर देखता है। ऐसे में जब परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल एक विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। केंद्र सरकार ने इसी सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का सम्मान करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सर्वोपरि मानकर परीक्षा रद करने तथा उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया। यह कदम इस भावना को स्वीकार करने वाला था कि युवाओं की मेहनत के साथ किसी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि नकल माफिया और भ्रष्ट तंत्र सफल हो जाता तो परिश्रम और लगन से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता। उल्लेखनीय है कि सरकार लंबे समय से पारदर्शी शासन और जवाबदेह प्रशासन के आधार पर लोगों के विश्वास को कायम रखने की बात करती रही है। नीट प्रकरण में सरकार की कार्रवाई इसी सोच का विस्तार दिखाई देती है। आज भारत में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। छोटे कस्बों, ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के बच्चे भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भाग लेते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता सामाजिक न्याय का भी प्रश्न बन जाती है। वर्तमान सरकार ने यह समझा कि यदि परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार ने इसे प्राथमिकता के रूप में लिया।

नीट पर उठे सवालों के बीच भी सरकार ने सुधारात्मक कदमों की बात की और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी अपना दायित्व समझा है। अब पुनः परीक्षा आयोजित हो रही है। इस अवसर का लाभ छात्रों को लेना चाहिए, इसी में उनका भविष्य है। सरकार ने दो स्तरों पर सार्थक प्रयास किया, एक ओर सघन जांच और कड़ी कार्रवाई, दूसरी ओर शांति और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने का रचनात्मक प्रयास। यही कारण है कि सरकार ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस से दूर रखा। अनेक विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर हमला किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रशासनिक और कानूनी कदमों को प्राथमिकता दी।

डिजिटल इंडिया, आधार आधारित पहचान, आनलाइन प्रक्रियाओं और तकनीकी निगरानी के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करने की कोशिशें की गई हैं। इसलिए यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि भविष्य में सरकार परीक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाएगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि नीट विवाद सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षण था। लेकिन संकट के समय किसी भी सरकार की वास्तविक परीक्षा होती है कि वह कितनी तेजी, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ प्रतिक्रिया देती है। केंद्र सरकार ने परीक्षा रद करने, सीबीआइ जांच शुरू करने और सुधारात्मक कदमों की घोषणा करके यह दिखाने का प्रयास किया कि वह युवाओं के प्रति गंभीर है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि नीट परीक्षा प्रकरण में सरकार का दृष्टिकोण, व्यवस्था की विश्वसनीयता बचाने और छात्रों का विश्वास बनाए रखने पर केंद्रित रहा है। लोकतंत्र में संस्थाओं की साख सबसे महत्वपूर्ण होती है और जब कोई संकट उस साख को चुनौती देता है, तब निर्णायक कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। परीक्षा रद करना और उच्चस्तरीय जांच कराना इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि करोड़ों विद्यार्थियों के सपनों, परिवारों के त्याग और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता की रक्षा करने का प्रयास है।

प्रबंधन शिक्षा में केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली की पहल

डा. अतुल अग्रवाल
भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हालिया आयोजित आइआइएम समन्वय मंच की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य आइआइएम के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश एवं काउंसलिंग प्रणाली लागू करने की संभावनाओं पर विचार करना था। यह चर्चा केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को अधिक सरल, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में एक संभावित ऐतिहासिक कदम हो सकता है।

यह विदित है कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने केवल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने की दिशा में भी गंभीर प्रयास किए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात आइआइएम इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में शामिल हैं। एक समय था जब आइआइएम केवल स्नातकोत्तर प्रबंधन शिक्षा तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब वे स्नातक और एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रमों की दिशा में भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। कई आइआइएम स्नातक तथा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आइआइएम बेंगलुरु, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, संभलपुर और सिरमौर जैसे संस्थान या तो स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग अलग संस्थान अलग अलग परीक्षाओं को स्वीकार करते हैं।

यह विविधता संस्थागत स्वतंत्रता और नवाचार का प्रतीक प्रतीत होती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह छात्रों के लिए अत्यधिक जटिल और बोझिल व्यवस्था बन चुकी है। आज एक छात्र को केवल प्रबंधन शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनेक परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। प्रत्येक परीक्षा का पाठ्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, परीक्षा तिथि और चयन प्रक्रिया अलग होती है। इसके बाद अलग अलग संस्थानों के लिए पृथक आवेदन, साक्षात्कार और काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इससे छात्र मानसिक, आर्थिक दबाव का सामना करते हैं। एक और गंभीर समस्या सीट आवंटन से जुड़ी हुई है। वर्तमान व्यवस्था में छात्र अनेक संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम समय तक सुरक्षित रखते हैं, ताकि उन्हें अपनी पसंद का सर्वश्रेष्ठ विकल्प मिल सके। इससे कई सीटें लंबे समय तक अवरुद्ध रहती हैं। प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है और संस्थानों को अंतिम समय तक प्रवेश प्रक्रिया को स्थिर करने में कठिनाई होती है।

यही कारण है कि अब एक समन्वित और केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत के पास इसका सफल अनुभव पहले से मौजूद है। इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा में केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रणाली ने पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत किया है। प्रबंधन शिक्षा में भी ऐसा माडल अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैट पहले से ही आइआइएम के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एक साझा राष्ट्रीय परीक्षा के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आइपीएमएटी और जेआइपीएमएटी जैसी परीक्षाएं स्नातक प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचानने का माध्यम बन सकती हैं। यदि इन परीक्षाओं के आधार पर एक साझा आवेदन और केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रणाली विकसित की जाए, तो छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया अत्यंत सरल हो सकती है।

खरी-खरी

फूफा का रायता

मनीष कुमार चौधरी

वैसे तो रायता विभिन्न अवसर और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तरीके से फैलाया जाता है, पर शादी-ब्याह में रायता फैलाने का आनंद ही कुछ और होता है। अधिकतर मौकों पर यह प्रतिभा प्रदर्शन रूठे फूफा के जिम्मे रहता है। अपनी पत्नी के रिलेशन में कोई विवाह आयोजन हो तो मुंह फुलाने में फूफा को विशेष महारत हासिल है। वह इस बात पर भी रूठ सकता है कि शादी में बुलाने की मनुहार उससे आधी-अधूरी ही की गई है। वह अपनी पत्नी के सामने इसका पुरजोर विरोध भी दर्ज करा देता है।

लेकिन वह फूफा है तो क्या, उसकी पत्नी भी कम नहीं होती। अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे शुभ अवसर पर कोई फजीहत न हो, इसके लिए वह पति से साफ-साफ कह देती है, 'देखिए जी, इस तरह की बातें कर शादी में रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बनने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपकी साइड के सारे रिश्तेदारों को जानती हूं कि कौन-कितनी मनुहार करता है! आप तो मेरे परिवार की हर शादी में इस तरह का नाटक करते हो।' यह सुनते ही फूफा रायता फैलाने की सारी प्लानिंग ताक पर रख देता है।

शादी ही वह एकमात्र आयोजन है, जहां फूफा को उसकी औकात पता चलती है। अपने निजी जीवन में फूफा भले ही कितना तोपची क्यों न हो, शादी में उसकी हैसियत परिवार के उस वयोवृद्ध के समान हो जाती है, जहां उसकी खैर-खबर लेने वाला कोई नहीं होता। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसे नहीं गांठती और सार्वजनिक रूप से कई महिला रिश्तेदारों के सामने उस पर रौब झाड़ते हुए कहती है कि हमारे ये तो बड़े सीधे-सादे, सरल मन के हैं।

आहत फूफा रायता फैलाने के कुत्सित इरादों की मन ही मन प्लानिंग करता रहता है। लेकिन अधिकांश अवसरों पर प्रैक्टिकली वह ऐसा नहीं कर पाता। फैलाने की बात तो दूर, वह रायता खाने से आगे नहीं बढ़ पाता। पर फूफा तो फूफा ठहरा। यह पदनाम रायता फैलाने वालों की लिस्ट में चूंकि पहले नंबर पर रहता है, तो उसे यह परंपरा बनाए रखने में भरपूर सहयोग करना पड़ता है। इसके लिए वह भांति-भांति के प्रपंच करता रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर फूफा के हाथ निल बटे सन्नाटा आता है।

X पोस्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को मेट्रो से यात्रा करते देखना सुखद है। उम्मीद है कि वे ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आगे भी संकट निपट जाने के बाद मेट्रो से चलते रहेंगे ताकि नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन से जाने की प्रेरणा मिलती रहे और डीजल-पेट्रोल की बचत हो।
आशुतोष@ashutosh83B

बंगाल में इमामों और पुजारियों को मिलने वाला धार्मिक भत्ता समाप्त कर दिया गया है। सरकारी खजाने के इस पैसे का उपयोग अब 'स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कालरशिप' के माध्यम से राज्य के मेधावी और जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय बहुत स्वागतयोग्य है।
प्रभाकर कुमार मिश्रा@PMishra_Journo

प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की विश्वसनीयता और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। इस तरह की रैंकिंग कूड़ा है, जिसमें न कोई पारदर्शिता है और न ही जवाबदेही।
कुमार श्याम@thekumarshyam

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या रिषभ पंत को वनडे टीम से बाहर करना और टेस्ट की उपकप्तानी से हटाने का फैसला सही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल
क्या वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

डर कर 'पुष्पा' ने दिये अपने घुटने टेक,
किसके दम पर अब भला कूदेंगे अभिषेक।
कूदेंगे अभिषेक बुआ जी भी हैं हारी,
सारे किये कुकर्म पड़ रहे हैं अब भारी!
साफ किया बंगाल आपने जी भर चर कर,
अब शुभेंदु के राज रहोगे तुम डर डर कर!!
-ओम प्रकाश तिवारी

समाज में आई विद्रूपता का नया प्रतीक

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

भोपाल में माडल-अभिनेत्री और कारपोरेट प्रोफेशनल रही ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत आत्महत्या हो या हत्या, लेकिन यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। ट्विशा अब दुनिया में नहीं हैं, इसलिए पूरा सच शायद ही कभी सामने आ पाए। प्रथमदृष्टया यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि ट्विशा के साथ हुआ व्यवहार एक संस्कारित परिवार में शायद ही कभी होता। उनकी शादी मात्र छह महीने भी नहीं चल पाई और अब वह इस दुनिया में नहीं हैं। इसके कारणों पर सारे समाज को चिंतन करना चाहिए। दोषी कौन है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह विचार करना कि आधुनिक समाज में कैसे भी शादी बचाने के विचार ने ट्विशा की जान ले ली। ट्विशा पर शादी टूटने की रूढ़िवादी सोच या कहें कि पारिवारिक-सामाजिक दबाव नहीं होता तो शायद आज वह जीवित होती।

ट्विशा की मौत ने उजागर कर दिया कि आधुनिक और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भारत जैसे सनातनी देश में आज भी महिलाएं वैवाहिक प्रताड़ना और सामाजिक खोखलेपन का शिकार हो रही हैं। घटना ने परिवार नामक व्यवस्था, समाज और कानून तीनों को कठघरे में खड़ा किया है। यदि ट्विशा के पिता का यह कहना सही है कि हनीमून के दौरान ही उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगा था, लेकिन वह इसलिए सब सहती रही कि शादी एक झटके में टूट न जाए, तो फिर यह सोच बेटियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। परिवार और समाज, दोनों का यही दबाव रहता है कि सारे रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी बेटी की ही है। तमाम तरह की प्रताड़ना झेलकर भी वह उफ न बोले। क्या आज के समय में यह संभव है?

ट्विशा शर्मा। फाइल

ट्विशा की ही बात की जाए तो वह योग्य और सफल बेटी थी। जो बातें सामने आ रही हैं, वह तो संकेत दे रही हैं कि उसके चरित्र हनन का प्रयास मौत के बाद ही नहीं, पहले से वह इन आरोपों को झेल रही थी। गर्भावस्था, गर्भपात और उस पर भी सवाल... कुछ इस तरह की बातें ट्विशा के चैट में भी सामने आई हैं। जब मायके वालों को मालूम था कि ट्विशा गर्भपात के बाद टूट गई है तो उसे मां-बाप को सहारा देना चाहिए था। लेकिन परिवार ने भी बेटी के नए घर पर ही सब निर्णय छोड़ दिए।

पुलिस की जांच तो संदिग्ध दिखाई दे ही रही है। वह पहले दिन से ही सास के पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के भय से ग्रसित है। उसकी नजर में वही सच है, जो वह बता रही हैं। ट्विशा की मौत के बाद उसके पति समर्थ सिंह का फरार होना और सास द्वारा मीडिया के सामने आकर बहू को ड्रग एडिक्ट बताना, चरित्र हनन की कोशिश करना यही बताता ही है कि ससुराल पक्ष दूध का धुला तो नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि ट्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों के कारण भोपाल की बदनामी हो रही है। ऐसे में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने या बाहरी एजेंसी से जांच करवाने में क्या दिक्कत है। ट्विशा के माता-पिता और भाई को इसी बात से संतुष्टि मिलती है तो सरकार को क्या परेशानी है। वे इस भीषण गर्मी में न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय जहां से मिल सकता है, उन सभी दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, पर शायद सुनने वाला कोई नहीं है। ट्विशा शर्मा किसी की बेटी है, बहन है, वह भोपाल की बहू थी।

ऐसी मृत्यु किसी अन्य बेटी की न हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। जब आरोप ऐसे परिवार पर हैं, जहां न्यायिक सेवा का प्रभुत्व है तो जांच एजेंसी का दबाव में होना स्वाभाविक है। ऐसे हालात में जांच को तुरंत राज्य से बाहर या सीबीआइ की निगरानी में ट्रांसफर करने पर विचार करना चाहिए, ताकि सिस्टम का दुरुपयोग न हो सके। डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता मिल चुकी है तो पुलिस को भी वाट्सएप या इंस्टाग्राम पर भेजे गए मैसेज को एफआइआर में दर्ज करना चाहिए। इस पूरी कवायद को केवल किसी निर्दोष को फंसाने की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे दोषी की पहचान और सजा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए कानून को बिना किसी पक्षपात के अपना काम करना चाहिए।

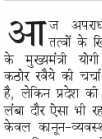

समाज को अपनी बेटियों को केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि शादी के बाद ससुराल ही उनका एकमात्र ठिकाना है, बल्कि अपनी बेटियों को सिखाना होगा, आश्वस्त करना होगा कि जिंदगी शादी टूटने से अधिक महत्वपूर्ण है। ट्विशा की मौत की लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि देश की हर उस बेटी की है, जो रसूख और रूढ़िवादिता के भंवर में फंसी हुई हैं। यह केवल एक कानूनी मसला नहीं, बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर काला धब्बा है। यह घटना कह रही है कि हमारे सामाजिक सोच और परवरिश में सब कुछ सही नहीं है।

योगी माडल

कानून एवं व्यवस्था की मिसाल

यूपी में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। योगी सरकार ने 'जीरो टालरेंस' व 'माफिया को मिट्टी में मिला देंगे' जैसी बातों को कार्रवाई के जरिये धरातल पर उतारने का माडल पेश किया है

विक्रम सिंह
पूर्व महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी

आज अपराधी और माफिया तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रवैये की चर्चा सारे देश में होती है, लेकिन प्रदेश की राजनीति का एक लंबा दौर ऐसा भी रहा है, जब अपराध केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं था, बल्कि सत्ता, जातीय समीकरण और राजनीतिक अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर राजनीतिक दलों में तनाव पैदा होता था, अधिकारियों के तबादले होते थे और गठबंधन टूटने की नौबत तक आ जाती थी।

वर्ष 1994 में कुख्यात गैंगस्टर महेंद्र फौजी का एनकाउंटर उस दौर का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह केवल एक दुर्दांत अपराधी के मारे जाने की घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट था, जिसने तत्कालीन सत्ताधारी गठबंधन (सपा और बसपा) में ऐसी दरार डाल दी, जो आगे चलकर 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड तक पहुंची और फिर वह कभी भर नहीं सकी।

आज के दौर में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 'जीरो टालरेंस' नीति की चर्चा होती है, तब पिछली सदी के अंतिम दशक का वह दौर और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यह फर्क केवल सरकारों का नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण का भी है। तब और अब का अंतर समझने के लिए जेन जी को महेंद्र फौजी के बारे में जानना आवश्यक है। पिछली सदी के अंतिम दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र फौजी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक फैले नेटवर्क वाला कुख्यात गैंगस्टर था। अप्रैल, 1994 में बुलंदशहर पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन जल्द ही इस सफलता का स्वाद फीका पड़ गया। पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए सत्ताधारी पार्टियां आपस में भिड़ गईं। एक अपराधी के एनकाउंटर के लिए एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया- वह भी एक बार नहीं दो बार!

बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी ओपी सिंह (बाद में डीजीपी बने) को हटाकर लखनऊ भेजा गया और फिर कुंभ मेले का एसएसपी बनाया गया। पुलिस पर इतने भारी दबाव के पीछे जातीय समीकरण काम कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर तो जातीय समीकरण साधने का दबाव हमेशा होता है। यह राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी थी कि एक कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर के बाद पुलिस का मनोबल न टूटने दिया जाए। स्वयं ओपी सिंह ने स्वीकार किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने उनसे साफ कहा था कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो सरकार गिर सकती है। यह बयान उस दौर की राजनीति को समझने के लिए पर्याप्त है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध और सत्ता के गठजोड़ की चर्चा महेंद्र फौजी तक सीमित नहीं रही। आगे चलकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कई नाम इस राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। सदन से लेकर सड़क तक अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नाम कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे। इससे यह धारणा मजबूत होती गई कि अपराध और राजनीति के बीच का गठजोड़ अटूट हो गया है।

वर्ष 2017 के बाद जब योगी सरकार ने माफिया पर सीधी कार्रवाई शुरू की, तो उसे केवल प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि दबावों से मुक्त एक नए राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा गया। माफिया को मिट्टी में मिला देने का योगी माडल प्रदेश भर में अपराध के खिलाफ 'जीरो टालरेंस माडल' के रूप में लागू हुआ। कौन भूल सकता है 2023 में प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल के करीबी उमेश पाल की सरेआम हत्या को, जिसे अतीक अहमद के लड़के समेत कई अपराधियों ने अंजाम दिया था। इस घटना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा था, 'माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।' यह बयान आगे चलकर उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रतीक बना।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में 10 हजार से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हुईं। इनमें सैकड़ों अपराधी मारे गए, हजारों घायल और गिरफ्तार हुए। 75 से अधिक माफिया की 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की गईं। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी व्यापक कार्रवाई हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे अपराधियों पर हुई कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि अब कानून का शिकंजा जाति, धर्म या राजनीतिक संरक्षण देखकर नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश में 'कानून का राज' स्थापित करने और तुष्टीकरण आधारित कार्रवाई की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से अलग एक नए प्रशासनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया।

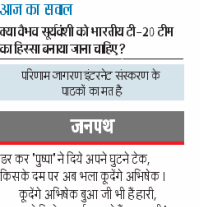

सरकार बदलने के साथ धारणा भी बदली। महेंद्र फौजी का मामला उस दौर का प्रतीक था, जब अपराध, जातीय समीकरण और सत्ता की राजनीति एक-दूसरे में उलझी हुई थीं। अपराधियों का मनोबल तोड़ने के बजाय पहले के समय में ये समीकरण पुलिस का मनोबल तोड़ते थे। जबकि इसके विपरीत आज का उत्तर प्रदेश उस दौर से अलग दिखता है, क्योंकि अब राजनीतिक विमर्श 'किस अपराधी की जाति क्या है' से आगे बढ़कर 'कानून का शासन कितना मजबूत है' पर केंद्रित हो चुका है।

विधानसभा में बोलते योगी आदित्यनाथ। फाइल

संयुक्त राष्ट्र ने भारत का वृद्धि अनुमान घटाया

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक झटकों का हवाला देते हुए 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। (प्रेट्र)

मजबूत जनसांख्यिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और सरकार के सहायक उपायों के दम पर वैश्विक स्तर पर अस्थिर माहौल के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है।
– एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस

संसेक्स	75,318.39	▲ 117.54
निफ्टी	23,659	▲ 41
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,64,900	▲ ₹ 1,300
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,66,000	▼ ₹ 5,000
डालर	₹ 96.86	▲ ₹ 0.16
क्रूड प्रति बैरल	$ 109	

एक नजर में

बीपीसीएल ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई

नई दिल्ली: भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर लगभग 41 प्रतिशत कर दी है। कंपनी के डायरेक्टर (फाइनेंस) वेट्सा रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि रूसी कच्चा तेल अब कुल आयात का 40-41 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में 31 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत था। जुलाई तक तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो गई है, जिसका बड़ा हिस्सा रूस से आएगा। (आइएएनएस)

अप्रैल में बुनियादी उद्योग का उत्पादन 1.7% बढ़ा

नई दिल्ली: देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में अप्रैल में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसे इस्पात, सीमेंट और बिजली के उच्च उत्पादन से समर्थन मिला। बुधवार को जारी आंकड़ों से जानकारी मिली। अप्रैल, 2025 में इन आठ उद्योगों का उत्पादन एक प्रतिशत बढ़ा था। मार्च में यह वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन महीने में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। (प्रेट्र)

एमएफ में कर्मियों की ओर से भुगतान कर सकेंगे नियोक्ता

नई दिल्ली: सेबी ने बुधवार को कुछ निश्चित परिस्थितियों में म्यूचुअल फंड (एमएफ) में तीसरे पक्ष से भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ नियोक्ता का अपने कर्मचारियों की ओर से निवेश करना और म्यूचुअल फंड यूनिट के रूप में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों का कमीशन का भुगतान करना शामिल है। सेबी ने इन प्रस्तावों पर 10 जून तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। अभी एमएफ में निवेश के लिए सभी भुगतान सीधे निवेशक के अपने बैंक खाते से होने चाहिए और केवल आरबीआइ से अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर से होने चाहिए। (प्रेट्र)

साबुन, शैंपू से लेकर टूथपेस्ट भी होंगे महंगे

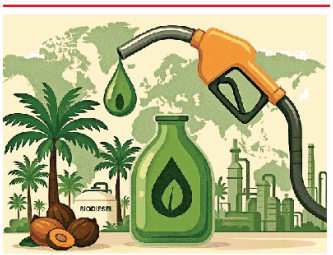

विभिन्न देशों की ओर से पाम-सोयाबीन तेल का इस्तेमाल बायोफ्यूल में करने से बढ़ रहे उत्पादों के दाम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया के 40 से अधिक देश वाहनों के ईंधन के लिए बायोफ्यूल पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पाम आयल से लेकर सोयाबीन तेल के वैश्विक दाम लगातार मजबूत हो रहे हैं। पाम आयल का इस्तेमाल साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट जैसे आइटम के उत्पादन में किया जाता है। इसके महंगा होने से इनकी कीमत भी कंपनियां बढ़ा चुकी है या बढ़ाने वाली है।

अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन जैसे सभी प्रमुख देश वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोफ्यूल को तेजी से अपना रहे हैं या इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने पाम आयल का निर्यात बंद कर दिया है, ताकि वहां पाम आयल का इस्तेमाल बायोफ्यूल के लिए किया जा सके। ब्राजील सोयाबीन से बायोफ्यूल बना रहा है। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी बायोफ्यूल के रूप में किया जा रहा है। यूरोप से मुख्य रूप से सूरजमुखी तेल का आयात भारत करता है। तेल के अलावा दूसरी अन्य चीजों के दाम में वृद्धि होने लगी है।

- पाम आयल के बड़े उत्पादक इंडोनेशिया ने बंद किया निर्यात
- सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी बायोफ्यूल में हो रहा

भारत खाद्य तेल की जरूरत का 60% हिस्सा करता है आयात

भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। मुख्य रूप से पाम आयल विदेश से मंगाया जाता है। पाम और सोयाबीन की कमी होने से इन दोनों खाद्य तेल की कीमत घरेलू स्तर पर पिछले ढाई महीनों में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी है। इसका असर सरसों तेल पर भी देखा जा रहा है। बाजार में सरसों तेल की कीमत 170-200 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। सूरजमुखी तेल की कीमत 160-190 रुपये प्रति लीटर, सोयाबीन तेल की कीमत 130-150 रुपये प्रति लीटर, मूंगफली तेल की कीमत 180-200 रुपये लीटर तो पाम तेल की कीमत 145-165 रुपये लीटर की वृद्धि हुई है।

वैश्विक स्तर पर काटन की कमी का भी संकट

अमेरिका में काटन का उत्पादन कम होने से वैश्विक स्तर पर काटन की कमी बताई जा रही है, जिससे काटन के दाम में भी तेजी दिख रही है। पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की किल्लत भी बताई जा रही है। हालांकि, घरेलू स्तर पर गेहूं की कोई कमी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो से भी विभिन्न जिन्सों के उत्पादन पर असर दिख सकता है। यही वजह है कि भारत ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

मेलोडी के चक्कर में धोखे से बढ़ गए पारले इंडस्ट्रीज के शेयर

नई दिल्ली, जेएनएन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान एक छोटा सा वीडियो भारतीय शेयर बाजार में बड़ी हलचल का कारण बन गया। इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी उन्हें भारत की मशहूर मेलोडी टाफी गिफ्ट करते नजर आए। वीडियो वायरल होते ही कई निवेशकों ने जल्दबाजी में पारले नाम देखकर शेयर खरीदना शुरू कर दिया। इसका फायदा पारले इंडस्ट्रीज को मिला, जिसके शेयरों में जबरदस्त खरीदारी शुरू हो गई। बुधवार के कारोबार में कंपनी का शेयर पांच प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 5.25 रुपये पर पहुंच गया।

असल में मेलोडी टाफी बनाने वाली कंपनी पारले प्रोडक्ट्स है, जो पार्ले-जी, मोनाको, हाइड एंड सीक और मैंगो बाइट जैसे लोकप्रिय ब्रांड बनाती है, लेकिन पारले प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में सूचीबद्ध ही नहीं है। दूसरी तरफ, जिस पारले इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी आई, उसका टाफी या बिस्कुट कारोबार से कोई लेना-देना नहीं है। पारले इंडस्ट्रीज इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और पेपर वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसे बिजनेस में लगी हुई है। उधर, पारले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने कहा कि यह कदम भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और उन्हें एक ग्लोबल प्लेटफार्म देने का एक अच्छा तरीका था। यह वीडियो वायरल होने के बाद बिक्री में उछाल आएगा।

12 सालों में 166 प्रतिशत बढ़ा टाफी का निर्यात

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 12 सालों के दौरान देश का टाफी निर्यात 166 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 132 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 2013-14 में टाफी निर्यात 49.68 करोड़ रुपये था।

प्रतिभूति बाजार से होने वाली घरेलू बचत बढ़कर 6.91 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय परिवारों के बीच वित्तीय संपत्तियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सेबी अधिकारियों द्वारा लिखे गए एक पेपर के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के 3.58 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2024-25 में प्रतिभूति बाजार के जरिये की गई बचत बढ़कर 6.91 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, 2024-25 के लिए भारत का सकल बचत-जीडीपी 47 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 34.47 प्रतिशत से बढ़कर 34.94 प्रतिशत हो गया है।

प्रभात कुमार रथ, शाइनी सुनील और कल्याणी एच द्वारा लिखे गए पेपर में कहा गया है कि प्रतिभूति बाजार से की गई घरेलू बचत, वित्तीय बचत का एक अहम हिस्सा है और यह सोना और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों के एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रही है।

- सेबी के मुताबिक भारतीय परिवारों के बीच वित्तीय संपत्तियों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही
- वित्तीय संपत्तियां ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता और तरलता के चलते लोगों के बीच हो रही हैं लोकप्रिय

निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स का रहा

2024-25 में प्राथमिक बाजार में किए गए निवेश की कुल रकम 6.32 लाख करोड़ रुपये थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 5.13 लाख करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड्स का था। 95,139 करोड़ रुपये के साथ इक्विटी दूसरे नंबर पर रही। इस साल सेकेंडरी मार्केट में किए गए निवेश का कुल योगदान 59,452 करोड़ रुपये रहा। 2024-25 में प्रतिभूति बाजार के जरिये परिवारों की बचत जीडीपी का 2.17 प्रतिशत रही। इसी तरह, परिवारों की बचत और जीडीपी का अनुपात 21.23 प्रतिशत से बढ़कर 21.7 प्रतिशत हो गया, जबकि परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 6.63 प्रतिशत से बढ़कर 7.10 प्रतिशत तक पहुंच गई।

बैंकिंग सिस्टम में पांच अरब डालर की नकदी डालेगा आरबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: आरबीआइ बैंकिंग सिस्टम में पांच अरब डालर की नकदी डालेगा। इसके लिए 26 मई को डालर-रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित की जाएगी। आरबीआइ द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच डालर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हुआ है।

इस व्यवस्था के तहत बैंक आरबीआइ को डालर बेचेंगे और बदले में उन्हें रुपये मिलेंगे। स्वैप की अवधि यानी तीन साल खत्म होने के बाद बैंक केंद्रीय बैंक को समान राशि के रुपये वापस देकर अपने डालर दोबारा खरीद लेंगे।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इस स्वैप आक्शन में न्यूनतम बोली एक करोड़ डालर की होगी और इसके बाद एक करोड़ डालर के गुणांक में ही अगली बोली लगाई जा सकेगी।

96.86 के नए निचले स्तर पर रुपया

मुंबई, प्रेट्र: लगातार नौवें सत्र में गिरावट दर्ज करते हुए डालर के मुकाबले रुपया बुधवार को 16 पैसे टूटकर 96.86 के नए निचले स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई की चिंताओं को और बढ़ा दिया। विदेशी मुद्रा बाजार में, डालर के मुकाबले रुपया 96.89 पर खुला, फिर और कमज़ोर होकर 96.95 के रिकार्ड निचले स्तर और 96.65 के उच्चतम स्तर को छुआ, और अंत में 96.86 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट है।

मिराए एसेट शेयरखान में शोध विश्लेषक (कमोडिटीज) अनुज चौधरी ने कहा, मजबूत डालर और अमेरिकी बांड रिटर्न में उछाल के कारण भारतीय रुपया नए निचले स्तर पर पहुंच गया। 30-वर्षीय बांड रिटर्न दो दशक के उच्चतम स्तर पर पहुच गया, जबकि 10-वर्षीय बांड रिटर्न 16 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे महंगाई की चिंताएं बढ़ीं और वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई।' उम्मीद है कि महंगाई की चिंताओं के बीच रुपया नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा।

- डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा बुधवार को 16 पैसे टूटी
- मजबूत डालर और बांड रिटर्न में उछाल से भारतीय मुद्रा दबाव में

अंतिम घंटे में खरीदारी से सेंसेक्स 117 अंक चढ़ा

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच अंतिम घंटे की खरीदारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल से बुधवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट से उबरकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक उतार-चढ़ाव भरे 117.54 अंक यानी 0.16 प्रतिशत चढ़कर 75,318.39 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 671.44 अंक टूटकर 74,529.41 अंक तक आ गया था। एनएसई निफ्टी 41 बढ़कर 23,659 अंक पर बंद हुआ।

सोना 1,300 रुपये बढ़ा, चांदी 5,000 रुपये सस्ती हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र: बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,300 रुपये बढ़कर 1,64,900 रुपये प्रति 10 ग्राम गई। व्यापारियों ने बताया कि कीमती धातुओं में नई खरीदारी से घरेलू सोने की कीमतों को सहारा मिला। हालांकि, चांदी 5,000 रुपये गिरकर 2,66,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विश्लेषकों ने कहा कि कम औद्योगिक मांग और मुनाफा-वसूली से चांदी अस्थिर बनी रहीं।

राष्ट्रीय फलक

पीएसपीसीएल के पूर्व सीएमडी समेत तीन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना

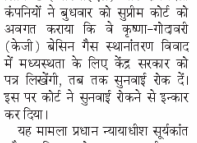

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के आर्थिक अपराध शाखा लुधियाना ने 12 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के पूर्व चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) 75 वर्षीय केडी चौधरी, पूर्व सीनियर एक्सईएन संजीव प्रभाकर और कालोनाइजर अमित गर्ग को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई 10 मई 2021 को दर्ज केस की जांच पूरी होने के बाद की है। विजिलेंस ने बुधवार को आरोपितों को अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल किया है। हालांकि, पेशी के बाद बाहर लाए जाने पर केडी चौधरी ने खुद पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि 66 केवी बसंत एवेन्यू सब-स्टेशन की स्थापना (2014-15) के मामले में कालोनाइजर ने पीएसपीसीएल के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कालोनी में 1015 वर्ग गज क्षेत्र में सब-स्टेशन स्थापित करवाया। आरोप है कि अगर उच्च अधिकारियों द्वारा कालोनाइजर की सभी कालोनियों के एनओसी की जांच करवाई जाती और कालोनियों का बिजली लोड एक साथ जोड़ा जाता तो पूरे 66 केवी सब-स्टेशन का खर्च कालोनाइजर को उठाना पड़ता।

- विजिलेंस की कार्रवाई में पूर्व सीनियर एक्सईएन व कालोनाइजर भी शामिल
- कालोनाइजर ने कालोनी में स्थापित करवाया 66 केवी सब-स्टेशन

पीएसपीसीएल के पूर्व सीएमडी केडी चौधरी कोर्ट परिसर बाहर आते हुए। फोटो अजय शर्मा

'भारत को वैश्विक ताकत के तौर पर देख रहे युवा'

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारत के ज्यादातर युवा देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रहे हैं और उनका मानना है कि मौजूदा विदेश नीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में विदेश नीति पर किए गए एक सर्वेक्षण में युवाओं ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं पर भरोसा जताया है और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया।

युवा ब्रिक्स को भी पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले वैश्विक ढांचे के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यानी अब देश के युवा सिर्फ नौकरी, पढ़ाई और इंटरनेट मीडिया तक सीमित नहीं है। वह दुनिया की राजनीति, देशों के रिश्तों और भारत की बढ़ती ताकत को भी बारीकी से समझ रहे हैं। यही तस्वीर सामने आई है द आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की नई रिपोर्ट 'फारेन पालिसी सर्वे : यंग इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट' में। सर्वेक्षण में देश के 19 शहरों के 18 से 35 वर्ष के पांच हजार से ज्यादा युवाओं से हुई बातचीत को शामिल किया गया है।

पश्चिम एशिया बनेगा तरक्की का आधार : सर्वेक्षण में सबसे दिलचस्प बात यह सामने आई है कि भारत के युवा पश्चिम एशिया को अब सिर्फ तेल और व्यापार का इलाका नहीं मानते। उनके लिए यह क्षेत्र भारत की तरक्की, तकनीक और वैश्विक साझेदारी का नया दरवाजा बन चुका है। युवाओं का मानना है कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और चार देशों के रणनीतिक गठबंधन आइ2यू2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को पश्चिम एशिया से और मजबूती से जोड़ेंगे। रिपोर्ट में यूएई ज्यादा चर्चा में रहा। युवाओं ने माना कि यूएई के साथ भारत की दोस्ती अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकती है। भारत-यूएई आर्थिक समझौते को युवाओं ने फायदे का सौदा बताया।

- ओआरएफ सर्वेक्षण में सामने आई नई पीढ़ी की विदेश नीति पर सोच
- पाकिस्तान पर सख्त रुख और यूएई पर सबसे ज्यादा भरोसा

भारत के पास है खेल बदलने वाली ताकत

वहीं, पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर युवाओं का रुख बेहद सख्त दिखाई दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए आपरेशन सिंदूर का युवाओं ने खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई और सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले को भी सही बताया गया। रिपोर्ट में चीन के साथ सीमा तनाव और पाक से होने वाले आतंकवाद को देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में गिना गया। इस सर्वेक्षण ने साफ कर दिया कि भारत का युवा अब दुनिया को नए नजरिये से देख रहा है। उसे लगता है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत किनारे खड़ा देश नहीं, बल्कि खेल बदलने वाली ताकत बन चुका है।

डिफाल्टर के मोबाइल फोन को डिसेबल नहीं कर सकेंगे बैंक

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने बुधवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार या होम लोन की रिकवरी के लिए डिफाल्टर के मोबाइल फोन को डिसेबल या प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों को उस मोबाइल डिवाइस को प्रतिबंधित या डिसेबल करने की अनुमति होगी, जिसे बैंक ने स्वयं फाइनेंस किया है। केंद्रीय बैंक इन नियमों को 1 अक्टूबर, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है।

केंद्रीय बैंक ने लोन की बकाया राशि की रिकवरी और रिकवरी एजेंसियों को काम पर रखने के मामलों से जुड़े सख्त नियम प्रस्तावित किए है। ये नियम उधारकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतों के बीच लाए गए हैं, जिसमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये उत्पीड़ने और गाली-गलौज का इस्तेमाल शामिल है। आरबीआइ ने प्रस्ताव दिया है, "कोई भी बैंक ऐसा कोई तकनीक आधारित तरीका नहीं अपनाएगा, जो किसी उधारकर्ता के मोबाइल डिवाइस की कार्यक्षमता को प्रभावित करे। बैंक ऐसा तभी कर सकेंगे जब उसे डिवाइस के फाइनेंस से जुड़े लोन की बकाया राशि की रिकवरी करनी हो।' बैंक तब तक डिवाइस को ब्लाक नहीं कर सकेंगे जब तक कि संबंधित लोन 90 दिनों से ज्यादा समय से बकाया नहीं हो गया हो। आरबीआइ ने कहा कि गलत तरीके से प्रतिबंध लगाने या हटाने में देरी होने पर बैंक को उधारकर्ता को उस समय तक 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा, जब तक कि उस गलत कार्रवाई को ठीक नहीं कर दिया जाता है। बैंक ने लोन की रिकवरी व रिकवरी एजेंटों को काम पर रखने मामलों में भी संशोधित मसौदा निर्देश जारी किए हैं।

- आरबीआइ ने लोन की रिकवरी से जुड़े सख्त नियम प्रस्तावित किए
- केंद्रीय बैंक का इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव

बिजली की अधिकतम मांग 265.44 गीगावाट के रिकार्ड स्तर पर रही

नई दिल्ली, प्रेट्र: बढ़ती गर्मी के चलते देश में बिजली की अधिकतम मांग बुधवार को 265.44 गीगावाट के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। इसने मंगलवार को बने पिछले रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बिजली की अधिकतम मांग 257.37 गीगावाट तक पहुंच थी और मंगलवार को बिजली की मांग बढ़कर 260.45 गीगावाट हो गई थी।

बुधवार को 15:45 बजे, बिजली की अधिकतम मांग 265.44 गीगावाट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर बताया कि यह लगातार तीसरा दिन है जब बिजली की अधिकतम मांग एक नए उच्चस्तर पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।

केजी बेसिन मामले को लेकर सुनवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और दो विदेशी कंपनियों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि वे कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन गैस स्थानांतरण विवाद में मध्यस्थता के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगी, तब तक सुनवाई रोक दें। इस पर कोर्ट ने सुनवाई रोकने से इन्कार कर दिया।

यह मामला प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची तथा जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष रखा गया। कंपनियों की ओर से पेश वकील ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि सभी याचिकाकर्ता आज केंद्र सरकार को मध्यस्थता के लिए पत्र लिखेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले मध्यस्थता का प्रयास किया जाए। वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि मध्यस्थता का परिणाम आने तक मामले की सुनवाई रोक दी जाए। हालांकि, केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मामले में सुनवाई जारी रखने का अनुरोध किया। अटार्नी जनरल ने कहा कि यदि इस बीच कुछ होता है, तो हम अदालत को सूचित करेंगे। पीठ ने सुनवाई रोकने से इन्कार करते हुए कहा कि पक्षकार मध्यस्थता के परिणाम से उसे अवगत करा सकते हैं। पीठ ने कहा कि अगर आप मध्यस्थता में सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब हम मामले का निपटारा कर देंगे।

- आरआइएल व दो अन्य कंपनियों ने कहा मध्यस्थता के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे

प्रतीकात्मक

निर्मला ने अमेरिकी राजदूत से की मुलाकात, आर्थिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। दोनों ने भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

वित्त मंत्रालय ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा, 'दोनों ने भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करने, भारत-अमेरिका वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग, निवेश के अवसरों और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।' इसमें यह भी कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गोर को आगामी 250वें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

अमेरिकी प्रशासन भारतीय कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि दोनों देशों को इसका लाभ मिल सके। इससे दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिलेगा।

'वर्क फ्राम होम' पर भेज दिग्गज कंपनी मेटा ने की आठ हजार कर्मचारियों की छुट्टी

नई दिल्ली, आइएएनएस : तकनीकी दुनिया की दिग्गज कंपनी 'मेटा प्लेटफार्म्स' से एक बेहद भावुक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार से अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 10 प्रतिशत यानी लगभग आठ हजार कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला कंपनी के उस व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसके तहत मेटा अब खुद को पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के सांचे में ढालने जा रही है। अचानक आए इस फैसले से हजारों घरों के चूल्हे प्रभावित हुए हैं। छंटनी के दिन उत्तर अमेरिकी कर्मचारियों को घर से काम करने (वर्क फ्राम होम) के लिए कहा गया था, ताकि दफ्तरों में असहज स्थितियों से बचा जा सके।

एआइ-आधारित बदलाव और कर्मचारियों का भविष्य : मेटा की एचआर प्रमुख जेनेल गेल ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक ई-मेल में इस दर्दनाक फैसले के पीछे की वजह स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि कई टीमों को 'एआइ-नेगेटिव सिद्धांतों' के आधार पर फिर से तैयार किया जा रहा है, ताकि कंपनी की संरचना को छोटा, तेज और अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। इस छंटनी के बीच एक राहत भरी खबर यह भी है कि मेटा के आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, लगभग सात हजार कर्मचारियों की नौकरी पूरी तरह खत्म नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें कंपनी के भीतर ही नए एआइ-केंद्रित भूमिकाओं में स्थानांतरित किया जा रहा है।

भविष्य की तैयारी: एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश : मेटा का यह कदम उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह एआइ के क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम करना चाहती है। कंपनी ने साल 2026 के लिए अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 125 अरब डालर से 145 अरब डालर के बीच रहने का अनुमान लगाया है। यह भारी-भरकम बजट मुख्य रूप से एआइ डाटा केंद्रों, कस्टम चिप्स और माडल ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। इस बीच, सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहाकि इस प्रक्रिया में एकत्र किया गया डाटा केवल एआइ प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए है, न कि किसी की निगरानी के लिए।

- फैसला कंपनी के व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा, अब खुद को पूरी तरह एआइ के सांचे में ढालने जा रही है मेटा

प्रतीकात्मक

20 को फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि होर्मुज में रुकावट आने से दुनिया में अन्न संकट पैदा हो सकता है। संगठन ने कहा कि इससे खाने-पीने की चीजों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

ट्रंप की बोलती बंद, ईरान में अमेरिका ने गंवाए 42 विमान

40 दिन चले आपरेशन एपिक फ्यूरी पर कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट

ईरान युद्ध के चलते अमेरिका का रक्षा खर्च 29 अरब डालर तक पहुंचा

वाशिंगटन, प्रेट्र: ईरान युद्ध को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोलती बंद कर सकती है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचने की बात उजागर हुई है। 40 दिन चले आपरेशन फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने एफ-15ई, एफ-35ए और एमक्यू-9 रीपर ड्रोन समेत 42 विमान गंवाए या क्षतिग्रस्त हुए। 28 फरवरी से शुरू हुआ यह आपरेशन आठ अप्रैल तक चला था। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के व्यापक नुकसान का जिक्र नहीं किया। वह हर बार यह कहते रहे कि अमेरिका ने युद्ध में अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि गोपनीयता, ईरान के खिलाफ जारी सैन्य संघर्ष और हमलों की जिम्मेदारी तय करने जैसे कारणों के चलते क्षतिग्रस्त या तबाह हुए विमानों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

अमेरिकी संसद और उसकी समितियों को नीतिगत और कानूनी विश्लेषण मुहैया कराने वाली सेवा सीआरएस ने मीडिया की खबरों और रक्षा विभाग व अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयानों की समीक्षा के आधार पर इस नुकसान का ब्योरा तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि 12 मई 2026 को संसद की एक उपसमिति को पेंटागन के कार्यवाहक नियंत्रक जूल्स डब्ल्यू हर्स्ट तृतीय ने बताया था कि ईरान में सैन्य अभियानों के लिए विभाग का अनुमानित व्यय बढ़कर 29 अरब डालर हो गया है। उन्होंने कहा, "इस बढ़ोतरी का बड़ा कारण उपकरणों की मरम्मत या उन्हें बदलने की लागत का ज्यादा सटीक आकलन होना है।"ध्यान रहे इससे पहले भी कई स्वतंत्र रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अमेरिका के हथियार और आयुध भंडार में काफी कमी आ गई है।

ये विमान हुए तबाह

तबाह या क्षतिग्रस्त विमानों में चार एफ-15ई स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, एक एफ-35ए लाइटिंग-द्वितीय लड़ाकू विमान, जमीनी हमले वाला एक ए-10 थंडरबोल्ड विमान, हवा में ईंधन भरने वाले सात केसी-135 स्ट्रेटोटैंकर विमान, एक ई-3 सेंटी अवाक्स विमान, विशेष अभियान वाले दो एमसी-130जे विमान, एक एचएच-60डब्ल्यू जाली ग्रीन-द्वितीय हेलीकाप्टर, 24 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन और एक एमक्यू-4सी ट्राइटन ड्रोन शामिल हैं।

रिपोर्ट पर अराघची ने कही यह वात

एएनआइ के अनुसार, युद्ध में अमेरिका को पहुंचे नुकसान की रिपोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि आखिर अमेरिका ने माना कि उसने युद्ध के दौरान अरबों डालर के दर्जनों विमान गंवा दिए। इससे हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों की पुष्टि होती है कि उन्होंने ही सबसे पहले बहुचर्चित एफ-35 को मार गिराया था।

युद्ध में राष्ट्रपति के अधिकार किए गए कम

- आठवें प्रयास में सीनेट ने पारित किया इस आशय का प्रस्ताव
- ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसदों ने भी किया समर्थन

वाशिंगटन, एएनआइ : ईरान युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकार कम करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन से पारित इस आशय के प्रस्ताव का समर्थन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसदों ने भी किया है। लगातार सात बार की नाकामी के बाद आठवें प्रयास में इस प्रस्ताव पर सीनेट की मुहर लगी है।

सीबीएस न्यूज के अनुसार, सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विरोध में 47 सीनेटरों ने मतदान किया। हैरानी की बात यह है कि चार रिपब्लिकन सीनेटरों ने भी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का साथ दिया और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। ट्रंप के खिलाफ वोटिंग करने वाले रिपब्लिकन सीनेटरों में सुसान कोलिंस, लिसा मुर्कोव्स्की, रैंड पाल और बिल कैसिडी शामिल हैं। डेमोक्रेट्स द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव आठवें प्रयास में पारित हुआ है। डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने इस प्रस्ताव को पेश किया था।

इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण रखना और संसद की भूमिका सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव पारित होने पर डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ ने कहा, डेमोक्रेट्स ने एक बार फिर इस असंवैधानिक युद्ध को समाप्त करने के लिए वोटिंग के लिए मजबूर किया है। रायटर के अनुसार, यह प्रस्ताव भले ही 100 सदस्यीय सीनेट से पारित हो गया है, लेकिन इसे रिपब्लिकन के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा से भी पारित कराना होगा। यही नहीं ट्रंप के संभावित वीटो को बेअसर करने के लिए इसे दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पास कराना आवश्यक होगा।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा, ईरान के साथ वार्ता अंतिम चरण में

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेताया, समझौता नहीं हुआ तो फिर करेंगे हमले
- ईरान बोला- हमला हुआ तो पश्चिम एशिया के बाहर तक फैल लाएगा युद्ध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ वार्ता अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर ईरान समझौता करने पर सहमत नहीं होता है तो उस पर फिर से हमले होंगे। इस पर ईरान ने भी धमकी भरा जवाब देते हुए कहा, अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो युद्ध पश्चिम एशिया के बाहर तक फैलेगा।

रायटर के अनुसार, ट्रंप ने युद्धविराम के लिए छह हफ्ते पहले आपरेशन एपिक फ्यूरी को रोक दिया था, पर युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है। ट्रंप ने इसी सप्ताह कहा था कि वह और हमलों का आदेश देने के करीब थे, पर वार्ता के लिए ज्यादा समय देने के लिए उन्होंने रुकने का निर्णय लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, "हम ईरान को लेकर अंतिम चरण में हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है। या तो कोई समझौता होगा या हम कुछ ऐसा करेंगे, जो थोड़ा खराब होगा, पर उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत जल्दी में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि कम लोग मारे जाएं।" उन्होंने कहा,अमेरिका पहले से भी ज्यादा भीषण हमला कर सकता है, पर वह इंतजार करेगा कि क्या कोई समझौता हो सकता है। इधर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उनके देश और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के माध्यम से संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है।

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ईरानी रिवोल्यूशरी गार्ड ने एक बयान में कहा, "अगर ईरान के खिलाफ आक्रमण दोहराया गया तो हम वादा करते हैं कि यह युद्ध क्षेत्र के बाहर तक फैल जाएगा।" वहीं ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने एक आडियो संदेश में कहा, दुश्मन की छिपी चाल से जाहिर होता है कि वह नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं।

तेहरान में पाकिस्तानी गृह मंत्री : प्रेट्र के अनुसार, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बुधवार को एक सप्ताह में दूसरी बार तेहरान गए। वह वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनकी यह यात्रा ईरान-अमेरिका शांति बहाल करने के इस्लामाबाद के प्रयासों के बीच हो रही है।

इटली में मोदी को मिला एफएओ का एग्रीकोला मेडल, भारत के 'अन्नदाताओं' को किया समर्पित

- कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में भारत के योगदान के लिए किया प्रदान
- संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है एफएओ, यह मेडल इसके सबसे बड़े सम्मानों में एक

रोम, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इटली की राजधानी रोम में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में एफएओ का एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में भारत के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने उन्हें यह मेडल प्रदान किया। मोदी ने कहा कि एग्रीकोला मेडल पाकर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने इसे देश के अन्नदाताओं को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एफएओ मुख्यालय में आयोजित समारोह में मैंने अत्यंत विनम्रता के साथ एफएओ का एग्रीकोला मेडल स्वीकार किया। मैं एफएओ का आभारी हूं। मैं यह सम्मान भारत के अन्नदाताओं, हमारे भोजन प्रदाताओं को समर्पित करता हूं। यह हमारे किसानों, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों, हमारे कृषि वैज्ञानियों और नवप्रवर्तकों की कड़ी मेहनत को मान्यता है। यह मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी स्वीकृति है।" बता दें कि एग्रीकोला मेडल को एफएओ के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुनियाभर में खाद्य और कृषि प्रणालियों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

मेलोनी बोलीं, "परिश्रम ही सफलता की कुंजी है" : इतालवी प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने भारत और इटलवी के बीच मजबूत होने रहे संबंधों को रेखांकित करते हुए बुधवार को हिंदी में कहा, "परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।" मोदी के साथ एक संयुक्त कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मेलोनी ने कहा कि भारत-इटली संबंध ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने मोदी की इस यात्रा को एक निर्णायक क्षण करार दिया जिसने द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा, "एक भारतीय शब्द है परिश्रम। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत, निरंतर प्रतिबद्धता और अथक प्रयास। यह एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में मुझे पता है कि भारत में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसे अक्सर एक लोकप्रिय कहावत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।" कहा कि यह यात्रा दो दशक से अधिक समय में किसी भारतीय पीएम की इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जिसने दोनों देशों के बीच राजनयिक जुड़ाव में नई जान फूंक दी है।

मिलकर बनाएंगे रक्षा साजो-सामान : भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भारत और इटली ने बुधवार को संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा देने के साथ ही एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप को अंतिम रूप दिया है।

मोदी और मेलोनी ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उस क्षेत्र के साथ-साथ बाकी दुनिया पर उसके प्रभाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। इस दौरान मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिये संघर्ष के समाधान का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता और नौवहन की बहाली का भी आह्वान किया। मोदी-मेलोनी वार्ता के बाद भारत और इटली ने रक्षा औद्योगिक रोडमैप जारी किया, जिसके तहत हेलीकाप्टरों और नौसैनिक हथियारों सहित सैन्य साजोसामान और प्रणालियों का सह-विकास और सह-उत्पादन किया जाएगा। दोनों देशों ने इसके अतिरिक्त इटली में उच्च शिक्षा और भारतीय नर्सों की आवाजाही के लिए नए ढांचे को अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों, कृषि, समुद्री परिवहन और समुद्री उत्पादों के क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने वाले समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात की और व्यापार, निवेश, टेक्नोलाजी, महत्वपूर्ण खनिज, एआइ, अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और विस्तार देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इतालवी राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण भी दिया।

मोदी बोले, रोम में काशी की एक झलक! : मोदी ने एक पोस्ट में इतालवी चित्रकार जियामपाओलो टोमासेटी के साथ अपनी बातचीत का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा, 'रोम में काशी की एक झलक! इतालवी चित्रकार जियामपाओलो टोमासेटी ने वाराणसी पर अपनी कलाकृति भेंट की।

भारत-इटली संबंधों को नया आयाम

रोम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनकी इतालवी समकक्ष जार्जिया मेलोनी ने एक इमारत की बालकनी से दिन में शहर का नजारा दिखाया और रात में कार से मशहूर कोलोसियम दिखाने ले गईं, जहां उन्होंने सेल्फी भी ली। जबकि बुधवार को द्विपक्षीय की बैठक के दौरान दोनों ने बगीचे में भ्रमण करने के साथ पौधरोपण भी किया। एएफपी/प्रेट्र/एएनआइ

पीएम मोदी अगर एस्टोनिया की यात्रा करें तो हमें बेहद खुशी होगी : मार्गस

तेलिन, प्रेट्र : एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत से उच्च स्तरीय दौरे की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तरी यूरोपीय देश एस्टोनिया का दौरा करते हैं तो एस्टोनिया को खुशी होगी।

त्साहकना ने कहा कि एस्टोनिया 2027 में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रूस पर दबाव डालकर क्षेत्र में शांति लाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, "भारत एस्टोनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। हमारे देश का आकार बिल्कुल अलग है, एस्टोनिया की जनसंख्या 13 लाख है जबकि भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। राष्ट्रपति अलार कारिस फरवरी में एआइ शिखर सम्मेलन के लिए भारत में थे। व्यापारिक दृष्टि से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं। रक्षा उद्योग हो, आइटी या एआइ समाधान, एस्टोनिया निवेश के लिए सही जगह है। हमारे पास ई-रेजिडेंसी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां और लोग निवासी बन सकते हैं और हमारे शानदार स्टार्टअप माहौल का हिस्सा बन सकते हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य से 24 घंटे में 26 जहाज निकले

दुबई, रायटर : ईरानी रिवोल्यूशरी गार्ड नेवी ने बुधवार को बताया कि उसके देश के साथ समन्वय करके पिछले 24 घंटों के दौरान तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और अन्य कमर्शियल जहाज समेत 26 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकले। इस जलमार्ग से आवागमन जारी है। इधर, ट्रंप के अमेरिका-ईरान वार्ता अंतिम चरण वाले बयान के बाद कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है। कच्चा तेल चार प्रतिशत की गिरावट के साथ 106 डालर प्रति बैरल हो गया है।

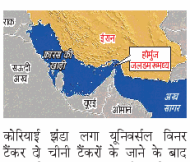

शिपिंग डाटा फर्म केप्लर व एलएसईजी के अनुसार, बुधवार को तीन सुपरटैंकर होर्मुज से गुजरे। ये टैंकर एशियाई बाजारों के लिए तेल लेकर जा रहे हैं और खाड़ी में पिछले दो महीने से भी ज्यादा समय से फंसे रहे। इन पर कुल 60 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है। इस दौरान एक तेल टैंकर ने होर्मुज में प्रवेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण

कोरियाई झंडा लगा यूनिवर्सल विनर टैंकर दो चीनी टैंकरों के जाने के बाद होर्मुज से निकला। कोरियाई टैंकर में चार मार्च को कुवैत से 20 लाख बैरल तेल भरा गया था। यह तब से क्षेत्र में फंसा था। जबकि दो चीनी सुपरटैंकर पर 40 लाख बैरल कच्चा तेल है। बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद से इस जलमार्ग से आवाजाही बाधित था। होर्मुज के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि वैश्विक तेल खपत का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है।

चिनफिंग व पुतिन ने मिलकर की ट्रंप की निंदा

- पिछले हफ्ते ट्रंप के बीजिंग दौरे को दोनों पक्षों ने बताया था ऐतिहासिक
- पश्चिम एशिया की लड़ाई को अविलंब खत्म करने के लिए भी कहा

बीजिंग, रायटर : चीन और रूस ने एकजुट होकर अमेरिका की नीतियों की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के बीजिंग दौरे को द्विपक्षीय संबंधों में विकास के लिहाज से ऐतिहासिक बताने और उसे लेकर अन्य बड़े दावे चंद रोज में ही खारिज हो गए हैं।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड प्लान और अमेरिका की गैरजिम्मेदाराना परमाणु नीति की निंदा की है। साथ ही पश्चिम एशिया में लड़ाई और तनाव अविलंब खत्म किए जाने के लिए कहा है।

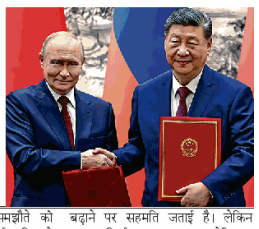

पुतिन और चिनफिंग ने संयुक्त बयान में कहा है कि भूमि से अंतरिक्ष में जाकर मिसाइल हमले को रोकने वाला अमेरिकी डिफेंस सिस्टम विकसित होने से वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा होगा। दोनों नेताओं ने अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों को सीमित करने वाले समझौते के नवीनीकरण को लेकर ट्रंप की अनिच्छा की भी निंदा की है। विदित हो कि इस समझौते को भविष्य में भी जारी रखने की पुतिन ने अमेरिका से कई बार अपील की लेकिन अमेरिका ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। विदित हो कि विश्व में सर्वाधिक करीब छह हजार परमाणु हथियार रूस के पास हैं और अमेरिका के पास इससे कुछ कम हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और चीन का द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। वार्षिक व्यापार का यह आकार 228 अरब डालर को पार कर गया है। पुतिन के ताजा दौरे में भी दोनों देशों ने व्यापार को और बढ़ाने पर सहमति जताई है। लेकिन 2,600 किमी पावर आफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को लेकर समझौता नहीं हो सका जबकि इसके लिए पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही है। शी और पुतिन बीते 13 वर्षों में 41 बार मिल चुके हैं। दोनों नेताओं ने 2022 में समझौता किया है, इसमें दोनों देशों के सहयोग को सीमाओं से परे बताया गया है। शायद इसीलिए पुतिन के बीजिंग पहुंचने पर चिनफिंग और ट्रंप के बीच हुए वादे और जी 7 की जगह जी 2 के आकार लेने की परिकल्पना हवा हो गई।

बीजिंग में बुधवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाते चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग। एएफपी >>

अमेरिका में मां-बेटे की हत्या में वांछित भारतीय नागरिक पर आरोप तय

न्यूयार्क, प्रेट्र : अमेरिका के न्यू जर्सी में 2017 में मां और उसके छह वर्षीय बेटे की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में वांछित एक भारतीय नागरिक के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए गए हैं। नजीर हमीद पर मार्च 2017 में भारतीय महिला शशिकला नर्रा और उसके बेटे अनीश नर्रा की हत्या का आरोप है।

एफबीआई ने सोमवार को हमीद के खिलाफ संघीय आरोपों की घोषणा की। बर्लिंगटन काउंटी अभियोजक कार्यालय और मेपल शेड पुलिस ने उस पर प्रथम श्रेणी हत्या के दो आरोप लगाए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि हमीद हत्याओं के छह महीने बाद भारत चला गया था। जांच के दौरान पता चला कि वह पीड़िता के पति हनुमंत नर्रा का भी पीछा कर रहा था। हमीद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया और एफबीआइ ने गिरफ्तारी के लिए 50,000 अमेरिकी डालर तक का इनाम देने की घोषणा की है।

क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिका में लगाया गया अभियोग

- पिछले कुछ समय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए बना रहे दबाव

वाशिंगटन, रायटर: ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर अमेरिका में अभियोग लगाया गया है। यह घटना क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह अभियोग ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, जहां कास्त्रो के कम्युनिस्ट उनके दिवंगत भाई फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में 1959 में हुई क्रांति के बाद से सत्ता में हैं। बुधवार को जारी एक बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी धरती से महज नब्बे मील की दूरी पर शत्रुतापूर्ण विदेशी सैन्य, खुफिया और आतंकी गतिविधियों को पनाह देने वाले किसी भी देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने सोमवार को कहा कि यह द्वीप किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। इस अभियोग से शीत युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वी रहे इन दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होंगे। सत्ता संभालने के बाद, फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन किया और फिर अमेरिकी नागरिकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। तब से अमेरिका ने इस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है।

राउल कास्त्रो। फाइल

लिथुआनिया और एस्टोनिया में ड्रोन से मची अफरातफरी

विलनियस, एपी : लिथुआनिया की राजधानी विलनियस में बुधवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब सीमा पार बेलारूस से ड्रोन आने का अलार्म बजा। इसके बाद देश के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा और प्रधानमंत्री इनगा रुजिनिएन को भूमिगत शेल्टर हाउस में भेजा गया। संसद भवन को सांसदों से खाली करा लिया गया और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए संदेश भेज दिए गए। हवाई अड्डे पर विमानों का आवागमन भी रोक दिया गया।

इस अलार्म के बाद नाटो के लड़ाकू विमान भी आकाश में गश्त करने लगे। लेकिन एक घंटा बाद जब ड्रोन ने सीमा पार नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली और इसके बाद व्यवस्थाएं सुचारु की गईं। विदित हो कि बेलारूस रूस का मित्र राष्ट्र है और बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार और मिसाइलें तैनात हैं। इससे पहले एस्टोनिया के आकाश में यूक्रेन का ड्रोन आ गया।

'ताइवान के भविष्य का फैसला बाहरी ताकतें नहीं कर सकतीं'

- ताइवानी राष्ट्रपति ने चीन, अमेरिका को दिया यह संदेश
- कहा, यह द्वीपीय क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा

ताइपे, रायटर : ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बुधवार को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर चीन के साथ ही अमेरिका को भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ताइवान के भविष्य का फैसला बाहरी ताकतें नहीं कर सकतीं। लोकतांत्रिक रूप संचालित यह द्वीपीय क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा।

लाई का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उन्हें न केवल चीन, बल्कि पारंपरिक रूप से ताइवान के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका के दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन लाई को अलगाववादी कहता है, जबकि ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह बीजिंग का दौरा किया था, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ शिखर वार्ता हुई थी। शिखर वार्ता के बाद ट्रंप ने कहा था कि ताइवान को आगे की हथियार बिक्री पर निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता के लिए 9,500 मील (करीब 15 हजार किलोमीटर) दूर जाकर युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है। लाई ने राष्ट्रपति कार्यालय में कहा, 'ताइवान का भविष्य बाहरी ताकतों द्वारा तय नहीं किया जा सकता। न ही इसे डराकर, विभाजन या तात्कालिक हितों द्वारा बंधक बनाया जा सकता है। ताइवान का भविष्य इसके 2.3 करोड़ लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताएंगे कि वह अमेरिका से हथियार खरीद जारी रखने की उम्मीद करते हैं। ट्रंप को यह भी बताएंगे कि चीन शांति को कमजोर कर रहा है।

बांग्लादेश पुलिस ने भारतीय अधिकारी का शव उच्चायोग को सौंपा

ढाका, एएनआइ: बांग्लादेश पुलिस ने भारतीय सहायक उच्चायोग के प्रोटोकाल अधिकारी नरेन धर का शव पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया है।

मंगलवार को चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग परिसर के अंदर नरेन धर का शव मिला था। हालांकि अभी तक मृत्यु का आधिकारिक कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों को फिलहाल किसी भी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है। शव मिलने के बाद भारतीय उच्चायोग ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया। चटगांव महानगर पुलिस (सीएमपी) ने मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएमपी के पुलिस आयुक्त हसन मोहम्मद शौकत अली ने बताया कि नरन धर का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और हमने उनका शव भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया है।

बल्लेबाज	रन
वैभव सूर्यवंशी	579
मिशेल मार्श	563
हेनरिक क्लासेन	555

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	24
कैगिसो रबाडा	21
अंशुल कंबोज	20

उम्र के हिसाब से वैभव की क्षेत्ररक्षण क्षमता काफी परिपक्व : जुबिन

- रायल्स के पूर्व निदेशक बोले, उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा फुर्तीले होंगे
- वैभव को टेस्ट में ओपनिंग की जगह मध्यक्रम में मौका दिया जाए

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट में इन दिनों जिस युवा खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहले ही क्रिकेट जगत का ध्यान खींच चुके वैभव को अब केवल एक आक्रामक बल्लेबाज नहीं, बल्कि भविष्य के संपूर्ण क्रिकेटर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर और मोहम्मद कैफ उनके क्षेत्ररक्षण पर कई बार सवाल उठा चुके हैं।

इंपैक्ट सब में उतरने के कारण सूर्यवंशी को क्षेत्ररक्षण का मौका नहीं मिलता है। इस पर मांजरेकर ने कहा था कि हमें इंपैक्ट सब के नियम को खत्म कर देना चाहिए। क्या आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में बस यही एक पहलू (बल्लेबाजी) देखना चाहते हैं? क्या एक क्रिकेटर वह नहीं होता जो अच्छी बल्लेबाजी के साथ-साथ अच्छा क्षेत्ररक्षण भी करता हो? पहले हम इंजमाम-उल-हक की बल्लेबाजी की तो इज्जत करते ही थे, लेकिन हमने उनका दूसरा पहलू भी देखा था, एक क्षेत्ररक्षक के तौर पर या किसी भी और रूप में। और इससे हमें उस खिलाड़ी को सही ढंग से समझने और उसका आकलन करने में मदद मिलती थी। यही नहीं कमेंट्री के दौरान कैफ ने इस बात की ओर इशारा किया था कि वैभव ने इस आइपीएल सत्र में अब तक एक भी कैच नहीं पकड़ा है। उन्होंने राजस्थान रायल्स के कोचिंग स्टाफ से आग्रह किया था कि वे युवा खिलाड़ियों की फील्डिंग पर काम करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी फुर्ती बेहतरीन बनी रहे। जब इस बारे में राजस्थान रायल्स के पूर्व क्रिकेट संचालन निदेशक जुबिन भरूचा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैभव में बल्लेबाजी के साथ-साथ क्षेत्ररक्षण, खेल को पढ़ने की क्षमता और टीम भावना जैसी दुर्लभ खूबियां मौजूद हैं, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती हैं।

जुबिन ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहा कि वैभव की क्षेत्ररक्षण की क्षमता उनकी उम्र के हिसाब से काफी परिपक्व है। उनके हाथ बेहद सुरक्षित हैं और मैदान पर उनकी मूवमेंट भी प्रभावशाली मानी जाती है। उनके पास अपने क्षेत्ररक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए सभी चीजें हैं। जैसे-जैसे उनकी शारीरिक क्षमता और फिटनेस बेहतर होगी, वे और अधिक तेज, चुस्त और फुर्तीले खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि जुबिन यह भी मानते हैं कि आधुनिक क्रिकेट में हर खिलाड़ी को अपने क्षेत्ररक्षण पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है और वैभव ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनमें सीखने की तीव्र इच्छा है और वे अपने खेल के हर हिस्से को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं।

तीनों प्रारूपों में खेलने की क्षमता

वैभव के साथ उनकी बल्लेबाजी पर काम कर चुके भरूचा ने कहा कि वह केवल टी-20 क्रिकेट तक सीमित खिलाड़ी नहीं हैं। उनमें टेस्ट क्रिकेट सहित खेल के तीनों प्रारूपों में सफल होने की क्षमता मौजूद है। खासकर उनका फ्रंट-फुट मूवमेंट उन्हें लंबी पारी खेलने के लिए उपयुक्त बनाता है क्योंकि वह किसी भी लेंथ की गेंद पर पहले से ही कोई शाट खेलने का इरादा नहीं रखते। वह गेंद को समझते हैं और फिर शाट खेलते हैं। जुबिन का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत में उन्हें ओपनिंग की जगह मध्यक्रम या नंबर छह पर मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह दबाव को समझते हुए धीरे-धीरे अपने खेल को विकसित कर सकें।

बल्लेबाजी तकनीक ने बदली 'गुड लेंथ' की परिभाषा: वैभव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अनोखी बल्लेबाजी तकनीक को लेकर है। जुबिन ने कहा कि वैभव पारंपरिक बल्लेबाजी शैली से बिल्कुल अलग खेलते हैं। सामान्य बल्लेबाज लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर वजन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वैभव का पूरा संतुलन और ताकत बैकफुट पर बनी रहती है। यहां तक कि जब उनका अगला पैर आगे जाता है, तब भी शरीर का वजन पूरी तरह उस पैर पर नहीं आता। यही कारण है कि पारंपरिक 'गुड लेंथ' गेंदें उनके विरुद्ध प्रभावी नहीं दिखतीं। वैभव ने अपनी तकनीक के दम पर यह बदल दिया है कि उनके लिए अच्छी लेंथ की गेंद वास्तव में क्या है। जुबिन ने कहा कि उनकी बल्लेबाजी में चौड़े बैकलिफ्ट और अनोखे बैट स्विंग की भी बड़ी भूमिका है। इसी तकनीक की वजह से वह मिड-आन, लांग-आन और मिड-विकेट के ऊपर से समान सहजता के साथ बड़े शाट लगा सकते हैं। वैभव गेंद को अन्य बल्लेबाजों की तुलना में कहीं ज्यादा चौड़े एंगल में खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी पीठ का झुकाव, डाउनस्विंग और बैट का एंगल उन्हें अलग स्तर का पावर गेम प्रदान करता है।

वैभव सूर्यवंशी ● फाइल फोटो

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका

राजस्थान रायल्स में वैभव को शुरुआत से देखने वाले जुबिन से जब पूछा गया कि क्या इस 15 साल के खिलाड़ी को अब अंतरराष्ट्रीय टीम में मौका दे देना चाहिए या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि वैभव को अब बड़े स्तर पर अवसर मिलना चाहिए। इतनी कम उम्र में जिस तरह की तकनीक, आत्मविश्वास और मैच की समझ वैभव ने दिखाई है, वह असाधारण है। वह केवल तकनीकी रूप से मजबूत खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान क्रिकेटर भी हैं। वह हमेशा विपक्षी टीम से कुछ कदम आगे सोचने की कोशिश करते हैं। वैभव की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक उनकी टीम भावना भी है। वह अपने साथी खिलाड़ियों की सफलता से उतनी ही खुशी महसूस करते हैं जितनी अपनी उपलब्धियों से। इतनी कम उम्र में यह परिपक्वता बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलती है।

गेंदबाजों ने जीवित रखी कोलकाता की आस

मुंबई को चार विकेट से हराकर **प्लेआफ की दौड़ में बरकरार केकेआर** ग्रीन-दुबे और कार्तिक ने झटके दो-दो विकेट

विशाल श्रेष्ठ ● जागरण

कोलकाता : ईडन गार्डेंस स्टेडियम में बुधवार को एक और 'करो या मरो' के मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स ने शानदार गेंदबाजी के बूते मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हरा दिया। मुंबई ने कोलकाता के सामने 148 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे केकेआर ने 18.5 ओवर में छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के एक समय 54 रनों पर तीन विकेट गिर चुके थे। मनीष पांडेय (45) व रोवमैन पावेल (40) ने बेहतरीन साझेदारी निभाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया।

इस जीत के साथ कोलकाता की प्लेआफ में पहुंचने की उम्मीद कायम है। कोलकाता को अब दिल्ली के विरुद्ध अपना अंतिम मैच जीतना होगा जो रविवार को ईडन में ही होगा, हालांकि इसके साथ पंजाब व राजस्थान के मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा।

पावरप्ले में चौका: कोलकाता ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो कारगर साबित हुआ। तीसरा ओवर डालने आए कैमरन ग्रीन ने मुंबई को दोहरा झटका दिया। उन्होंने पहले रियान रिकल्टन (06) व उसके बाद नमन धीर (00) को पवेलियन भेजा। तेज गेंदबाज सौरव दुबे ने रोहित शर्मा (15) व सूर्यकुमार यादव (15) को आउट कर मुंबई की परेशानी बढ़ा दी। मुंबई ने इस सत्र में पहली बार पावरप्ले में चार विकेट गंवाए। उसका इस सत्र में यह दूसरा न्यूनतम स्कोर भी है। सबसे कम स्कोर चेन्नई के विरुद्ध 104 रन का है।

रोहित, सूर्य, हार्दिक सब फ्लाप: कोलकाता के गेंदबाजों के आगे रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रियान रिकल्टन व हार्दिक पांड्या जैसे धाकड़ बल्लेबाजों की एक न चल पाई। पुछल्ले बल्लेबाज कार्बिन बाश ने अगर 18 गेंदों पर अविजित 32 रनों की पारी न खेली होती तो मुंबई 140 का आंकड़ा भी पार न कर पाती। बाश ने शानदार गेंदबाजी कर तीन विकेट भी चटकाए, हालांकि यह उसकी टीम के काम न आया।

बारिश ने रोक दी थीं सांसें: कोलकाता में बुधवार दोपहर तक कड़ी धूप निकली हुई थी लेकिन शाम होते-होते आसमान में काले बादल घिरने लगे और बारिश शुरू हो गई। इससे कोलकाता खेमा चिंता में पड़ गया था क्योंकि मैच रद होने पर टीम को बाहर होना पड़ता। वर्षा बारिश के कारण शाम 4.30 बजे तक ईडन की पिच समेत पूरे ग्राउंड को ढंककर रखा गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और मैच निर्धारित समय पर ही शुरू हुआ, हालांकि आठ ओवर का खेल समाप्त होते ही फिर से बारिश शुरू हो गई। कोलकाता टीम फिर चिंता में पड़ गई क्योंकि वह बहुत बेहतर स्थिति में थी। करीब एक घंटे के व्यवधान के बाद रात 9.15 बजे खेल फिर शुरू हुआ और ओवर में कोई कटौती नहीं की गई।

नमन धीर का विकेट लेने के बाद खुशी से उछलते कैमरन ग्रीन ● एएफपी

चोट के बावजूद खेल रहे वरुण

कोलकाता के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के दौरान लड़खड़ाते दिखे, जिससे साफ हो गया कि वे पैर की चोट से अभी भी पूरी तरह उबरे नहीं हैं। कमेंटेटरों व पूर्व क्रिकेटरों का एक वर्ग इसके लिए वरुण की प्रशंसा कर रहा है, हालांकि एक वर्ग इसे कोलकाता टीम व खुद वरुण की गैर-जिम्मेदाराना हरकत बता रहा है। इस बीच बीसीसीआइ के सचिव का कहना है कि आइपीएल के दो महीने के दौरान उसका केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता।

स्कोर बोर्ड

मुंबई इंडियंस : 147/8 (0 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रिकल्टन का. मनीष बो. ग्रीन	6	7	1/0
रोहित का. ग्रीन बो. सौरव	15	13	0/2
नमन का. अंगकृष बो. ग्रीन	0	3	0/0
सूर्यकुमार बो. सौरव	15	6	2/1
तिलक का. अनुकूल बो. कार्तिक	20	32	0/1
हार्दिक बो. सुनील	26	27	2/1
जैक्स रन आउट	14	7	1/1
बाश अविजित	32	18	3/2
चाहर का. अनुकूल बो. कार्तिक	10	7	2/0

अतिरिक्त : 9 (बा : 4, लेबा : 2, वा : 3), विकेटपतन : 1-17 (रिकल्टन, 2.3), 2-17 (नमन, 2.6), 3-23 (रोहित, 3.5), 4-41 (सूर्यकुमार, 5.3), 5-84 (तिलक, 13.4), 6-95 (हार्दिक, 15.2), 7-105 (जैक्स, 16.4), 8-147 (चाहर, 19.6), गेंदबाजी : अनुकूल 1-0-6-0, सौरव 4-0-34-2, ग्रीन 3-0-23-2, कार्तिक 4-0-37-2, सुनील 4-0-13-1, वरुण 4-0-28-0

कोलकाता नाइट राइडर्स : 148/6 (18.5 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रहाणे का. रिकल्टन बो. बाश	21	17	4/0
एलन बो. चाहर	8	5	2/0
मनीष बो. बुमराह	45	33	6/0
ग्रीन का. गजनफर बो. बाश	4	8	0/0
पावेल का. बाश बो. गजनफर	40	30	4/2
रिंकू अविजित	9	5	2/0
तेजस्वी का. रिकल्टन बो. बाश	11	12	2/0
अनुकूल अविजित	4	4	0/0

अतिरिक्त : 6 (लेबा : 1, नोबा : 1, वा : 4)

विकेटपतन : 1-10 (एलन, 0.6), 2-48 (रहाणे, 5.4), 3-54 (ग्रीन, 7.1), 4-118 (मनीष, 14.6), 5-124 (पावेल, 15.2), 6-140 (तेजस्वी, 17.5)

गेंदबाजी : चाहर 3-0-23-1, बुमराह 4-0-26-1, बाश 3-0-30-3, गजनफर 4-0-25-1, हार्दिक 2-0-13-0, रघु 2-0-23-0, जैक्स 0.5-0-7-0

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	आरसीबी (Q)	13	9	4	0	+1.065	18
2	गुजरात (Q)	13	8	5	0	+0.400	16
3	हैदराबाद (Q)	13	8	5	0	+0.350	16
4	राजस्थान	13	7	6	0	+0.083	14
5	पंजाब	13	6	6	1	+0.227	13
6	कोलकाता	13	6	6	1	+0.011	13
7	चेन्नई	13	6	7	0	-0.016	12
8	दिल्ली	13	6	7	0	-0.871	12
9	मुंबई (E)	13	4	9	0	-0.510	8
10	लखनऊ (E)	13	4	9	0	-0.702	8

शीर्ष दो में जगह बनाने की कोशिश में टाइटंस

अहमदाबाद, प्रेट्र : प्लेआफ में पहले ही अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी गुजरात टाइटंस की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के विरुद्ध गुरुवार को होने वाले आइपीएल के मैच में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखकर शीर्ष दो में जगह पक्की करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लीग चरण में शीर्ष दो स्थानों पर रहने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के दो अवसर मिलते हैं।

गुजरात टाइटंस अभी 16 अंक लेकर तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (18 अंक) पहले स्थान पर है। इन दोनों के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद (16 अंक) भी शीर्ष दो में जगह बनाने की दौड़ में है। इन तीनों टीम ने पहले ही प्लेआफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अगर गुजरात टाइटंस सीएसके की विरुद्ध बड़ी जीत दर्ज करता है तो वह रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के (+1.065) नेट रन रेट से भी आगे निकल सकता है। अगर सनराइजर्स अपने आखिरी लीग मैच में आरसीबी को हरा देता है तो पहले दो स्थान के लिए फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। अभी गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट (+0.400) है जो सनराइजर्स (+0.350) से बेहतर है। पिछले मैच में सनराइजर्स के हाथों हार के कारण सीएसके की प्लेआफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसे में पांच बार की पूर्व चैंपियन सीएसके सत्र के अंतिम मैच में प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी।

शुभमन गिल

रुतुराज गायकवाड़

रुतुराज गायकवाड़ की अगुआई वाली टीम सीएसके टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है और प्लेआफ में अंतिम स्थान के लिए दावेदारी में बने रहने के लिए उसे गुजरात के विरुद्ध जीत के साथ अन्य मैचों के परिणाम भी अपने अनुकूल रहने के लिए प्रार्थना करनी होगी।

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच पर होने वाले इस मुकाबले से पहले टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके प्रारंभिक जोड़ीदार साई सुदर्शन शानदार फार्म में हैं।

सीएसके के गेंदबाजों के लिए उन पर अंकुश लगाना बड़ी चुनौती होगी। बीच के ओवरों में भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकता है जिसमें गुजरात टाइटंस के स्टार स्पिनर राशिद खान सीएसके की मजबूत बल्लेबाजी पंक्ति की परीक्षा लेंगे।

बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ

सिलहट, एपी: ताइजुल इस्लाम ने छह विकेट लेकर पाकिस्तान को बुधवार को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 358 रन पर समेट दिया, जिससे बांग्लादेश ने 78 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल ने पांचवें दिन गिरे तीन में से दो विकेट हासिल किए और 34.2 ओवर में 120 रन देकर छह विकेट चटकाए। उन्होंने चौथे दिन ही पाकिस्तान को 316/7 पर रोकने में अहम भूमिका निभाई थी।

पाकिस्तान ने पांचवें दिन सुबह 42 रन जोड़े, लेकिन फिर 13 गेंदों के भीतर बिना कोई रन जोड़े तीन विकेट गंवा दिए और बांग्लादेश ने तेजी से जीत अपने नाम कर ली। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 104 रन से जीता था। यह पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश की लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें उसने क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले उसने 2024 में भी पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। रिजवान की जुझारू पारी के खत्म होते ही पाकिस्तान की 437 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीद भी समाप्त हो गई।

ट्राफी के साथ बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी ● एएफपी

> जहां तक मोहम्मद रिजवान का सवाल है, मुझे लगता है कि उन्हें साइट स्क्रीन को लेकर शिकायत करने या नाटकीय हरकतें करने में कम समय बिताना चाहिए और अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। शायद तब दर्शक उनसे इतने नाराज नहीं होते।
> – **लिटन दास**, विकेटकीपर, बांग्लादेश

दलीप ट्राफी के साथ 23 अगस्त से शुरू होगा घरेलू क्रिकेट सत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2026-27 घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत 23 अगस्त से दलीप ट्राफी के साथ होगी, जबकि रणजी ट्राफी एक बार फिर दो चरणों में खेली जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी। बीसीसीआइ ने बुधवार को यह घोषणा की। आगामी सत्र के दौरान बीसीसीआइ आयु वर्ग और सीनियर क्रिकेट में कुल 1788 मुकाबलों का आयोजन करेगा जिसमें पुरुषों के लिए अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 के अलावा सीनियर स्तर जबकि महिलाओं के लिए अंडर-15, अंडर-19 और अंडर-23 के अलावा सीनियर स्तर के मुकाबले शामिल हैं।

बीसीसीआइ ने बुधवार को कहा, '2026-27 का घरेलू सत्र बीसीसीआइ की एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू ढांचा बनाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथ ही यह सभी प्रारूप और वर्ग में संतुलित प्रगति भी सुनिश्चित करता है। दलीप ट्राफी का पूरा टूर्नामेंट बेंगलुरु के बीसीसीआइ के सेंटर आफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। बीसीसीआइ के घरेलू कैलेंडर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता रणजी ट्राफी का पहला चरण 11 अक्टूबर से पांच नवंबर के बीच होगा जिसमें चार दौर खेले जाएंगे। दूसरा चरण 17 जनवरी से तीन मार्च 2027 के बीच होगा जो सैयद मुश्ताक अली ट्राफी (टी20) और विजय हजारे ट्राफी (50 ओवर) के खत्म होने के बाद खेला जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के लीग चरण के मुकाबले मुंबई, मोहाली, विशाखापत्तनम और कोलकाता में होंगे जबकि नाकआउट चरण नागपुर में होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी से आइपीएल की विभिन्न फ्रेंचाइजी को नीलामी से पहले अपनी सूची तैयार करने का मौका मिलेगा। आइपीएल की नीलामी दिसंबर में होगी।

बीसीसीआइ की कार्यक्रम तैयार करने वाली टीम ने विजय मर्चेंट ट्राफी (अंडर-16) नवंबर से जनवरी के बीच कराने का फैसला किया है जिससे स्कूली क्रिकेटरों को अपनी सालाना या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने में भी आसानी होगी जो आम तौर पर फरवरी और मार्च में होती हैं। अंडर-23 वर्ग का सीमित ओवरों का टूर्नामेंट और विजी ट्राफी के लिए अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता टी20 प्रारूप में खेली जाएगी।

महिलाओं का घरेलू सत्र सीनियर महिला टी20 ट्राफी (एलीट) के साथ शुरू होगा, जो 26 अक्टूबर से छह नवंबर तक लखनऊ, पुणे, नई दिल्ली और मोहाली में चलेगा। इसके नाकआउट मैच 14 से 20 नवंबर तक अहमदाबाद में होंगे, जबकि प्लेट ग्रुप के मैच और नाकआउट 26 अक्टूबर से चार नवंबर तक दीमापुर में खेले जाएंगे। सीनियर महिला वनडे ट्राफी (एलीट) 19 से 31 दिसंबर तक कटक, जयपुर, बड़ौदा और रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसके बाद चार से 10 जनवरी तक चेन्नई में नाकआउट मैच खेले जाएंगे।

घरेलू कार्यक्रम

- 11 अक्टूबर से होगी रणजी ट्राफी, दो चरणों में होगा टूर्नामेंट
- 17 जनवरी से तीन मार्च 2027 तक चलेगा दूसरा चरण
- 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में होंगे दलीप ट्राफी के मैच
- 5 अक्टूबर से श्रीनगर में शेष भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच होगा ईरानी कप मैच
- 14 नवंबर से छह दिसंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्राफी (टी-20) खेली जाएगी
- 14 दिसंबर 2026 से आठ जनवरी 2027 तक विजय हजारे ट्राफी (वनडे) आयोजित होगी

खेल डायरी

मालविका और अश्मिता दूसरे दौर में

कुआलालंपुर, प्रेट्र: भारत के लिए मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में निराशाजनक दिन में मालविका बंसोड़ और अश्मिता चालिहा ही उम्मीद की किरण बनकर उभरीं जिन्होंने महिला सिंगल्स में अलग-अलग अंदाज में जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई। एसीएल (एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट) चोट से उबरने के बाद वापसी कर रही मालविका ने जर्मनी की दुनिया की 52वें नंबर की खिलाड़ी यवोन ली को 21-17, 16-21, 21-9 से शिकस्त दी। वहीं, अश्मिता ने इंडोनेशिया की दुनिया की 56वें नंबर की खिलाड़ी थालिता रमाधनी विरियावान पर 21-16, 21-13 से आसान जीत दर्ज की। मालविका डेनमार्क की होजमार्क कजर्सफेल्ट से भिड़ेंगी जबकि अश्मिता का सामना गोह जिन वेई से होगा।

हाकी कोच बलदेव पद्मश्री से होंगे सम्मानित

नई दिल्ली, प्रेट्र: हाकी कोच बलदेव सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बलदेव (75 वर्ष) ने एनएच 44 पर बसे छोटे से शहर शाहाबाद मारकंडा को बेहतरीन हाकी प्रतिभा पैदा करने का एक बड़ा केंद्र बना दिया। वह 1982 में हरियाणा खेल विभाग में कोच के तौर पर शाहाबाद मारकंडा आए थे और उन्होंने वहां चार साल तक सेवा दी। अधिकारियों ने बताया कि 1993 में वह इस शहर में वापस लौटे और उन्होंने इस हाकी नर्सरी को सबसे ज्यादा हाकी प्रतिभा पैदा करने वाले केंद्र में से एक बना दिया।

आर्सेनल 22 साल बाद बना इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन

लंदन, एपी: आर्सेनल का 22 वर्षों से चला आ रहा इंतजार अंततः खत्म हो गया। मंगलवार रात मैनचेस्टर सिटी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रा होने के साथ ही मिकेल आर्टेटा की टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। इस परिणाम के साथ आर्सेनल ने तालिका में चार अंकों की अजेय बढ़त हासिल कर ली, जिसे अंतिम मुकाबले में भी मैनचेस्टर सिटी पार नहीं कर सकती। क्लब ने 2004 के बाद पहली बार ट्राफी जीती है।

खिताब पक्का होते ही लंदन स्थित एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसकों ने जश्न मनाया। समर्थकों ने आतिशबाजी की, फ्लेयर्स जलाए और सड़कों पर देर रात तक उत्सव चलता रहा। टीम के खिलाड़ी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में एकत्र होकर सिटी और बोर्नमाउथ का मैच देख रहे थे। आर्सेनल के मिडफील्डर डेक्लान राइस ने इंटरनेट मीडिया पर टीम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मैंने आप सबसे कहा था काम पूरा हो गया।

मैनचेस्टर सिटी को खिताबी दौड़ बनाए रखने के लिए बोर्नमाउथ को हराना जरूरी था, लेकिन टीम ऐसा नहीं कर सकी। जूनियर क्राउपी ने पहले हाफ में बोर्नमाउथ को बढ़त दिलाई। इसके बाद एर्लिंग हालैंड ने इंजरी टाइम में बराबरी का गोल जरूर किया, लेकिन जीत दिलाने वाला दूसरा गोल नहीं आ सका।

आर्टेटा ने बदला आर्सेनल का भाग्य: मिकेल आर्टेटा के लिए यह सफलता बेहद खास है। पिछले तीन सीजन में उनकी टीम लगातार उपविजेता रही थी। 2023 और 2024 में मैनचेस्टर सिटी ने अंतिम दौर में आर्सेनल को पीछे छोड़कर खिताब जीता था, जबकि पिछले वर्ष लिवरपूल चैंपियन बना था। दिसंबर 2019 में आर्सेनल की कमान संभालने वाले आर्टेटा का यह पहला लीग खिताब है। 44 वर्षीय स्पेनिश कोच प्रीमियर लीग जीतने वाले जोस मोरिन्हो के बाद दूसरे सबसे युवा मैनेजर बन गए हैं। आर्सेनल ने इस सीजन शानदार रक्षात्मक खेल के दम पर सफलता हासिल की। टीम ने लीग में सबसे मजबूत डिफेंस दिखाया और सेट-पीस गोलों में विशेष महारत दिखाई।

इनविंसिबल्स के बाद पहली बार चैंपियन: आर्सेनल ने आखिरी बार 2004 में प्रीमियर लीग जीती थी, जब आर्सेन वेंगर की मशहूर 'इनविंसिबल्स' टीम पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं हारी थी। उसके बाद चेल्सी, मैनचेस्टर युनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लीसेस्टर सिटी और लिवरपूल जैसी टीमों ने खिताब जीते। 2017 के बाद यह पहला मौका है जब सिटी या लिवरपूल के अलावा किसी क्लब ने ट्राफी जीती।

आर्सेनल के चैंपियन बनने के साथ ही एमिरेट्स स्टेडियम के बाहर आर्सेनल के प्रशंसक जश्न मनाते हुए ● रायटर

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

कमेंटेटर क्रिकेट पर बात करें : रियान पराग

जयपुर, प्रेट्र: राजस्थान रायल्स के कप्तान रियान पराग ने आइपीएल के दौरान निजी तौर पर उनको निशाना बनाने वाले टीवी कमेंटेटरों और विशेषज्ञों पर पलटवार करते हुए उनसे खिलाड़ियों का सम्मान करने और क्रिकेट के बारे में बात करने तक ही सीमित रहने का आग्रह किया।

राजस्थान के कप्तान रियान ने कहा कि आइपीएल में इस साल बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि पूरा देश क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। हम खिलाड़ी जब भी मौका मिलता है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता। हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलतियां होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है, विशेषकर कमेंटेटर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे क्रिकेट से प्यार करें। क्रिकेट की बात करें।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का
गुरुवार, 21 मई, 2026

टेक टिप्स

भूल गए हैं वाइ फाइ पासवर्ड ये हैं आसान उपाय

घर में वाइ फाइ से कनेक्टेड डिवाइसेज में पासवर्ड वर्षों से लगा हुआ हैं, स्वाभाविक है कि यह हमेशा आपको याद भी नहीं रहेगा। अगर किसी नई डिवाइस को कनेक्ट करना हो या फिर गेस्ट के साथ पासवर्ड को साझा करना हो तो पासवर्ड याद करने के लिए आप दिमाग पर जोर डालना शुरू कर देते हैं या फिर पासवर्ड को पहले कहीं आपने लिखा है, तो उसे खोजना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अधिक परेशान होने के बजाय कनेक्टेड लैपटाप को ओपन करें, वहां आप कुछ ही क्लिक करके और कुछ ही सेकंड में पासवर्ड को जान जाएंगे। आइए जानें...

- विंडोज पर पासवर्ड जानने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और कंट्रोल पैनल पर जाएं।
- विंडोज11 है तो नेटवर्क एंड इंटरनेट आप्शन पर जाकर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को चुनें।
- विंडोज 10 है तो सेटिंग > नेटवर्क एंड इंटरनेट > स्टेटस > नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आप्शन को चुनें।
- कनेक्शन पर जाकर अपने वाइ फाइ नेटवर्क को टैप करें।
- वाइ फाइ स्टेटस पेज पर, वायरलेस प्राप्र्टीज पर क्लिक करें और फिर सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करें।
- अंत में अपने वाइ फाइ नेटवर्क का पासवर्ड ऊपर दिखाने के लिए 'शो कैरेक्टर्स' के बगल वाले बाक्स को चेक करें।

इन दिनों

इंटरनेट मीडिया पर हेल्थ इन्फ्लुएंसर सेहत को लेकर लोगों के बर्ताव और विश्वास दोनों को बदल रहे हैं। किसी उपचार तंत्र का हिस्सा नहीं होने के बावजूद ऐसे लोगों पर आम यूजर क्यों करते हैं भरोसा, आनलाइन माध्यमों से मिलने वाली जानकारी किस हद तक होती हैं सही, बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

● फोटो : मैग्नीफिक

सेहत का स्कैम

कुछ ही समय पहले की बात है, 'बालों को फिर से उगाने' और 'जड़ों के फालिकल्स' को बेहतर बनाने के दावे के साथ आदिवासी हेयर आयल से जुड़े खूब सारे वायरल वीडियो दिखते थे। सेलेब्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स और व्लागर्स तक, हर कोई इसे प्रमोट कर रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं, इस तेल का प्रयोग करने वालों की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही। इसी तरह विटामिन सप्लीमेंट्स से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने वाले पाउडर तक, शुगर-फ्री स्वीटनर्स से लेकर लो कैलोरी पैकेज्ड स्नैक्स के बेशुमार फायदे गिनाते इन्फ्लुएंसर्स आपको इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हर जगह दिख जाएंगे। वेलनेस और फिटनेस इंडस्ट्री को तो इन इन्फ्लुएंसर्स ने ग्लैमराइज ही कर दिया है। आपको वजन कम करना है, लंबे समय तक जीना है या तनाव को कम करना है या ब्लडशुगर नियंत्रित रखना है या फिर नींद में सुधार करना है, इसका जवाब देने के लिए इंटरनेट मीडिया पर अनगिनत रील्स मौजूद हैं।

यहां आपको टिप्स भी मिलेंगे और जरूरी प्रोडक्ट भी सुझाए जाएंगे। लाखों फालोअर्स वाले सेहत के ऐसे जानकारों पर लोग भरोसा भी करते हैं, भले ही डाक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इसके लिए बार-बार लोगों को आगाह करते रहें। सनस्क्रीन से कैंसर होता है और निकोटीन अल्जाइमर को ठीक कर सकता है, बिना दवाओं के डायबिटीज को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, जैसे बिना सिर-पैर वाले दावे मिलियन में व्यूज बटोर लेते हैं, वहीं डाक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल की बातें आभासी दुनिया के सक्रिय नागरिकों को बोरिंग लगने लगती हैं।

सेहत जरूरी, पर अज्ञानता से रहें सतर्क

यह सच है कि सेहत को लेकर लोगों में सतर्कता बढ़ी है और इंटरनेट की इसमें बड़ी भूमिका रही है। लोग बीमारियों के प्रति सतर्क हो रहे हैं, समय पर उपचार के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन यह सतर्कता खुद से इलाज करने या ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स या दवाएं खरीदने या फिर मेडिकल जानकारियों से खुद को और दूसरों को भ्रमित करने के रूप में नहीं होनी चाहिए। इसका दुष्प्रभाव बहुत गंभीर होता है। चिंताजनक यह है कि कई इन्फ्लुएंसर घरेलू नुस्खों, प्राचीन ज्ञान और सांस्कृतिक गौरव के नाम पर एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा के प्रति संदेह पैदा कर रहे हैं। इससे एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, जहां आसानी से प्रभावित होने वाले यूजर्स जान-बूझकर की जाने वाली अज्ञानता की संस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं।

क्यों प्रभावी सावित होते हैं इन्फ्लुएंसर्स

लोग फिटनेस, पोषण और सप्लीमेंट से जुड़ी हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर भरोसा कर रहे हैं। खास बात है कि इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर डाक्टर, डेंटिस्ट या नर्स जैसे पारंपरिक चिकित्सा पेशेवर नहीं होते। ये अक्सर अपनी बायो में खुद को डाइट या लाइफ कोच, पैरेंटिंग कोच, फिटनेस एक्सपर्ट या उद्यमी के तौर पर पेश करते हैं। लाखों फालोअर्स वाले ये इन्फ्लुएंसर अब सिर्फ यह तय नहीं करते कि हम क्या खरीदते हैं या क्या पहनते हैं। वे हमारी जीवनशैली से जुड़ी पसंद-नापसंद पर भी असर डालते हैं। हैरानी की बात है कि अधिकांश प्रभावी हेल्थ क्रिएटर्स किसी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं होने के बावजूद पेशेवर स्वास्थ्य अनुभव रखने का दावा करते हैं। इसी तरह वजन कम करने या कैंसर के उपचार में सफल होने वाले कुछ इन्फ्लुएंसर अपने अनुभव साझा करके लोगों का भरोसा जीतते हैं। यहां हमें समझने की जरूरत है कि किसी दूसरे व्यक्ति का निजी अनुभव खुद पर लागू करने से खतरे भी हो सकते हैं। कोई जानकारी गलत केवल इसलिए ही नहीं होती कि उसमें सच्चाई या तथ्य की कमी है, बल्कि इसलिए भी हो सकती है कि हर किसी की स्थिति-परिस्थिति अलग होती है।

हेल्थ और हाइप में समझना होगा अंतर

कुछ डाक्टर या स्वास्थ्य पेशेवर उपयोगी कंटेंट बना रहे हैं, पर वे कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिस्पर्धा में अक्सर पीछे रह जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि एक दशक में फिटनेस पर आधारित कंटेंट की भरमार के चलते वेलनेस इंडस्ट्री का आकार काफी बड़ा हो चुका है। न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आनलाइन वेलनेस कंटेंट देखने वाले यूजर्स अक्सर यह स्वीकार करते हैं, इंटरनेट से मिली जानकारी अक्सर डाक्टरों की सलाह से 'बेहद या बहुत अलग' होती है।

महत्वपूर्ण बातें

- सेहत से जुड़ी किसी जानकारी या दावे पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसके दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
- आनलाइन देखी या पढ़ी गई किसी स्वास्थ्य सलाह के मूल स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए।
- गौर करें कि क्या इन्फ्लुएंसर या जानकारी देने वाले के पास चिकित्सा संबंधी योग्यताएं हैं या नहीं।
- किसी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले, विचार करें कि क्या उससे कोई नुकसान हो सकता है।

सही जानकारी का क्या है तरीका

अगर आप डाक्टर या हेल्थ पेशेवर तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो रील्स या चैटबाट पर भरोसा करने के बजाय टेलीहेल्थ जैसे उपायों को देख सकते हैं। इसमें घर बैठे ही वीडियो काल या मेडिकल एक्सपर्ट के साथ चैट के जरिये आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे इलाज का खर्च भी कम हो जाता है। कुछ वर्चुअल फोरम भी होते हैं, जहां लोग अपनी पहचान उजागर किए बिना अनुभव साझा करने के साथ भावनात्मक सहायता और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाओं, कंपनियों के मोबाइल एप्स लोगों को स्वस्थ व्यवहार अपनाने, जरूरतों के अनुसार आहार संबंधी सलाह देने, दवा के रिमाइंडर व वियरेबल डिवाइस के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। सही जानकारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) आदि की वेबसाइट आपको बेशुमार जानकारियां उपलब्ध करा सकती हैं। फिर भी अगर इंटरनेट मीडिया पर ही जानकारी खोजना चाहते हैं, तो हेल्थ प्रोफेशनल्स के वीडियो, पाडकास्ट से आपको उपयोगी जानकारियां मिल जाएंगी।

आनलाइन जानकारी व इलाज में समझें अंतर

डा. ज्योति मिश्रा
साइकोलाजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा हास्पिटल, दिल्ली

इंटरनेट पर हर तरह की सलाह मिल जाती है, इसलिए लोग स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और लाइफस्टाइल से जुड़े फैसलों के लिए भी इस पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं, लेकिन हर जानकारी सही या वैज्ञानिक हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार अधूरी या गलत सलाह डर, चिंता और भ्रम बढ़ा देती है। खासतौर पर 'परफेक्ट लाइफ' के कंटेंट से लोग खुद की तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम हो सकता है। इंटरनेट जानकारी को अंतिम सच मान लेना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है और उसका समाधान भी अलग हो सकता है। जरूरी है कि आनलाइन सलाह को केवल सामान्य जानकारी की तरह लें, न कि इलाज की तरह। यदि कोई परेशानी है तो डाक्टर से सीधे बात करनी चाहिए। वास्तविक सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।

गूगल आइ/ओ 2026

गूगल ने दिखाई एआइ की नई दुनिया

गूगल आइ/ओ 2026 ने साफ कर दिया है कि एआइ जुड़ने से अब सर्च, यूट्यूब, जीमेल, एंड्रायड, वर्कस्पेस अधिक स्मार्ट बन जाएंगे। जानते हैं कि इससे आने वाले समय में कैसे बदलेगा काम करने का तरीका...

गूगल ने अपने सालाना डेवलपर इवेंट गूगल आइ/ओ 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। कंपनी ने जेमिनी 3.5 फ्लैश माडल, नया एआइ सर्च एक्सपीरियंस, एआइ एजेंट, यूट्यूब एआइ फीचर्स और एंड्रायड एक्सआर स्मार्ट ग्लासेज जैसे प्रोडक्ट्स और टेक्नोलाजी पेश की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि कंपनी हर महीने 3.2 क्वाड्रिलियन से ज्यादा एआइ टोकंस प्रोसेस कर रही है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग सात गुना ज्यादा है। इससे साफ है कि गूगल एआइ-फर्स्ट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जेमिनी 3.5 फ्लैश : गूगल का दावा है कि यह नया एआइ माडल मौजूदा माडल्स की तुलना में लगभग चार गुना ज्यादा तेज काम करता है। यह इतना पावरफुल है कि 12 घंटे में पूरा आपरेटिंग सिस्टम तैयार कर सकता है। फिलहाल जेमिनी 3.5 फ्लैश को जेमिनी एप और गूगल सर्च के एआइ मोड में उपलब्ध कराया गया है। डेवलपर्स इसे एआइ स्टूडियो और एंड्रायड स्टूडियो के जरिये भी उपयोग कर सकते हैं। जेमिनी 3.5 प्रो माडल अगले महीने लांच किया जाएगा।

जेमिनी ओम्नी : गूगल ने जेमिनी ओम्नी नाम का नया मल्टीमाडल वीडियो जनरेशन माडल भी पेश किया है। यह टेक्स्ट, फोटो, आडियो और वीडियो इनपुट को एक साथ समझकर नया वीडियो तैयार कर सकता है। यूजर कैमरा एंगल, सीन और मूड तक बता सकेंगे और एआइ उसी हिसाब से वीडियो बनाएगा। अगर कोई यूजर किसी ट्रैवल वीडियो जैसा सिनेमैटिक शाट बनाना चाहता है, तो सिर्फ रेफरेंस फोटो और टेक्स्ट प्राम्प्ट देकर वीडियो तैयार कर सकता है। फिलहाल यह गूगल एआइ प्लस, प्रो और अल्ट्रा यूजर्स के लिए उपलब्ध होने जा रहा है।

जेमिनी स्पार्क : गूगल ने जेमिनी स्पार्क नाम का नया पर्सनल एआइ एजेंट भी लांच किया है। यह लंबे समय तक चलने वाले टास्क बैकग्राउंड में पूरा कर सकता है यानी फोन या एप को लगातार खुला रखने की जरूरत नहीं होगी। यह गूगल क्लाउड के वर्चुअल मशीन पर रन करेगा। जेमिनी स्पार्क भविष्य में कई गूगल सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे मीटिंग शेड्यूल करने, रिसर्च करने, डाटा मैनेज करने और कई दूसरे काम बिना लगातार मैनुअल इनपुट दिए कर सकेंगे।

जीमेल, डाक्स व कीप में एआइ अपग्रेड

गूगल वर्कस्पेस एप्स, जैसे- जीमेल, गूगल डाक्स और गूगल कीप को नए एआइ फीचर्स मिले हैं। अब यूजर नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकेंगे, आइडिया जनरेट कर सकेंगे और वायस कमांड से नोट्स आर्गनाइज कर पाएंगे। जीमेल में नया एआइ इनबाक्स फीचर भी जुड़ा है, जिसमें पर्सनलाइज्ड ड्राफ्ट रिप्लाई, इंस्टेंट फाइल एक्सेस और स्मार्ट ईमेल मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यूजर किसी खास टापिक से जुड़े सभी ईमेल्स को एक क्लिक में रीड मार्क कर सकेंगे। गूगल पिक्स नाम का नया एआइ इमेज एडिटिंग टूल लांच किया गया है। यह आब्जेक्ट हटाने, टेक्स्ट एडिट करने और इमेज ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है।

यूट्यूब में आया आस्क यूट्यूब फीचर : यूट्यूब के लिए भी गूगल ने नया आस्क यूट्यूब फीचर लांच किया है। इससे यूजर स्मार्ट तरीके से वीडियो खोज सकेंगे। अगर वीडियो का नाम याद नहीं है, लेकिन कोई खास सीन, डायलाग या मोमेंट याद है, तो एआइ उसी आधार पर वीडियो खोज देगा। यह फीचर वीडियो और शार्ट्स दोनों में सर्च कर सकता है। फिलहाल इसे अमेरिका में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले यूट्यूब प्रीमियम यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है।

गूगल सर्च अब बनेगा एआइ असिस्टेंट : गूगल ने अपने सर्च इंजन को भी बड़े स्तर पर अपग्रेड किया है। नया एआइ सर्च बाक्स अब टेक्स्ट, आडियो और इमेज आधारित सर्च सपोर्ट करेगा। यूजर अब सिर्फ लिंक नहीं, बल्कि एआइ द्वारा तैयार जवाब और सुझाव भी देख सकेंगे। कंपनी ने एजेंटिक बुकिंग फीचर भी जोड़ा है। उदाहरण के लिए अगर कोई यूजर शुक्रवार रात के लिए छह लोगों का प्राइवेट कराओके रूम ढूंढ़ना चाहता है, तो गूगल सर्च खुद उपलब्धता, कीमत और बुकिंग लिंक दिखा देगा।

यूनिवर्सल कार्ट से आसान होगी शापिंग : गूगल ने यूनिवर्सल कामर्स प्रोटोकाल पर आधारित यूनिवर्सल कार्ट फीचर भी पेश किया है। इसकी मदद से यूजर गूगल सर्च, जेमिनी एप, यूट्यूब और जीमेल के भीतर ही शापिंग कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर अलग-अलग मर्चेंट और प्लेटफार्म के साथ काम करेगा।

एंड्रायड 17 में मिलेगा हेलो इंडिकेटर : एंड्रायड 17 अपडेट के साथ गूगल नया एंड्रायड हेलो इंडिकेटर भी लाने वाला है। यह स्क्रीन के ऊपर बाईं तरफ दिखाई देगा और बताएगा कि एआइ एजेंट इस समय कौन-सा काम कर रहा है। इससे यूजर को बैकग्राउंड एआइ एक्टिविटी की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

एंड्रायड एक्सआर स्मार्ट ग्लासेज: गूगल ने इवेंट में एंड्रायड एक्सआर आधारित स्मार्ट ग्लासेज भी दिखाए। कंपनी दो तरह के माडल पर काम कर रही है, जिसमें एक आडियो बेस्ड स्मार्ट ग्लास और दूसरा डिस्प्ले वाला माडल शामिल है। फिलहाल सैमसंग का एक्सआर हेडसेट इस प्लेटफार्म पर काम करता है, लेकिन अब गूगल इसे बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

संतोष आनंद

आज का भविष्यफल: 21 मई, 2026 गुरुवार

पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी का राशिफल।

आज का राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक।

आज का दिशाशूल: दक्षिण

कल 22 मई 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल: पश्चिम

विशेष: सप्तमी तिथि क्षय

विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी, तत्पश्चात सप्तमी अश्लेषा नक्षत्र तत्पश्चात मघा नक्षत्र वृद्धि योग, तत्पश्चात ध्रुव योग कर्क में चंद्रमा 26 घंटे 09 मिनट तक तत्पश्चात सिंह में।

मेष: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक प्रगति होगी। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।

वृष: सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।

मिथुन: आर्थिक योजना फलीभूत होगी। नेत्र या उदर विकार के प्रति सचेत रहें। कर्म में व्यवधान आएगा।

कर्क: पिता या घर के मुखिया का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी।

सिंह: धन, सम्मान में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी।

कन्या: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

तुला: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उदर विकार हो सकता है। कर्मक्षेत्र में व्यवधान आएगा।

वृश्चिक: रचनात्मक सफलता मिलेगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। देशाटन की स्थिति बनेगी।

धनु: जल की कमी से बीमार हो सकते हैं। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा।

मकर: शिक्षा प्रतियोगिता में प्रगति होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक जोखिम न उठाएं।

कुंभ: पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मीन: सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक योजना फलीभूत होगी। पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे।

वर्ग पहेली-3341

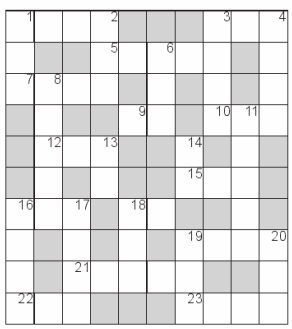

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं:
1. पूर्णतया, बिल्कुल (4)।
3. रचना का महान पुरुष (3)।
5. किसी से ईर्ष्या या जलन करना (2,3)।
7. हिस्सेदार, साझी (4)।
9. प्राण, जीवन (2)।
10. शरीर के रंध्रों से निकलने वाला जल (3)। 12. जल में रहने वाला एक जंतु, यदि (3)। 15. दरिद्रता, निर्धनता (3)। 16. समुद्र, सागर, समंदर (3)। 18. अलावा (2)।
19. मधुर या मीठी बोली (4)।
21. बहाना (5)।
22. सिंह, शेर (3)।
23. बनिया, साहूकार (4)।

ऊपर से नीचे:
1. अचानक, हठात (3)।
2. हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने का यंत्र (3)।
3. विविध प्रकार की आकृति (4)।
4. पीड़ा में मुंह से धीमी आवाज का निकलना (4)। 6. वाक्य, बात (3)।
8. पंजाब की पांच नदियों में से एक (3,2)।
11. हिम्मत करना (2,3)। 13. बिना काम की चीज (2)। 14. शताब्दी, सौ साल (2)।
16. धीमा करना (4)।
17. राजा नंद का प्रधानमंत्री, जिसने चाणक्य से मिल कर षड्यंत्र रचा था (4)।
18. जुल्म, अत्याचार (3)। 19. लेखनी (3)।
20. जलाना (3)।

कल का हल

	क		आ			वि			
	रा	ज	धा	नी		क्ष	य	रो	ग
	ह			चा	ह	त		ग	
कि	ना	रा		दि				नौ	टा
		श		खा	ना	ब	दो	श	
	ठ	न	ठ	ना	ना		ह		
नी	सा				प्र		रा	व	त
	ठ		श	ला	का			श	
म	स	ख	रा		र	म	पी	क	
			ब			न		र	

सुडोकू-3341

		2		3		6		5
							9	
9		5	4		7			
7				1		4		2
		6					1	
4				7				6
	9		5			7		
		4			3			
6	8		1			5		9

कल का हल

3	1	5	7	6	4	2	8	9
6	9	8	1	5	2	3	4	7
7	4	2	8	9	3	5	6	1
8	6	3	9	4	7	1	2	5
4	2	7	5	8	1	6	9	3
1	5	9	3	2	6	4	7	8
2	3	1	6	7	9	8	5	4
5	7	4	2	3	8	9	1	6
9	8	6	4	1	5	7	3	2

राष्ट्रीय फलक

अमरनाथ यात्रा : भोले के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू

- 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण, प्रशासनिक तैयारियां तेज
- पहलगाम और बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी

अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार भी अटूट आस्था और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सवा माह से जारी अग्रिम पंजीकरण प्रक्रिया में 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। पहलगाम और बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। पिट्ठू, खच्चर व पालकी के किराये भी तय कर दिए हैं। वहीं अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक दोनों मार्ग तैयार कर दिए जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने गश्त शुरू कर दी है। ज्ञात हो, 15 अप्रैल से पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और यस बैंक की तय शाखाओं में पंजीकरण पूरे देश में जारी है। इस वर्ष पहली बार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रीनगर के यात्री निवास पंथाचौक में साउंड एंड लाइट शो हो रहा है। यह शो पूरी यात्रा अवधि के दौरान रोजाना होगा। यात्रा मार्गों और यात्रा से संबंधित गतिविधियों के अलावा भजन और कीर्तन मुख्य आकर्षण होंगे। बालटाल मार्ग पर नौ किमी से अधिक तथा नुनवान पहलगाम मार्ग पर आठ किमी रास्ते से बर्फ हटाई जा चुकी है।

यात्री निवासों में 1000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था : सूत्रों ने बताया कि अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा और नुनवान में बने 90 करोड़ लागत वाले यात्री निवासों में प्रत्येक में 1000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। बालटाल-सोनमर्ग में लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए यात्री निवास में 800 श्रद्धालुओं के ठहरने की क्षमता है।

लंदन में चमकीं नैना, खेतों में मजदूरी कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बनाई पहचान

जासं, बहराइच

हौसलों की उड़ान अगर ऊंची हो, तो गरीबी और तंगहाली भी रास्ता नहीं रोक सकती। खेतों में मजदूरी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखने वाली नैना को महिला सशक्तीकरण और बाल विवाह रोकने की दिशा में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए लंदन में अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। घर लौटने पर जिला प्रशासन ने नैना को सम्मानित किया।

बहराइच जिले के रिसिया ब्लाक के पटेल नगर गांव निवासी नैना की जिंदगी संघर्षों भरी रही है। उनके पिता विजय बहादुर राज मिस्त्री हैं और मां सोना देवी गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद नैना ने दसवीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए मजदूरी की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। आर्थिक तंगी से पढ़ाई छूट गई, पर नैना ने हार नहीं मानी। वर्ष 2021 में वह आगा खान फाउंडेशन के प्रोजेक्ट लहर से जुड़ीं। संस्था की मदद से नैना ने इंटर किया फिर स्नातक की परीक्षा पास की।

लंदन के रायल अल्बर्ट हाल में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद संबोधित करतीं नैना। सूचना विभाग

12 युवतियों की टीम बनाकर बाल विवाह के खिलाफ छेड़ी जंग: खुद आत्मनिर्भर बनने के बाद नैना ने गांव की 12 युवतियों की टीम तैयार की और महिला सशक्तीकरण के काम शुरू कर दिए। नैना अब 16-29 वर्ष की युवतियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का अभियान चला रही हैं। नैना के संघर्ष की कहानी ने उन्हें सात समंदर पार लंदन तक पहुंचा दिया। गत 11 मई को लंदन के बंकिंघम पैलेस के अल्बर्ट हाल में आयोजित किंग्स ट्रस्ट समारोह में उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया। इस समारोह में हालीवुड अभिनेता जार्ज क्लूनी, सर राड स्टीवर्ट जैसी विश्व प्रसिद्ध हस्तियां मौजूद थीं। नैना ने इस सम्मान को उन लड़कियों को समर्पित किया है जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रही हैं।

हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश

हेमकुंड साहिब के लिए बुधवार को ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब से पंज प्यारों की अगुआई में श्रद्धालुओं को पहला जत्था रवाना हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जत्थे को रवाना किया। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेककर देश एवं प्रदेश की खुशहाली व सुरक्षित एवं सुगम यात्रा की कामना की। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खोले जाने हैं।

गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने उपराज्यपाल समेत अतिथियों को सरोपा, प्रसाद व स्मृति चिह्न भेंटकर उनका स्वागत किया। शबद-कीर्तन के बाद 'जो बोले सो निहाल' के उद्घोष के बीच अतिथियों ने पहले जत्थे को धाम के लिए रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल संधू ने कहा, हेमकुंड साहिब की यात्रा भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है, जिसमें आध्यात्मिकता, वीरता साथ-साथ चलती हैं। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, हेमकुंड साहिब सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि तप, त्याग, सेवा व साहस की दिव्य भूमि है।

यात्रियों के जत्थे को रवाना करते दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा व अन्य। जागरण

1975 में पिता के साथ हेमकुंड आए थे संधू : उपराज्यपाल ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि वर्ष 1975 में वह पिता बिशन सिंह के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए थे।

फीफा की स्थापना से बदली फुटबाल की दुनिया की तस्वीर

फीफा की स्थापना 1904 में आज ही सात यूरोपीय देशों ने मिलकर पेरिस में की थी। फुटबाल को वैश्विक स्तर पर एकजुट करने और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के संचालन के उद्देश्य से बनी फीफा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 211 है। इनमें देश और स्वायत्त क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

पहली महिला पायलट जिसने अकेले पार किया अटलांटिक महासागर

अमेलिया ईयरहार्ट ने 1932 में आज ही अटलांटिक महासागर को अकेले और बिना रुके पार कर इतिहास रच दिया था। कनाडा से उड़ान भरने के बाद वह उत्तरी आयरलैंड के लंदनडेरी के पास उतरीं और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनीं।

प्रभात रंजन ने की थी आनंद मार्ग संगठन की स्थापना

प्रभात रंजन सरकार का जन्म 1921 में आज ही वर्तमान बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर में हुआ था। वे दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु व सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। रेलवे में कार्य करते हुए उन्होंने 1955 में अध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन आनंद मार्ग की स्थापना की। 1959 में उन्होंने प्रगतिशील उपयोग तत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो सामाजिक-आर्थिक विकास का एक अनूठा माडल है। उन्होंने प्रभात संगीत के तहत 5,018 आध्यात्मिक गीतों की रचना की। उन्हें श्री आनंदमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। 21 अक्टूबर, 1990 को कोलकाता में निधन हो गया।

15 मिनट की चार्जिंग से बदलेगी ई-वाहनों की दुनिया

अध्ययन ▶ एमएमयूटी के शोधार्थी मयंक श्रीवास्तव ने विकसित की सुरक्षित सालिड-स्टेट बैटरी तकनीक

आग का खतरा लगभग खत्म, क्रिस्टलोग्राफिक इंजीनियरिंग से बढ़ी चालकता

डा. राकेश राय • जागरण

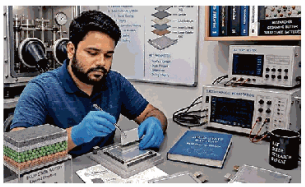

गोरखपुर : वह दिन दूर नहीं, जब इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी केवल 10 से 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी। बैटरी में आग लगने और विस्फोट जैसी घटनाओं की आशंका भी लगभग समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए एक शोध ने यह उम्मीद जगाई है। भौतिक और पदार्थ विज्ञान के शोधार्थी मयंक श्रीवास्तव ने ऐसी सालिड स्टेट बैटरी तकनीक विकसित की है, जिससे यह संभव हो सकेगा। प्रो. डीके द्विवेदी के निर्देशन में शोध को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के 'द जर्नल आफ केमिकल इंफार्मेशन एंड माडलिंग' समेत 'एल्सवियर', 'स्प्रिंगर नेचर' को मिलाकर कुल 11 प्रतिष्ठित पत्रों ने प्रकाशित किया है।

क्रिस्टलोग्राफिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग : वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग में सबसे बड़ी बाधा लंबा चार्जिंग समय, सीमित ड्राइविंग रेंज और बैटरी में आग लगने का खतरा है। पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों में ज्वलनशील लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग होता है, जिससे ओवरहीटिंग और विस्फोट का खतरा रहता है। मयंक ने 'क्रिस्टलोग्राफिक इंजीनियरिंग' तकनीक से इन समस्याओं का समाधान खोजने में सफलता प्राप्त की है। नई तकनीक में लिथियम एट्रियम ब्रोमाइड, लिथियम नाइट्राइट, लिथियम एट्रियम क्लोराइड जैसे ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया गया है। इससे बैटरी अधिक सुरक्षित, हल्की और उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बन गई है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज बढ़ाएगी।

मयंक ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती आयनों की धीमी गति, इंटरफेस अस्थिरता और चार्जिंग के दौरान कैथोड संरचना का क्षरण था। इन समस्याओं को हल करने के लिए उन्नत कम्प्यूटेशनल माडलिंग व क्रिस्टलोग्राफिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया। शोध में ठोस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थों की क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन को नियंत्रित किया गया, जिससे आयन चालकता में सुधार हुआ। उन्होंने ऐसी नई विधि विकसित की है, जिससे आयनों का प्रवाह तेज हो सके। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी की आंतरिक संरचना को नुकसान पहुंचने से बचाने की तकनीक भी तैयार की।

इजराइल के एरियल यूनिवर्सिटी की लैब में काम करते मयंक श्रीवास्तव : स्वयं

साफ्टवेयर पर आधारित शोध

शोध निर्देशक प्रो. डीके द्विवेदी ने बताया कि यह शोध साफ्टवेयर आधारित है। इसके पेटेंट के लिए आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। मयंक इसे मूर्त रूप देने के लिए इन दिनों इजरायल के एरियल विश्वविद्यालय के 'द रेडिकल रिएक्शन रिसर्च सेंटर' में शोध प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने बताया कि यह शोध भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए उम्मीद जगाने वाला है। यह तकनीक न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुरक्षित और किफायती बनाएगी, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को भी नई गति देगी।

'केक जैसी' दो परतों वाली है चंद्रमा की ऊपरी सतह

नई दिल्ली, प्रेट्र : चंद्रयान-3 के प्रयोग से चंद्रमा के छिपे रहस्य उजागर हुए हैं। इसरो ने मंगलवार को नए अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि चंद्रमा की मिट्टी (रेगोलिथ) एक समान नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट दो-परत वाली "केक जैसी" संरचना है, जिसकी ऊपरी परत केवल कुछ सेंटीमीटर मोटी है। रेगोलिथ वास्तव में 'टूटी हुई चट्टान' है। ये परतें दर्शाती हैं कि चंद्र सतह के बनने के बाद से छोटे उल्कापिंडों की बारिश से चंद्र सतह में अपरदन प्रक्रिया होती रहती है।

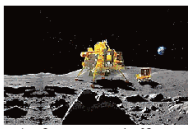

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि विज्ञानियों ने उस स्थान पर गौर किया जहां चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 2 सितंबर, 2023 को 'हाप प्रयोग' के दौरान छोटी छलांग लगाकर पहुंचा था। जब लैंडर के इंजन 'हाप परीक्षण' के लिए चालू हुए तो ऊपर की तीन सेंटीमीटर ढीली धूल हट गई। इससे नीचे की पुरानी, अधिक कठोर मिट्टी उजागर हो गई। अध्ययन में पता चला सतह पर मौजूद धूल हल्की होती है, लेकिन केवल 6.5 सेंमी की गहराई पर यह दोगुनी घनी और पांच गुना अधिक चिपचिपी हो जाती है। अंतरिक्षयात्री के लिए इसका मतलब यह है कि सतह पर चलना सूखी आटे पर चलने जैसा महसूस हो सकता है, जबकि कुछ सेंटीमीटर गहराई में, यह नम, सख्त मिट्टी की तरह व्यवहार करता है।

इसरो का किया अध्ययन। इंटरनेट मीडिया

इधर-उधर

बसों का शौक, 14 साल का लड़का बना सीरियल बस चोर

लड़के ने छह महीने में चुराई तीन सार्वजनिक बसें • इंटरनेट मीडिया

ओस्लो, एजेंसी : नार्वे में महज 14 साल का एक लड़का बसों का ऐसा दीवाना निकला कि उसने छह महीने में तीन बार सार्वजनिक बसें चुरा लीं। हैरानी की बात यह रही कि हर बार वह बस को सैकड़ों किमी तक बिना किसी हादसे के चलाता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2026 में किशोर ने ओस्लो से बस चुराई और उसे 300 किमी दूर क्रिस्टियानसैंड तक ले गया। इससे पहले अप्रैल में उसने एक अन्य बस चुराकर नार्वे की सीमा पार करते हुए स्वीडन तक पहुंचा दी थी, जहां पुलिस ने 180 किमी दूर पकड़ लिया।

एएमयू में नए प्रतिरोधी बैक्टीरियल जीनोम की पहचान

- शोधार्थियों ने 'एके 633' नामक जीवाणु के जीनोम अनुक्रमण से एनडीएम-7 जीन युक्त दुर्लभ 'मोजेक प्लास्मिड' का पता लगाया
- घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे पर चिंता बढ़ी

प्रतीकात्मक

अलीगढ़, प्रेट्र : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के शोधकर्ताओं ने अलीगढ़ शहर के नाले में बहने वाले अपशिष्ट जल में एक नए नए बहु दवा प्रतिरोधी बैक्टीरियल जीनोम की पहचान की है, जिससे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे पर चिंता बढ़ गई है। ये निष्कर्ष वैज्ञानिक पत्रिका मालिक्यूलर बायोलाजी रिपोर्ट्स के अप्रैल संस्करण में प्रकाशित हुए हैं, जो असद उल्लाह खान, शम्सी खालिद व अबसर तलत के नेतृत्व में विज्ञानियों की एक टीम द्वारा किए गए दीर्घकालिक अध्ययन पर आधारित हैं, जो एक दशक से अधिक समय से एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन (एआरजीएस) के विकास पर नजर रख रहे हैं।

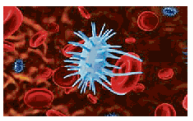

मोजेक प्लास्मिड का पता लगाया : अध्ययन के अनुसार, एक प्रमुख शहरी नाले से प्राप्त 'एके 633' नामक जीवाणु के जीनोम अनुक्रमण से एनडीएम-7 जीन युक्त एक दुर्लभ "मोजेक प्लास्मिड" की उपस्थिति का पता चला है, जो कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है। सूक्ष्मजीवविज्ञान में प्लास्मिड जीवाणुओं के भीतर पाए जाने वाले छोटे डीएनए अणु होते हैं जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक सामग्री, जिसमें दवा प्रतिरोधक गुण भी शामिल हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। 'मोजेक प्लास्मिड' आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से निर्मित प्लास्मिड को संदर्भित करता है, जो इसे विभिन्न जीवाणु स्रोतों से प्रतिरोधक गुण धारण करने में सक्षम बनाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि एनडीएम-7 जीन न्यू दिल्ली मेटालो-बेटा-लैक्टामेज (एनडीएम) प्रतिरोध जीनों के परिवार से संबंधित है, जो बैक्टीरिया को अंतिम उपाय एंटीबायोटिक्स जैसे कार्बापेनेम के प्रति भी प्रतिरोधी बना देता है, जो अक्सर तब उपयोग किए जाते हैं जब अन्य एंटीबायोटिक्स फेल हो जाते हैं। अध्ययन में उल्लेख किया गया कि एके 633 का अनुक्रमण प्लास्मिड 'पी1550' की भूमिका को उच्च जोखिम वाले एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरियल क्लोन के वैश्विक प्रसार में इंगित करता है।

बैक्टीरियल जीनोम का बढ़ता खतरा : शोधकर्ता असद उल्लाह खान ने कहा कि ये निष्कर्ष दवा प्रतिरोधी बैक्टीरियल जीनोम के बढ़ते खतरे की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी और जागरूकता कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। कहा कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध विश्व स्तर पर प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है और उन्होंने अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान, विशेष रूप से अस्पतालों के अपशिष्ट और खराब नाली प्रबंधन को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारकों के रूप में बताया। खान ने शहरी क्षेत्रों में नाली सफाई के दौरान सतर्कता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर नालियों की सफाई के बाद कीचड़ को लंबे समय तक सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है बजाय इसके कि उसे तुरंत हटा दिया जाए। ऐसे प्रथाएं प्रतिरोधी जीवों के प्रसार में योगदान कर सकती हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, जीनोटाइपिक विश्लेषण बैक्टीरियल आइसोलेट्स की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन यह समझने के लिए आवश्यक है कि कैसे प्रतिरोध जीन समुदाय और अस्पताल सेटिंग्स में बैक्टीरिया के बीच फैलते हैं।

पार्किंसंस से पीड़ित महिलाओं में पुरुषों की तुलना में गिरने का खतरा अधिक

अनुसंधान

एक अध्ययन में पाया गया है कि पार्किंसंस रोग से पीड़ित महिलाओं में पुरुषों की तुलना में गिरने का खतरा अधिक होता है। साथ ही वे दर्द, अवसाद और चिंता की अधिक शिकायत करती हैं। द लैंसेट रीजनल हेल्थ वेस्टर्न पैसिफिक जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार, पुरुषों में स्मृति में परिवर्तन की शिकायत अधिक पाई गई और उनमें बौद्धिक क्षमता में हानि की दर भी अधिक थी। आस्ट्रेलियाई पार्किंसंस जेनेटिक्स अध्ययन के आंकड़ों पर आधारित और क्यूआइएमआर बर्गहोफर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पार्किंसंस के प्रकट होने और बढ़ने के तरीके में लिंग-आधारित महत्वपूर्ण अंतर पाए गए, जो रोकथाम, निदान और देखभाल के लिए अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करते हैं। न्यूरोडीजेनरेटिव विकार से पीड़ित 11,000 लोगों ने अपनी स्थिति के अनुभव के बारे में एक प्रश्नावली का उत्तर दिया और लार के नमूने भी प्रदान किए। पार्किंसंस में कंपन, धीमी गति और मांसपेशियों में अकड़न जैसे लक्षण होते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर मिगुएल रेंटेरिया ने कहा, "ये अंतर हमें बताते हैं कि पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी नहीं है जो सभी पर एक जैसी लागू होती है।" पुरुषों और महिलाओं में दिखने वाले ये विशिष्ट पैटर्न अलग-अलग अंतर्निहित जैविक प्रक्रियाओं और पर्यावरणीय प्रभावों को दर्शा सकते हैं। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

एक्टिंग स्कूल में सारा को नहीं सीखना पड़ा अभिनय

धुरंधर फिल्म के दोनों पार्ट में सराहा गया है सारा का काम। (@saraarjunn)

कुछ लोग एक्टिंग स्कूल से अभिनय सीखकर आते हैं, तो कुछ सेट पर ही सीख जाते हैं। धुरंधर फिल्म की अभिनेत्री सारा अर्जुन भी एक्टिंग स्कूल नहीं गई हैं, उसके बावजूद उनके जीवन में कोई प्लान बी नहीं था, उन्होंने कभी एक्टिंग के अलावा सोचा ही नहीं। सारा कहती हैं कि करियर को कैसे बनाना है, इसे लेकर किसी के पास कोई ब्लू प्रिंट या योजना नहीं होती है। मैंने बतौर बाल कलाकार अभिनय करना शुरू कर दिया था। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एक सधे तरीके से सीखने का अनुभव देता है। मुझे वह अनुभव सेट पर काम करते करते मिला है। मैं भले ही किसी इंस्टीट्यूशन गई नहीं हूं, लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन के साथ रहती हूं। मेरे पिता (राज अर्जुन) ने तब थिएटर करना शुरू किया था, जब वह 16 साल के थे। देश में अलग-अलग जगहों पर उन्होंने थिएटर किया है। वह चीजें मुझमें भी आई हैं। उसके अलावा मैं वर्कशाप भी करती हूं। अहम यह है कि क्या आप उस काम को करना चाहते हैं। उससे फर्क पड़ता है। जब सारा से पूछा गया कि अगर उन्हें किसी कलाकार की अलमारी से कोई चीज चुराने का मौका मिले, तो वह कौन सा कलाकार होगा और वह क्या चुराना चाहेंगी? इस पर सारा ने कहा कि मैं रेखा जी की अलमारी से साड़ियां चुराना चाहती हूं। उनकी साड़ियां मुझे बहुत पसंद है। आजकल मुझे साड़ियां थोड़ी ज्यादा पसंद भी आ रही हैं।

डाक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा शोमैन सुभाष घई का सिनेमाई सफर

फिल्मकार सुभाष घई ने हिंदी सिनेमा में अपने करीब पांच दशक के सफर में हीरो, सौदागर, खलनायक और ताल समेत कई सुपरहिट फिल्में बनाईं। इन पांच दशकों में उन्होंने न सिर्फ फिल्म निर्माण बल्कि उसमें शामिल सिनेमेटोग्राफी से लेकर संगीत समेत कई विभागों में न सिर्फ बदलावों को देखा, बल्कि स्वयं भी कई बदलाव लेकर आएं। सुभाष घई के इन पांच दशकों के सिनेमाई सफर और उनकी फिल्मों से जुड़े किस्सों को केंद्र में रखकर निर्देशक राघव खन्ना फीचर लेंथ डाक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसका निर्माण एपिक स्टूडियोज और सुभाष घई की प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स मिलकर कर रही है। इस डाक्यूमेंट्री को डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने से पहले दुनियाभर के कई फिल्म फेस्टिवल्स में प्रदर्शित किया जाएगा। इस डाक्यूमेंट्री को लेकर राघव का कहना है, 'मैं सुभाष घई का सिनेमा देखते हुए बड़ा हुआ हूं और उन स्पष्ट यादों को एक लंबी कहानी के तौर पर डाक्यूमेंट्री में बदलना एक रोमांचक सफर है। इसकी स्क्रिप्ट सिर्फ एक बायोपिक से कहीं ज्यादा है, यह युवाओं के लिए एक टाइम मशीन की तरह है, जो उन्हें पुराने दौर में वापस ले जाती है।'

सुभाष घई निर्देशित फिल्म खलनायक की बन रही है सीक्वल। फाइल

इस तरह बना था फिल्म अमर प्रेम का 'चिंगारी कोई भड़के' गाना..

वैसे तो गाने लिखना और उन्हें रिकार्ड करना बड़े सोच विचार की और रचनात्मक प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ सुपरहिट गानों का जन्म कुछ छोटी-छोटी घटनाओं से होता है। साल 1972 में प्रदर्शित हुई राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर अभिनीत फिल्म अमर प्रेम के गाने चिंगारी कोई भड़के... की शुरुआत ऐसी ही एक घटना से हुई थी। इस गाने का किस्सा हाल ही में संगीतकार विशाल डडलानी ने इंडियन आइडल 16 में साझा किया। जब प्रतिभागी अभिषेक ने यह गाना गाया, तो विशाल ने इसके पीछे की कहानी बताते हुए कहा कि पंचम दा (आरडी बर्मन) ने सारी रात काम करके गाने का संगीत तैयार किया था। उन्होंने बख्शी (आनंद बख्शी) को गाना लिखने के लिए दिया था। वो (आनंद बख्शी) बारिश में घर जा रहे थे और धूमपान करने की आदत थी। बारिश में लाइटर जल नहीं रहा था, तो दिमाग में यह पंक्तियां आई कि चिंगारी कोई भड़के, तो सावन उसे बुझाए..। लीजेंड्स ऐसे ही होते हैं, एक साधारण सी बात को ऐसे सजा देते हैं कि वो उम्र भर का गाना बन जाए। क्या कमाल का संगीत है। पंचम दा को सलाम है और आनंद बख्शी साहब तो लीजेंड थे।'

विशाल डडलानी ने बताया गाने के पीछे का किस्सा। फाइल

तकनीक संग तालमेल बिठाएगा गुल्लक का मिश्रा परिवार

गुल्लक में शांति मिश्रा के रोल में हैं गीतांजलि। (@geetanjalikulkarniofficial)

समय के साथ हुए बदलाओं को वेब सीरीज के बनते नए सीजन की कहानियों में भी दिखना चाहिए। वेब सीरीज गुल्लक का पांचवां सीजन भी उस बदलाव को अपनाएगा। शो का मध्यमवर्गीय मिश्रा परिवार अब नई तकनीकों के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगा। इस बार शो में उनके घर में नई पुताई होगी, नया वाई-फाई कनेक्शन लगेगा, मिश्रा परिवार बदलते समय के साथ कदम मिलाने का प्रयास करेगा। वहीं बिट्टू की मम्मी की आनलाइन लोकप्रियता के कारण, मिश्रा परिवार की कर्ताधर्ता शांति मिश्रा को भी लोगों का अटेंशन मिलेगा, जिसका वो मजा उठाएंगी। गीतांजलि कुलकर्णी अपने पात्र शांति के बदले अंदाज को लेकर कहती हैं कि शांति हमेशा से मिश्रा परिवार का भावनात्मक आधार रही हैं, लेकिन इस सीजन में दर्शकों को उनका थोड़ा अलग रूप देखने को मिलेगा। ऐसा रूप जो तेजी से बदलती दुनिया के साथ अपने अनोखे अंदाज में खुद को ढालने की कोशिश करेगा। मुझे गुल्लक की सबसे खास बात यह लगती है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद ईमानदारी से दिखाती है और शायद यही वजह है कि लोग साल-दर-साल इन किरदारों में खुद को देख पाते हैं। पांच जून से गुल्लक 5 सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा।

मेहमान भूमिका करेंगे शाह रुख

फिल्म किंग में दिखेगा शाह रुख का एक्शन अवतार @iamsrk

पिछले कुछ वर्षों में हिंदी सिनेमा के बादशाह अभिनेता शाह रुख खान ने रकेट्री : द नंबी इफेक्ट, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन : शिवा और टाइगर 3 फिल्मों में मेहमान भूमिकाएं निभाकर खूब चर्चा बटोरी। अब खबरें हैं कि वह अभिनेता और कामेडियन जानी लीवर की आगामी कामेडी फिल्म आपरेशन आपरेशन में भी एक विशेष मेहमान भूमिका निभाने वाले है।

सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में शाह रुख की भूमिका दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाली होगी। उनकी भूमिका फिल्म की शुरुआत में ही दिखाई जाएगी, जिसके बाद कहानी एक अलग मोड़ लेगी। इस फिल्म में जानी लीवर केंद्रीय भूमिका में हैं, जबकि उनके साथ अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने उनकी पत्नी तथा अभिनेता मनोज पाहवा ने एक अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म को जून के मध्य में मुंबई के विभिन्न स्थानों पर शूट करने की योजना है। जब शाह रुख खान से इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया था, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इसे स्वीकार किया। वह जून में शूटिंग करेंगे। इसे लेकर जानी लीवर ने भी खुशी जताई।

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

जिम्मेदारी जरूर है पर खास रोल का दबाव नहीं : सिद्धार्थ

लार्जर दैन लाइफ वाले रोल कर लेने के बाद अक्सर कलाकार के लिए अपना अगला रोल चुनना कठिन हो जाता है। अभिनेता सिद्धार्थ गुप्ता ने फिल्म पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णावतारम् : पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्) में भगवान श्रीकृष्ण का रोल किया है। उनके इस रोल की सराहना भी हो रही है। लेकिन अब इसके बाद क्या सिद्धार्थ पर दबाव है कि वह ऐसे रोल करें, जो उतने ही पावरफुल हों? सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझ पर एक जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन कोई दबाव नहीं। मैं कलाकार हूं, कल को दूसरे रोल भी करूंगा। कलाकारों के पास वह आजादी कम ही होती है, जहां वह खुद के लिए चुनते हैं। मिले विकल्पों में ही चुनाव करना होता है। मेरी यह फिल्म सिनेमाघरों में अच्छी चल रही है, लेकिन अब कौन सा रोल मिलेगा, अंदाजा नहीं है। अभिनय मेरा जुनून है। किसी रोमांटिक या एक्शन फिल्म की जगह इस फिल्म को चुनने को लेकर आगे सिद्धार्थ कहते हैं कि यह ऐसा विषय था, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था। बाकी रोल हमें चुनते हैं, हम उन्हें नहीं। मुझसे पहले श्रीकृष्ण भगवान का रोल कई लोग कर चुके थे।

पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णावतारम् : पार्ट 1 में श्रीकृष्ण के रोल में हैं सिद्धार्थ

इन्हें रोज फोन करने लगी हैं जाह्नवी

कई बेहतरीन दोस्तियां फिल्म के सेट पर भी हुई हैं। ऐसी ही दोस्ती हुई है जाह्नवी कपूर और उनकी जल्द रिलीज होने वाली पैन इंडिया तेलुगु फिल्म पेद्दी के निर्देशक बुची बाबू सना के बीच। दो साल तक जाह्नवी ने इस फिल्म पर काम किया है, ऐसे में सेट पर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। जाह्नवी कहती हैं कि बुची सर यूं तो देखने में शर्मीले और छुईमुई से हैं, लेकिन वह सच में वैसे नहीं हैं, बेहद ही राउडी डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे इस फिल्म के दौरान काफी बदला है। वह मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। हर रोज मैं उनको एक फोन तो करती ही हूं कि सर सब कुछ कैसा जा रहा है। मुझे पता है कि मैं फालतू की बातें करती हूं। मुझे पता है कि फिल्म में मेरा रोल तो खत्म हो गया है, लेकिन एक आदत सी बन गई है। फिल्म में मेरा जो लुक है, उस पर बुची सर को भरोसा था, मैं उनके भरोसे के साथ आगे बढ़ी हूं। वह सेट पर छोटी-छोटी बातें भी बताते थे कि स्कर्ट के साथ ये करो, ऐसे बात करो, मेरे किरदार का जो अंदाज और तेवर है, वह हटके और अतरंगी है।

@janhvikapoor

भाग्यश्री को याद है मनमोहन देसाई की कही वो बात

साल 1989 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने बाद अभिनेत्री भाग्यश्री ने निर्माता हिमालय दसानी से शादी की। उसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्में प्रस्तावित हुईं, लेकिन उन्होंने परिवार और बच्चों को प्राथमिकता देते हुए इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि, फिल्मकार यश चोपड़ा और मनमोहन देसाई की कही बातें आज भी उनके जेहन में ताजा हैं। भाग्यश्री बताती हैं, 'जब मैं इंडस्ट्री छोड़ रही थी यश जी ने उस वक्त भी कहा था और जब मेरे बेटे से मिले तब भी कहा था कि ओह, तुम्हारी मां कितनी नासमझ लड़की है। शायद वो अगर इंडस्ट्री नहीं छोड़ती तो... कुछ और ही होता। हालांकि, मेरे लिए सबसे यादगार डायलाग मनमोहन जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भाग्यश्री तुम आज बोलो हां, और मैं कल तुम्हारे साथ फिल्म शुरू कर दूंगा।' भाग्यश्री ने यह भी बताया कि उन्होंने साल 1994 में प्रदर्शित फिल्म हम आपके हैं कौन का प्रस्ताव मिलने के बाद भी वह फिल्म नहीं की थी, क्योंकि उस समय वह गर्भवती थी।

इन दिनों हिंदी के साथ दक्षिण भारतीय फिल्में भी कर रही हैं भाग्यश्री @bhagyashree.online